चिंतन

किताबों को सियासी अखाड़ा नहीं बौद्धिक संवाद का माध्यम बनाएं

लोकतंत्र में किताबें विचारों का माध्यम होती हैं, लेकिन जब वही किताबें राजनीति का अखाड़ा बन जाएं, तो यह चिंता का विषय हो जाता है। हाल के दिनों में तीसरे पक्ष या पूर्व अधिकारियों द्वारा लिखी गई किताबों को लेकर संसद से लेकर सड़कों और सोशल मीडिया तक जिस तरह का शोर मचा है, उसने लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विचारों पर बहस के बजाय आरोप-प्रत्यारोप और बदनाम करने की राजनीति हावी होती दिख रही है। तीसरे पक्ष द्वारा लिखी गई किताबें किसी सरकार या संस्था का आधिकारिक दस्तावेज नहीं होतीं। वे लेखक की सोच, उसके अनुभव और उसक समय की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं। ऐसे में काल, समय और संदर्भ को समझे बिना वर्षों पुराने प्रसंगों को वर्तमान राजनीति से जोड़ना न तो सत्ता पक्ष की समझदारी है और न ही विपक्ष की जिम्मेदारी। दुर्भाग्य यह है कि दोनों ही पक्ष इन किताबों को अपने-अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। संसद में किताबों को लेकर हुए हालिया विवाद के बाद सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरों और अधूरी जानकारियों की बाढ़ सी आ गई है। बिना पूरी किताब पढ़े, बिना तथ्यों की पुष्टि किए, चुनिंदा पंक्तियों को आधार बनाकर माहौल बनाया गया। यह प्रवृत्ति न केवल जनता को भ्रमित करती है, बल्कि संसद जैसे सर्वोच्च मंच की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। जहां जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, वहां नेता एक-दूसरे की नीयत पर सवाल उठाने में उलझे नजर आते हैं। पूर्व अधिकारियों, विशेषकर सेवानिवृत्त सैन्य प्रमुखों द्वारा लिखी गई किताबें स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती हैं। हाल ही में जनरल एम. एम. नरवणे की किताब को लेकर उठा विवाद इसका स्पष्ट उदाहरण है। ऐसी किताबें सत्ता पक्ष को असहज कर सकती हैं, क्योंकि वे नीतियों, निर्णयों और दावों पर सवाल उठाती हैं, लेकिन असहज सवालों से बचने के लिए हंगामा खड़ा करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी लेखक को अपने अनुभव और विचार साझा करने का अधिकार है। जब ऐसी किताबों को लेकर सेंसरशिप की मांग उठती है या सदन में शोर-शराबा किया जाता है, तो यह संकेत देता है कि विचारों से टकराने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है। किताबों पर होने वाली राजनीति अक्सर दोहरे चरित्र को उजागर करती है। सत्ता पक्ष इन्हें गैर-जिम्मेदार या भ्रामक बताकर खारिज करने में जुट जाता है, जबकि विपक्ष इन्हीं किताबों को सरकार को घेरने का औजार बना लेता है। दोनों ही स्थितियों में सच्चाई, तथ्य और संतुलन कहीं पीछे छूट जाते हैं। कई बार इन विवादों का असली उद्देश्य जनहित नहीं, बल्कि तात्कालिक राजनीतिक या चुनावी लाभ होता है। इस राजनीतिक शोर का सबसे बड़ा नुकसान संसद को होता है। संसद का समय देश की सबसे कीमती पूंजी है। जब यह समय किताबों के बहाने हंगामे में जाया होता है, तो आमजन के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान हाशिये पर चले जाते हैं। कुल मिलाकर किताबें समाज को सोचने, समझने और सवाल करने का अवसर देती हैं। उन्हें राजनीतिक अखाड़ा बनाने के बजाय बौद्धिक संवाद का माध्यम बनाया जाना चाहिए। जब तक विचारों से डरकर शोर मचाया जाता रहेगा, तब तक संसद की गरिमा और लोकतंत्र दोनों कमजोर होते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि राजनीति विचारों से लड़ें, किताबों से नहीं।

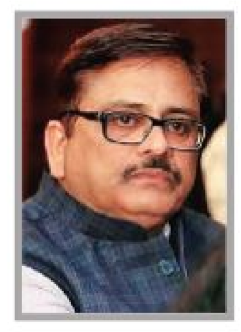

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जरूरत

साल 2026-27 के आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास और लोकव्यापीकरण के लिए कई अभूतपूर्व घोषणाएं की गई है। आयुर्वेद से जुड़े नीति नियंताओं और जानकारों के मुताबिक इन घोषणाओं के धरातली क्रियान्वयन के बाद इस पद्धति को काफी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। बजट घोषणाओं पर गौर करें तो इसमें देश में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 'एआईआईए' की स्थापना, आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं 'डीटीएल' को अत्याधुनिक करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इसी तरह देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच रीजनल मेडिकल हब तैयार किए जाएंगे। प्रस्तावित मेडिकल हब में आयुर्वेद, योग, डायग्नोस्टिक और रिकवरी सेवाएं एक साथ मिलेगी जिसका लाभ निरोगी और रोगी दोनों तरह के लोग ले सकेंगे। बजट में गुजरात के जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को भी सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बिलाशक यह बजट भारत के सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति 'आयुर्वेद' को नयी दशा और दिशा देने में पूरी तरह से सार्थक साबित होगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहचान वनौषधियों से परिपूर्ण जंगल हैं जहां औषधीय महत्व वाले लगभग 1525 तरह के वनस्पतियों की उपलब्धता के साथ ही समृद्ध जैव विविधता भी है। राज्य का 44 फीसदी हिस्सा वनों से आच्छादित है जिसमें औषधीय गुणों वाले जड़ी-बूटियों की असाधारण विविधता है। इन्हीं खूबियों के चलते छत्तीसगढ़ को स्थापना काल से ही 'हर्बल स्टेट' की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 2000 को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर तीन राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का अस्तित्व सामने आया। छत्तीसगढ़ अपने राजनीतिक स्थिरता के साथ जीरो कट बिजली आपूर्ति और खनिज संसाधनों के चलते अपने साथ निर्मित दो अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ते हुए देश के शीर्षस्थ राज्यों में शुमार हो चुका है। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ की एक पहचान 'एजुकेशन हब' के साथ ही 'मेडिकल हब' के तौर पर भी है जहां शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक सरकारी और निजी संस्थान स्थापित हैं। राज्य में मेडिकल, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, कानून के केंद्रीय संस्थान संचालित हैं।

प्रदेश में मेडिकल से संबंधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 'एम्स', भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ' एनआईटी', अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 'ट्रिपल आईटी ', भारतीय प्रबंधन संस्थान 'आईआईएम', हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 'एचएनएलयू' और गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 'एनआईईएलआईटी' और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन 'एनआईएफडी' की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने राजधानी रायपुर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 'सीआरआईवायएन' के स्थापना को भी मंजूरी दिया है। प्रदेश में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा के अकादमिक विकास के साथ ही अनुसंधान की काफी संभावनाएं हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत अब छत्तीसगढ़ राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की आवश्यकता है ताकि यह राज्य अपनी पहचान को सार्थक कर सकें।वर्तमान में राज्य में सरकारी क्षेत्र के 2 तथा निजी क्षेत्र के 6 आयुर्वेद कॉलेज संचालित हैं। राज्य स्थापना के पच्चीस सालों पर गौर करें तो प्रदेश में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है लेकिन केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान की आवश्यकता अब बलवती हुई है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजिन की सरकार है जिसके चलते राज्य को केंद्र सरकार से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है।

केंद्र सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ शीर्ष पायदान पर है लिहाजा जन अपेक्षा है कि नवीन बजट में घोषित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में से एक इस राज्य में स्थापित हो। छत्तीसगढ़ में 'एआईआईए' के स्थापना की आवश्यकता के मूल में यहां विशेष प्रजातियों के वनौषधियों की प्रचुरता के साथ ही परंपरागत वैद्यों की अच्छी खासी मौजूदगी है। यह सीधे तौर पर राज्य के लिए प्राकृतिक के साथ ही बौद्धिक संपदा भी है। राज्य के वनों में मुख्य रूप से आंवला, हर्रा, बहेड़ा, नीम, अपामार्ग, चिरायता, गिलोय, अर्जुन, अश्वगंधा, शतावरी , पुनर्नवा, भुंई आंवला, कलिहारी, बेल, अडूसा, बीजा प्रजाति के औषधि वनस्पतियां उपलब्ध हैं। वनस्पति विज्ञानियों की मानें तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और चिकित्सा के दृष्टिगत कई दुर्लभ और औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। इन वनस्पतियों में प्रमुख जनजातिय बहुल बस्तर में पाए जाने वाले ट्री-फर्न, सफेद मूसली, पसरा, बीजा, शीशम और दहीमन हैं जिनका संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। राज्य के जनजातीय समुदाय के परंपरागत वैद्यों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी मधुमेह, उच्च रक्तचाप,

गठिया और एनीमिया रोग के उपचार के नुस्खे उपलब्ध हैं जिनका वैज्ञानिक मानकीकरण करने तथा इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है। दुर्गम जंगलों में निवासरत इन जनजातीय वैद्यों को जड़ी - बूटियों की अच्छी- खासी पहचान और चिकित्सकीय महत्व के बारे में जानकारी है। छत्तीसगढ़ में यदि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होती है तो परंपरागत वैद्यों के पास उपलब्ध नुस्खों पर अनुसंधान और इसके वैज्ञानिक मानकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य के अनूकूल जलवायु और उर्वरा मिट्टी के दृष्टिगत राज्य वनौषधियों की खेती, व्यापार व निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि केरल राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत आयुर्वेदिक पर्यटन है जहां देश और विदेश के लोग इस उद्देश्य से पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आयुर्वेदिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि बस्तर से लेकर सरगुजा का क्षेत्र इसके अनुकूल हैं। राज्य में उपलब्ध वनौषधियों की प्रचुरता, निर्बाध बिजली और मानव संसाधन की उपलब्धता के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद दवा उद्योग की बेहतर संभावनाएं हैं। राज्य में राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के आवश्यक सभी प्रकार के अधोसंरचना, भूमि की उपलब्धता,परिवहन संपर्क और संसाधन मौजूद हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की प्रबल दावेदारी है। उल्लेखनीय है कि इस संस्थान से जहां आयुर्वेद के अकादमिक विकास और चिकित्सा अनुसंधान को पंख लगेगा वहीं इससे रोजगार और व्यापार के नये अवसर भी पैदा होंगे। इस संस्थान के स्थापना से छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगा वहीं आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समन्वित शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा।इसके अलावा यह संस्थान आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं तथा पैरा मेडिकल्स के कौशल उन्नयन तथा तकनीकी नवाचार के दिशा में भी काफी सहायक होगा।

गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ही भारत सहित दुनिया में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लोगों का रूझान काफी बढ़ा है। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि संपूर्ण जीवनशैली है जिसमें विभिन्न ऋतुओं में व्यक्ति को सेहतमंद रखने के लिए दिनचर्या, खान-पान और परहेज का उल्लेख है। वर्तमान परिदृश्य में जब भारत सहित दुनिया की एक बड़ी आबादी मोटापा , मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग और कैंसर जैसे जीवनशैली गत रोगों के चुनौतियों से जूझ रहा है तब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इन बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। नित नई- नई महामारियां भी जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से बचाव और रोगी के संक्रमण मुक्त होने में मुख्य भूमिका व्यक्ति के रोग-प्रतिरोधक क्षमता की होती है। आयुर्वेद पद्धति में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने तथा विकसित करने के तमाम उपाय निहित हैं। विचारणीय है कि छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में भी एक बड़ी जनसंख्या संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से ग्रस्त है जिसका नकारात्मक असर राज्य के आर्थिक विकास में पड़ना लाजिमी है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थान की आवश्यकता है ताकि "युवा छत्तीसगढ़" सेहतमंद और ऊर्जावान बना रहे। किसी भी देश और प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में स्वास्थ्य की मुख्य भूमिका होती है। बिलाशक इस उद्देश्य की पूर्ति में 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान' की भूमिका अहम हो सकती है लिहाजा राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह इस दिशा में प्रभावी पहल करेगी।

पुण्यतिथि पर विशेष

हर्षवर्धन पान्डे

लता मंगेशकर : मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे..

लता मंगेशकर की मखमली और जादुई आवाज की दुनिया दीवानी थी। उनकी आवाज़ दिल को छूती नहीं, बल्कि दिल में बस जाती थी। हर दिल अजीज लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा की गायकी में ऐसे चार चांद लगाए कि हर कोई उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह पाया। सही मायनों में हिंदी सिनेमा की गायकी की दुनिया को लता ने अपने मधुर स्वर से नई दिशा देने का काम किया। लता की वो आवाज हर किसी के दिल के तारों को आज भी झंकृत कर देती है। हिंदी सिनेमा के 100 बरस से अधिक के सफ़र में लता की गायकी सिल्वर स्क्रीन पर चार चांद लगा देती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। लता पांच भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। लता की तीन बहनें मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। पांच साल की उम्र में ही लता ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। जब वो स्कूल गयी तो वहां के बच्चों को संगीत सिखाने लगी लेकिन जब लता को अपनी बहन 'आशा' को स्कूल लाने से मना किया गया तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का भी बॉलीवुड में सफर इतना आसान नहीं था। काफी समय तक उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। इसकी दो वजहें थीं। एक तो साल 1940 के दौर में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री ली, बॉलीवुड में नूरजहां और शमशाद का दबादबा था और दूसरा लता की आवाज़ की पिच काफी हाई थी और आवाज़ पतली, ऐसे

में उस दौर के चलन में चल रहे गानों के मुताबिक आवाज भी फिट नहीं बैठती थी। प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज को 'पतली आवाज' कहकर अपनी फिल्म 'शहीद' में गाने से मना कर दिया था, फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता को फिल्म 'मजबूर' में 'दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा' गीत गाने को कहा जो काफी सराहा गया । लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि वो फ़िल्मों के लिए गाने गाये, लेकिन लता मंगेशकर बचपन से ही गायिका बनना चाहती थीं। साल 1942 में उनके पिता इस दुनिया को छोड़ गए और लता मंगेशकर के कंधों पर परिवार को संभालने की सारी ज़िम्मेदारी आ गई । इसी वज़ह से लता ने 1942 से लेकर 1948 तक करीब 8 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 1948 में म्यूज़िक कंपोज़र गुलाम हैदर ने लता को बड़ा ब्रेक दिया, जिसके बाद उनका संघर्ष का दौर खत्म हुआ और फिल्मी दुनिया में ऐसा सिक्का चला कि लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। चंद महीनों में ही लता के प्रति लोगों का नजरिया बदला और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और फिर इसके बाद उन्हें मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ा। लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम किया। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। साल 1977 में आई फिल्म 'किनारा' में लता मंगेशकर ने 'नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा, मेरी आवाज़ ही, पहचान है, गर याद रहे' गीत गाया। लता मंगेशकर की ये लाइनें उनके हर चाहने वाले को हमेशा याद रहेंगी। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए। फिल्म 'मधुमति' के गाने 'आजा रे परदेसी' के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला। लता मंगेशकर को साल 2001 में 'भारत रत्न' से भी नवाजा गया था। लता दीदी को इसके पहले पद्म भूषण (1969), पद्म विभूषण(1999) और दादा साहब फाल्के अवार्ड (1989) पुरस्कार से भी नवाजा गया । सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने ताउम्र शादी नहीं की। इसकी वजह बताते हुए वो कहती थी कि पिता की मौत के बाद घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उन पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। मध्यप्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार के लिए चयनित कलाकारों को दो-दो लाख की राशि, सम्मान पट्टिका, शाल-श्रीफल से अलंकृत किया जाता है। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता का निधन हो गया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज का जादू लम्बे समय तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रंग भरता रहेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कथनी और करनी में न हो कोई अंतर

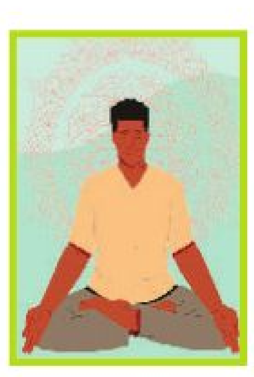

संकलित
दर्शन

सभी के हित का ध्यान रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वाह करना कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य का पालन यदि समुचित रूप से किया जाता है तो जीवन पूर्णतः गौरवान्वित बनता है। जो कर्त्तव्यनिष्ठ है। वह अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। वह परमार्थ पोषक एवं प्रामाणिक होता है। वह जैसा रहता है, वैसा ही करता भी है। ऐसी कथनी-करनी की एकरूपता से वह समाज में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है और प्रत्येक उससे प्रेरणाएँ ग्रहण करता है। कर्त्तव्य परिपालन की बात करना और कर्त्तव्य परिपालन के नाम पर शोर-शराबा मचाना अलग बात है और कर्त्तव्यों के क्षेत्र में बिना किसी शोर-शराबे के समर्पित हो जाना अलग बात है। आज हम देखते हैं कि कर्त्तव्यों के परिपालन के लिए अक्सर लम्बे-चौड़े उपदेश दिये जाते हैं, पर जब कर्तव्य निर्वाह का अवसर आता है तो व्यक्ति दायें-बायें देखने लगता है। कटु सत्य तो यह है कि आज कर्त्तव्यों की चर्चा करने वाले लाखों हैं, पर कर्त्तव्यों के पावन पथ पर गतिशील होने वाले विरले ही हैं। कई बार मुझे चिंतन के क्षणों में लगता है कि आज व्यक्ति कर्त्तव्यों से विमुख हो गया है। इस विमुखता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता और अशांति का विस्तार हुआ है। कर्त्तव्यों के पावन क्षेत्र से भटककर कोई व्यक्ति कभी भी शांति का अहसास नहीं कर सकता। जीवन का गौरव और उसकी सार्थकता कर्त्तव्य पालन में ही है। कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति गुलाब का फूल है, वह काँटों में मुस्कराता है।

मुश्किल समय में मन अस्थिर हो जाता है

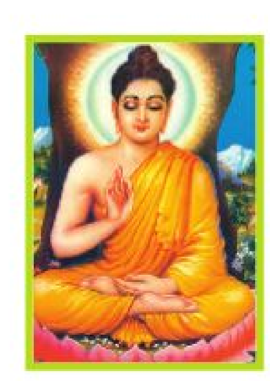

संकलित
प्रेरणा

गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे। यात्रा में उनके शिष्य भी साथ रहते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते-चलते काफी समय हो गया था। काफी चलने की वजह से वे थक गए थे। आराम के लिए वे एक जगह रुके। बुद्ध ने शिष्य आनंद से कहा कि प्यास लगी है, पास में से ही एक झरने के बहने की आवाज आ रही है, वहां जाकर पीने का पानी ले आओ। बुद्ध की आज्ञा मिलने के बाद आनंद झरने के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर आनंद ने देखा कि एक बैलगाड़ी पानी में से गुजरी है तो पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है। पानी में मिट्टी दिख रही थी, पानी पीने लायक नहीं था। आनंद गंदा पानी देखकर लौट आया। आनंद ने लौटकर बुद्ध से कहा कि तथागत, वहां का पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अब तुम कुछ देर बाद फिर से जाना। इस बार तुम्हें अच्छा पानी मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर आनंद कुछ देर बाद फिर से पानी लेने पहुंच गया। इस बार पानी शांत था, पानी में कोई हलचल नहीं थी। पानी एकदम साफ दिख रहा था। आनंद ने तुरंत ही पीने के लिए पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पीकर आनंद से कहा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मन तनाव की वजह से अशांत हो जाता है। अशांति गंदे पानी की तरह है। जब तक मन अशांत रहता है, तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।

उत्तरायणी कौथिक उत्सव

देहरादून में गुरुवार को उत्तरायणी कौथिक उत्सव के दौरान कलाकार प्रस्तुति देते हुए।

आज की पाती

पाक का संशोधन लोकतंत्र के लिए काला अध्याय

संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, जो समय के साथ बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए ढांचे को लचीला बनाते हैं। लेकिन जब ये संशोधन सत्ता के संतुलन को बिगाड़ने का हथियार बन जाते हैं, तो वे लोकतंत्र को ही खोखला करने लगते हैं। पाकिस्तान की संसद द्वारा नवंबर 2025 में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन ठीक ऐसा ही एक उदाहरण है। यह संशोधन सतह पर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में कार्यपालिका और सेना के हाथों में न्यायपालिका को बंधक बनाने का प्रयास है। इसने न केवल पाकिस्तानी संस्थानों के बीच शक्ति संतुलन को उलट दिया है, बल्कि विधि के शासन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। - मनीष शर्मा, राजनांदगांव

ट्रेंड

'भारत टैक्सी' से मुनाफा

सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी-छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, 'भारत टैक्सी' इसका उदाहरण है। चालक बहन-भाई 'भारत टैक्सी' से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे।
- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

देश का सामरिक विकास

प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले विपक्षी दल संसद में प्रजातंत्र का गला घोंटते हैं, ये सारा देश देख रहा है। विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सामरिक विकास रास नहीं आ रहा है।
-जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

टैरिफ का आकलन

भारत पर अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने की खबर कितनी देश व जनहित में है, इस बारे में समुचित जानकारी के अभाव में तत्काल कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पर जमीनी अमल होने के बाद ही पता चलेगा कि इससे आमजन का क्या भला होगा।
- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

विरोध करने का निर्णय

मोदी सरकार ने ठान लिया है कि दोनों विपक्षी नेताओं को बात करने नहीं देना है। सारी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने यह तय किया कि अगर वे हमें बात करने नहीं देंगे, तो हमें वाक आउट करना चाहिए और विरोध करना चाहिए।
-मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

अमेरिकी महाद्वीप में खसरे को लेकर चेतावनी जारी

'पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन' (पीएएचओ) ने अमेरिकी महाद्वीप में खसरे के मामलों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर एक नई महामारी संबंधी चेतावनी जारी की है। मेक्सिको में खसरे के काफी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पीएएचओ की ओर से जारी चेतावनी में तत्काल टीकाकरण अभियान चलाने का भी आह्वान किया गया है साथ ही कहा गया है कि हाल में सामने आए मामले में 78 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। बुधवार को यह चेतावनी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब नवंबर में कनाडा का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया है। यह एक ऐसा झटका है जिसकी पुनरावृत्ति जल्द ही अमेरिका और मेक्सिको में भी हो सकती है। इस वर्ष के पहले तीन हफ्तों में पीएएचओ ने सात देशों में खसरे के 1,031 नए मामलों की पुष्टि की है - जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में चौंका देने वाली 43 गुना वृद्धि है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन संक्रमण का प्रसार अब भी अधिक है। मेक्सिको में सबसे अधिक 740 मामले हैं, उसके बाद अमेरिका में 171 और कनाडा में 67 मामले हैं। अमेरिका में अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी ध्यान दक्षिण कैरोलिना की ओर केंद्रित किया गया है, जहां खसरे के मामलों में वृद्धि हो रही है।

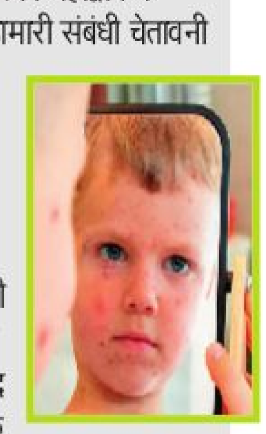

ऑफ बीट

उम्र बढ़ना एक जटिल प्रक्रिया सबमे इसका असर अलग

आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे, जो अपनी वास्तविक उम्र से छोटा दिखाई देता होगा। इसी तरह आप ऐसे लोगों के भी संपर्क में आए होंगे, जो अपनी उम्र से काफी बड़े नजर आते हैं। क्या कारण है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हर व्यक्ति में समान नहीं होती? मैंने अपने पूरे करियर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया (एजिंग) पर अध्ययन किया है। मैं मिशिगन विश्वविद्यालय में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से संबंधित कोशिकीय एवं आणविक विज्ञान का प्रोफेसर हूं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े अनुसंधान में ऐसा समाधान नहीं तलाशा जाता, जो ढलती उम्र में आपको होने वाली हर बीमारी से निजात दिला सके। बल्कि, पिछले एक या दो दशक में हुए शोध इस ओर इशारा करते हैं कि 'एजिंग' एक बहुकारकीय प्रक्रिया है और इसे महज एक उपाय से नहीं रोका जा सकता। 'एजिंग' क्या है? -एजिंग की अलग-अलग परिभाषाएं हैं, लेकन वैज्ञानिक आमतौर पर कुछ समान कारकों पर सहमत होते हैं : उम्र बढ़ने की प्रक्रिया समय पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति को बीमारियों, चोट और मौत के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से
aapkepatra.haribhoomi@gmail.com
पर भेज सकते हैं।

शाह ने लॉन्च किया 'भारत टैक्सी'

अब जीरो कमीशन, नो सर्ज प्राइसिंग, ड्राइवर बनेंगे मालिक

सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और देश में समावेशी परिवहन सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

देश के कैब सर्विस सेक्टर में गुरुवार को एक नया चैप्टर जुड़ गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत का पहला सहकारी मॉडल आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च कर दिया। यह सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी व नागरिक-केंद्रित परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल मोबिलिटी सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है।

भारत के कैब सेक्टर में नया अध्याय जुड़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में 'भारत टैक्सी' के शुभारंभ के दौरान यह जानकारी दी।

चालक भाई-बहन मुनाफा कमाएंगे और विशेष सपोर्ट

शाह ने कहा कि सहकारिता से बहुत लोग छोटी-छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, 'भारत टैक्सी' इसका उदाहरण है। आज का दिन टैक्सी चालक बहनों-भाइयों के लिए बहुत ही अहम है। उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ।

भारत टैक्सी एप के प्रमुख फीचर्स

- इस ऐप में ग्राहकों को किसी तरह की सर्ज प्राइसिंग नहीं देनी होगी। पीक आवर्स में भी किराया फिक्स रहेगा।
- राइड ऑप्शन के तौरपर कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी और इंटरसिटी ट्रैवल सपोर्ट मिलेगा।
- कम किराया और पूरी पारदर्शिता के साथ ड्राइवर्स की पुलिस वेरिफिकेशन होगी। लाइव ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट के साथ राइड शेयरिंग और अलग-अलग भाषओं में 24/7 सपोर्ट।

प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता नहीं होगी

'भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव आधारित डिजिटल टैक्सी एप है। इसका मकसद कमर्शियल वाहन चालकों को ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना है। भारत टैक्सी के ड्राइवरों को 'सारथी' कहा जाएगा। दिल्ली में टेस्टिंग पूरी हो गई है जबकि गुजरात के राजकोट में अभी ट्रायल चल रहा है। पेमेंट और पारिश्रमिक प्रणाली में ड्राइवरों को बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकेगा।

टैक्सी खरीदने के लिए ड्राइवरों को मिलेगा लोन

भविष्य में वह ड्राइवरों को अपनी खुद की टैक्सी खरीदने के लिए सरकारी लोन उपलब्ध कराएगी। सेवा का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भारत टैक्सी ने दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस के साथ साझेदारी की है। इस ऐप में रीयल-टाइम ट्रैकिंग, सत्यापित ड्राइवर, बहुभाषी सुविधा और सारे दिन 24 घंटे कस्टमर केयर जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, इसे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है।

एप के फायदे

1. अलग-अलग तरह की ट्रैवल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत टैक्सी सर्विस -हर तरह की कैब सर्विसेज ऑफर करती है। यह कैब सर्विस व्यक्तिगत, परिवारों और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए पर्फेक्ट है।
2. भारत टैक्सी सर्विस के सबसे अहम फीचर्स में से एक है- ड्राइवर्स के लिए ज़ीरो कमीशन। ड्राइवर अपनी पूरी कमाई अपने पास रखते हैं और प्लेटफ़ॉर्म को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। इससे उनकी इनकम बढ़ती है, आर्थिक दबाव कम होता है। वे यात्रियों को बेहतर व भरोसेमंद सर्विसेज देने के लिए प्रेरित होते हैं।
3. भारत टैक्सी सर्विस इंस्टेंट बुकिंग सपोर्ट करता है। यूजर्स प्लेटफॉर्म के जरिए फटाफट कैब बुक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी सिंपल और समय बचाने वाली है और इससे इमरजेंसी या लास्ट-मिनट ट्रैवल प्लान के दौरान यात्रियों को सुविधा होती है।

खबर संक्षेप

अलंकार ने राजनीति में उतरने का दिया संकेत

बरेली। यहां के सिटी मजिस्ट्रेट रहे निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि लोकतंत्र विफल होता दिख रहा है। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वेअपने लोगों से लड़ने नहीं आए हैं। अग्निहोत्री ने भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा।

ठाकुर पर लगा आजीवन प्रतिबंध कोर्ट ने हटाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग सिंह ठाकुर पर बीसीसीआई के मामलों में हिस्सा लेने पर लगा बैन

हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन पर जिंदगी भर का प्रतिबंध लगाना न तो सही था और न ही इसका कोई इरादा था। सीजेआई की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि यह आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने का सही मामला है। जिंदगी भर बैन की जरूरत थी।

साणंद में छापा, 81 रसूखदार हिरासत में

साणंद। गुजरात के साणंद जिले में पुलिस ने अहमदाबाद के पास एक प्राइवेट वीकेंड होम पर छापा मारा

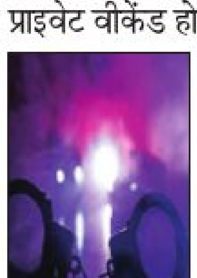

और शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए शराब और हुक्का पार्टी करने के आरोप में 81 लोगों को हिरासत में लिया है। बुधवार रात को गोरस सीम इलाके के पास निर्वाण ग्रीन्स वीकेंड होम में यह छापा मारा गया। यह पार्टी 'एवी' नाम के व्यक्ति ने की थी।

9 से बेंगलुरु मेट्रो का किराया बढ़ेगा

बेंगलुरु। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर किराए में पांच प्रतिशत की

बढ़ोतरी की घोषणा की। नई दरें 9 फरवरी से लागू होंगी। जनसंपर्क अधिकारी बीएल यशवंत चौहान ने बताया कि हर साल एक फॉर्मूले के तहत प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। इसमें अधिकतम 5 प्रतिशत और न्यूनतम 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।

पीएम 13 को भाजपा पार्षदों को देंगे पार्टी

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर

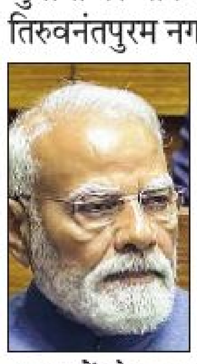

ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएगी। तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा को जीत मिली है, जिसने 4दशकों से ज्यादा तक चले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के निर्बाध शासन को भी खत्म किया है। प्रधानमंत्री 13 फरवरी को अपने आवास पर पार्षदों के लिए डिनर रखा है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे का बार-बार हस्तक्षेप

सरकार पर तीखे सवाल, कार्यवाही में कई बार व्यवधान, फिर विपक्ष का बहिर्गमन

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

राज्यसभा में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए और कई बार हस्तक्षेप करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उनके लगातार बोलने और बीच-बीच में टोका-टोकी के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। राज्यसभा कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि संसद राज्यसभा और लोकसभा दोनों खंभों पर खड़ा सर्वोच्च सदन है। दोनों की कार्यवाही में कुछ मर्यादाओं का हनन हो रहा हो तो संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए दूसरे सदन में विषय उठाने से रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि आसंदी से व्यवस्था का मामला बताते हुए उन्हें लोकसभा का मामला राज्यसभा में उठाने की अनुमति सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नहीं दी।

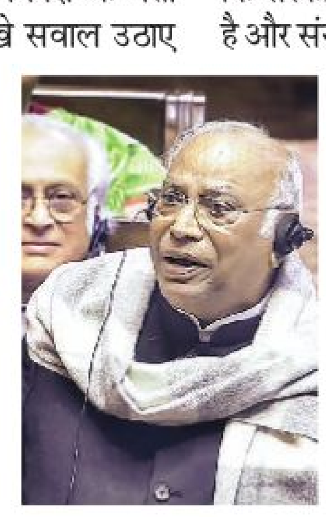

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब की शुरुआत से ही खरगे ने सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जमीनी सच्चाइयों की झलक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की आय और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। खरगे ने कहा कि देश में युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार सिर्फ उपलब्धियों का प्रचार कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी खरगे ने कई बार बीच में बोलते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और संसद को केवल एकतरफा मंच बना दिया गया है।

खरगे ने सवाल उठाया कि यदि सब कुछ ठीक है, तो किसान आंदोलन, मणिपुर की स्थिति और दलित-आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार क्यों सामने आ रहे हैं?

खरगे ने विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापार समझौतों की बातें की जा रही हैं, लेकिन आम आदमी की थाली लगातार महंगी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और इसे बार-बार बाधित किया जा रहा है।

खरगे के लगातार हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बनी। सभापति ने कई बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और सभी सदस्यों से मर्यादा में बोलने को कहा। इसके बावजूद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक जारी रही।

अंततः स्थिति तनावपूर्ण होने पर कुछ देर के लिए कार्यवाही प्रभावित हुई और विपक्ष के कई सांसदों ने विरोध दर्ज कराते हुए अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाज़ी की। दिनभर की कार्यवाही के दौरान खरगे का रुख आक्रामक बना रहा और उन्होंने बार-बार सरकार से सीधे जवाब देने की मांग की। पीएम मोदी के जवाब के समय आखिरकार तमाम आपत्तियां दर्ज करते हुए विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया।

संसद में बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा,

प्रधानमंत्री मोदी को मैंने ही लोकसभा आने से किया था मना, अप्रत्याशित घटनाक्रम था

संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के विरोध और नारेबाजी

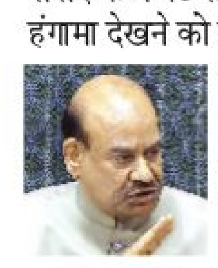

के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालात बिगड़ते देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गंभीर और अहम बयान दिया है। बिरला ने कहा कि जिस तरह का माहौल उस दिन लोकसभा में बना, उसमें कोई भी अप्रिय और अप्रत्याशित घटना घट सकती थी।

राहुल का नाम लिए बिना खरगे से बोले नड्डा

पार्टी को 'अबोध बालक' का बंधक न बनने दें

संसद के बजट सत्र में सियासी हंगामा जारी है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे

के बीच लोकतंत्र और अहंकार जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और उन्हें 'अबोध बालक' कह दिया। नड्डा और खरगे के बीच हुई इस तकरार के बीच सभापति ने भी टिप्पणी की। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार हर समय और सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने लोकसभा को चलने नहीं दिया। राज्यसभा में भी जबरन हंगामा किया जा रहा है।

भारत की मालदीव संग कृषि क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा

नेपाल को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने का भारत ने दिया आश्वासनःचौहान

कृषि अनुसंधान, लाइवस्टॉक एवं एग्रो-क्लाइमेटिक परिस्थितियों पर सहयोग को लेकर सहमति

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने आवास पर नेपाल के कृषि एवं पशुधन मंत्री डॉ. मदन प्रसाद परियार एवं मालदीव के कृषि एवं पशु कल्याण राज्य मंत्री अहमद हसन दीदी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भारत, नेपाल और मालदीव के बीच कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। चौहान ने बताया कि बैठक में कृषि अनुसंधान, उन्नत बीज, लाइवस्टॉक, मृदा स्वास्थ्य तथा एग्रो-क्लाइमेटिक परिस्थितियों के अनुरूप कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली में कृषि के क्षेत्र में हो रहे उन्नत अनुसंधान कार्यों का लाभ नेपाल एवं मालदीव के कृषि क्षेत्र की उन्नति में भी दिया जाएगा। नेपाल को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने का आश्वासन भारत सरकार द्वारा दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन मौजूद है, जिस पर दोनों देश कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा (इ–प्रोक्यूमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य के लिए वरिष्ठ मंडल अभियंता–II, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल मे ई–निविदा आमंत्रण।

NIT - 69	**कार्य का नामः** वरिष्ठ मंडल अभियंता–II के अंतर्गत सहायक मंडल अभियंता मेरठ के तहत मेरठ सिटी स्टेशन पर लाइन न. 1A, 1, 4 व 5 पर बेलास्टलेस ट्रेक (BLT) का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत (रुपये) :– 112309980.61** **बयाना राशि (रुपये): 711600.00**
निविदा खोलने की तिथि और समय	03.03.2026 15:00 Hrs.
वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्तावेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	निविदा **www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध।

ठेकेदारो को ई–टेंडर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) **IREPS** साइट **www.ireps.gov.in** के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें। मैनुअल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेगी। निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य होगी।

सं 128-W/280/e Tender Notice/NIT-69-25-26-W-II दिनांक : 04.02.2026 400/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

ई–निविदाएं आमंत्रण सूचना

दिल्ली ट्रांसको लि. (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का उपक्रम) निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है :

निविदा सं. टी25पी131631 : नये और पुराने किलोकारी, डीटीएल स्टाफ कॉलोनी के क्वार्टरों में फ्लोरिंग टाइल्स की स्थापना और बाथरूम्स का पुनरोद्धार।

निविदा के सम्पूर्ण विवरण हेतु कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स पर पधारें :

https://govtprocurement.delhi.gov.in (निविदा आईडी नं. 2026_DTL_286033_1) और www.dtl.gov.in सहित यूनिक नं. DTL-9868-030226.

बोली जमा हेतु अन्तिम तिथि : 09.03.2026 को 13:00 बजे

इस ई-निविदा के सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन/विस्तार की तिथि/स्पष्टीकरणों इत्यादि को केवल उपरोक्त वेबसाइट पर डाला जाएगा। बोलीदाताओं को स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर पधारना चाहिए।

अभिभाषण पर पीएम का स्पष्टीकरण जरूरी सदन में नहीं आ सकते तो सूचना जरूरीः वेणुगोपाल

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

लोकसभा की कार्यवाही को लेकर एक बड़ा संसदीय विवाद सामने आया है। लोकसभा सांसद एवं लोक लेखा समिति (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के समापन में गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

गुरुवार शाम को लिखे गए पत्र में के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में जिन संसदीय नियमों का पालन अनिवार्य है, उनका उल्लंघन किया गया। उन्होंने नियम 20 का हवाला देते हुए कहा कि इस नियम के तहत बहस के अंत में प्रधानमंत्री द्वारा सरकार का पक्ष स्पष्ट करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री ऐसा करने में असमर्थ हों, तो इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिए।

वेणुगोपाल ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि न तो प्रधानमंत्री ने बहस का उत्तर दिया और न ही सदन को उनकी अनुपस्थिति या असमर्थता की कोई जानकारी दी गई, जो नियम 20 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि संसदीय परंपरा के अनुसार किसी भी बहस का समापन संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ होता है। यदि असाधारण परिस्थितियों में बिना उत्तर के बहस समाप्त करनी हो, तो इसके लिए नियम 362 के तहत प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक होता है, जिसे अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाए और सदन की स्वीकृति के बाद ही बहस को समाप्त माना जा सकता है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि इस मामले में नियम 362 के तहत कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया, इसके बावजूद लगभग दोपहर 12 बजे धन्यवाद प्रस्ताव को अचानक मतदान के लिए रख दिया गया, जिससे बहस को बिना निर्धारित प्रक्रिया के समाप्त कर दिया गया। वेणुगोपाल ने इसे नियम 362 का भी उल्लंघन बताया है।

के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को 'सदन के नियमों का संरक्षक' बताते हुए कहा कि संसद का संचालन संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अध्यक्ष का यह दायित्व है कि सदस्यों को इस अधिकार का पूर्ण संरक्षण मिले।

उन्होंने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के उत्तर को छोड़े जाने और अचानक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रक्रिया को लेकर सदन अंधेरे में है। इससे संसदीय मर्यादाओं और स्थापित परंपराओं से विचलन हुआ है, जिसने सांसदों को आहत और भ्रमित किया है।

केसीवेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे सदन को स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री के उत्तर और बहस के समापन के संदर्भ में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित नियमों और अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण सदन के हित में होगा।

इस पत्र के सामने आने के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है।

कांग्रेस राज में होती थी 'लिंचिंग': सीतारमण

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

संसद के बजट सत्र में गुरुवार को एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर तीखा हमला बोला। खरगे ने लिंचिंग जैसे गंभीर शब्द का इस्तेमाल कर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वित्त मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की। सीतारमण ने कांग्रेस को उनके अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए उन विवादित घटनाओं का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने तथ्यों के साथ कांग्रेस के दावों की धज्जियां उड़ा दीं। विपक्ष के नेता ने जिस 'लिंचिंग' शब्द का सहारा लिया है, वह पूरी तरह गलत है।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **सुभाष पुत्रः** राज कुमार **पताः** मकान नंबर A–4/153 नंद नगरी दिल्ली, ने **FIR No. 1056/2016 U/s 12/9/55 G Act थानाः नंद नगरी दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सुभाष** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सुभाष** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 1056/2016 U/s 12/9/55 G Act थानाः नंद नगरी दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **सुभाष** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **18.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री दीपाक्षी राणा
जेएमएफसी–03, कमरा नंबर 19
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/1583/NE/2026
(Court Matter)

पश्चिम बंगाल विधानसभा में अंतरिम बजट पेश, यहां 'रेवड़ी' बांटी

महिलाओं को 500 रु. तो बेरोजगारों को हर माह मिलेंगे 1500

वित्त मंत्री चंद्रिमा ने 04.06 लाख करोड़ का बजट किया पेश

एजेंसी ⏭ कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 04.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। बंगाल सरकार ने अपनी सबसे बड़ी योजना 'लक्ष्मी भंडार' का ऐलान किया। इस योजना के तहत राज्य की 2.42 करोड़ महिलाओं को मासिक सहायता राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई राशि फरवरी से ही लागू हो जाएगी। राजनीतिज्ञ इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।

'लक्ष्मी भंडार' का किया ऐलान

आशा और आंगनबाड़ी कार्यकार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ायाः ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के अलावा, प्रस्तावित बजट में गिग वर्कर्स को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे कि स्वास्थ्यसाथी) में शामिल करने को कहा है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बजट में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में भी 1000 की बढ़ोतरी की जाएगी। बेरोजगारों को 5 साल तक 1500 मासिक भत्ता मिलेगा।

ममता बोलीं- हमने अपना वादा निभाया

सीएम ममता बेनर्जी ने कहा कि हम 100 दिन रोजगार योजना, आवास योजना जैसी कई योजनाओं में देश में नंबर एक पर हैं। केंद्र ने इन योजनाओं के लिए फंड देना बंद कर दिया। हम यह बजट जनता के लिए पेश कर रहे हैं, न कि चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे। हमने अपना वादा निभाया है। हमने इस फरवरी से लक्ष्मी भंडार में 500 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है।

वोटिंग से पहले 10-10 हजार, सुनवाई आज

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा पर प्रशांत किशोर की जन सुराज

पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने चुनावी लाभ की कोशिश की। लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। शीर्ष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सुनीता ठाकुर पत्नी श्री अशोक ठाकुर पता प्लॉट नंबर 1, उदासीन आश्रम आराम बाग, पहाड़गंज, दिल्ली–110055 दुसरा दैया नं.60, मकान नं.5, आराम बाग पहाड़गंज, दिल्ली–110055 ने सीसी सं. 542575/16 धारा 138 एनआई एक्ट के तहत** थानाः राजिन्द्र नगर, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **सुनीता ठाकुर** मिल नहीं रही है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **सुनीता ठाकुर** फरार हो गयी है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **सीसी सं. 542575/16 धारा 138 एनआई एक्ट के तहत** थानाः राजिन्द्र नगर, दिल्ली **के उक्त सुनीता ठाकुर** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **12.03.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
अरविंद तोमर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–07
एनआई एक्ट कोर्ट नं.507, एक्सटेंशन ब्लॉक
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/17443/CD/2025

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 : फाल्गुन कृष्ण – 5 वि. 2082

आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है

संसदीय मर्यादा की अनदेखी

यह अच्छा नहीं हुआ कि विपक्ष के हंगामे के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में दूसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब नहीं दे सके और उसे उनके संबोधन के बिना ही पारित करना पड़ा। ऐसा कम ही होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बात न कह सकें और वह भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। यह एक परंपरा रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब आमतौर पर प्रधानमंत्री ही देते हैं। इसकी अपेक्षा भी की जाती है और प्रतीक्षा भी। दशकों बाद यह परंपरा टूटी। जब भी संसद की स्थापित परंपराएं टूटती हैं, तब संसद की गरिमा गिरने के साथ राजनीतिक कटुता तो बढ़ती ही है, लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था भी डिगती है। लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह यह कहा कि उन्होंने अनहोनी की आशंका के चलते प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका था, क्योंकि विपक्षी सांसदों के व्यवहार के कारण कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, वह बहुत ही गंभीर है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि विपक्ष के आक्रामक रवैये के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल ही न सकें? इसकी भी अनदेखी न की जाए कि राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री की ओर से जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया जा रहा था तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और अंततः सदन से बाहर निकल गए। आखिर इससे क्या हासिल हुआ?

संसद के बजट सत्र के शुरुआती चरण में संसद के दोनों सदनों और उसके परिसर में जैसे दृश्य देखने को मिले हैं, वे संसदीय मर्यादाओं का उपहास उड़ाने वाले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश के जरिये चीन के मामले में प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाने और उन्हें कमजोर शासक साबित करने की चेष्टा की। पता नहीं क्यों वे यह भूल गए कि इसके जवाब में उन्हें प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से अप्रिय बातें सुनने को मिल सकती हैं और उनके साथ-साथ उनके दल को भी असहज होना पड़ सकता है। बीते दिनों संसद परिसर में भी ऐसा कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से सामना होते ही राहुल गांधी ने उन्हें न केवल गद्दार दोस्त कहा, बल्कि यह कटाक्ष भी किया कि उन्हें कांग्रेस की ही शरण में आना होगा। क्या राहुल कांग्रेस से दूसरे दलों में गए सभी नेताओं को भी इसी नजर से देखते हैं? प्रश्न यह भी है कि दूसरे दलों से जो नेता कांग्रेस में आए हैं, उनके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है? अच्छा हो कि पक्ष-विपक्ष यह समझें कि संसद हंगामे के लिए नहीं है।

भूजल के लिए सर्वे

राजधानी में भूजल की उपलब्धता, गुणवत्ता और दोहन को लेकर सर्वे कराने की दिल्ली सरकार की योजना सर्वथा उचित है। दिल्ली में पेयजल की कमी वर्षभर बनी रहती है और पानी का कोई अतिरिक्त स्रोत न होने के कारण भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार राजधानी में सभी वैध व अवैध बोरवेल का सर्वे कराने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वह आगे नीति तय करेगी। सर्वे का यह कार्य केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा गया है। यह सर्वे 20 माह में पूरा होगा। इस बीच, दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने नई बोरवेल नीति बनाने का कार्य शुरू किया है, ताकि अवैध भूजल दोहन को रोककर भूजल स्तर गिरने से रोका जाए और भूजल का वैध रूप से दोहन कर उसे पेयजल के रूप में उचित ढंग से इस्तेमाल किया जा सके।

> अवैध बोरवेल चिह्नित करने के साथ उन्हें सील किया जाना चाहिए और आरोपितों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो

राजधानी में अवैध रूप से भूजल दोहन चिंता की बात है। पानी माफिया मालामाल हो रहे हैं और भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। दिल्ली सरकार को इसके लिए दोतरफा काम करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर दिल्ली में अवैध बोरवेल चिह्नित करने के साथ ही उन्हें सील किया जाना चाहिए और आरोपितों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में भी ठोस काम किया जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या खतरनाक टास्क बेस्ड मोबाइल गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?

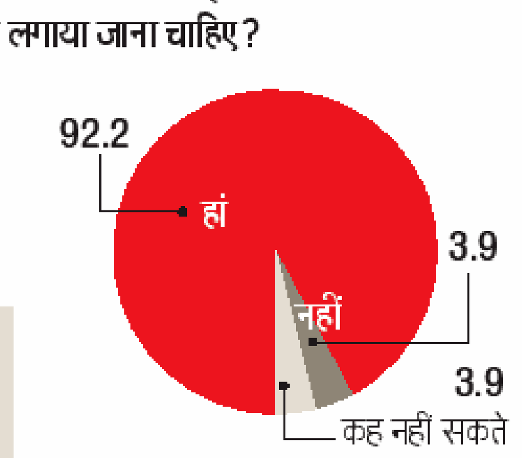

आज का सवाल

क्या भारत टैक्सी पहले से स्थापित टैक्सी सेवाओं को चुनौती देने में सक्षम होगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम

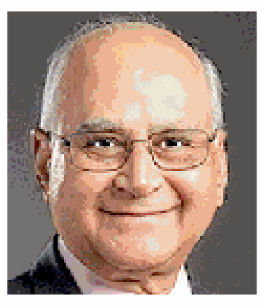

जीएन वाजपेयी

फिसलन भरे वैश्विक परिदृश्य में ऐसे बजट की आवश्यकता थी कि भारत के कदम फिसलें नहीं और वह सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली आर्थिकी बना रहे

केंद्रीय बजट भारत सरकार की सबसे व्यापक वार्षिक आर्थिक गतिविधियों में से एक है। यह कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। कराधान और व्यय नीति को निर्धारित करता है। कल्याणकारी एवं विकास संबंधी योजनाओं पर खर्च का खाका तैयार करता है। इसकी नीतियां जीडीपी वृद्धि, निवेश और रोजगार से लेकर महंगाई के रुझान को भी प्रभावित करती हैं। गत रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया, वह भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैसे तो बजट एक वार्षिक आयोजन है, लेकिन इस बजट के मूल में एक दूरगामी लक्ष्य है और वह है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के लिए बुनियाद को मजबूत बनाना। इस बजट में भारत की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने एवं विकसित भारत को मूर्त रूप देने वाले पहलुओं का समावेश है। इसमें वित्तीय नीति, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय, विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्र, एमएसएमई और उद्यमिता समर्थन, कराधान उपाय और सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि की आवश्यकताओं को भलीभांति चिह्नित कर उनके लिए अपेक्षित उपाय किए गए हैं।

वैश्विक अनिश्चित माहौल में वित्त मंत्री ने विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। बजट में वर्ष 2031 तक जीडीपी के मुकाबले ऋण अनुपात को 50 प्रतिशत तक कम करने की राह तैयार की गई है। यह राजकोषीय घाटे को घटाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घाटे को नियंत्रित रखने के बावजूद सरकार ने विकास गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी उदारता दिखाई है।

बजट ब्याज के बोझ को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को भी संतुलित करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर जारी है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कई महत्वाकांक्षी नई परियोजनाओं का भी एलान किया गया है। इनमें सात हाई स्पीड रेल कारिडोर प्रमुख हैं। इनके अलावा नए डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर का निर्माण, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण, एक तटीय कार्गो प्रमोशन योजना और सात सिटी इकोनमिक जोन भी शामिल हैं। रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र भी बजट की प्राथमिकता के केंद्र में है। इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में सेमीकंडक्टर मिशन, घरेलू चिप निर्माण, आपूर्ति शृंखला में लचीलेपन और प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य शृंखलाओं को आकार देने पर ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा उत्पादन और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। रेयर अर्थ कारिडोर की पहल रेखांकित करती है कि भविष्य की योजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं में हैं।

अवधेश राजपूत

बायोफार्मा शक्ति मिशन और कार्बन कैप्चर, उपयोग, और भंडारण जैसी पहल भी सरकार के रणनीतिक सोच को रेखांकित करती हैं। सैकड़ों पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुत्थान और डेडिकेटेड रासायनिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से सरकार इकोसिस्टम संचालित ढांचे पर दांव पर लगा रही है। यह 'वाल्यूम प्रोड्यूसर' से 'वैल्यू प्रोड्यूसर' यानी मात्रात्मक उत्पादक से नवाचार प्रेरित गुणात्मक उत्पादक बनने की योजना पर काम कर रही है। अगर 2030 तक देश को सात ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की इकोनमी बनाना है तो ऐसा परिवर्तन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। बजट में छोटे उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बड़े कोष की स्थापना का भी प्रविधान है। इसका उद्देश्य उद्यमों तक पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना और आर्थिकी की रीढ़ को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी, बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से तरलता में सुधार जैसे तमाम उपाय भी उद्यमों के अनुकूल हैं।

बजट ने कई सामाजिक आयामों का भी ध्यान रखा है। जैसे कृषि को 1.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। इसमें उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, चंदन, काजू और कोको के लिए सार्थक उपाय किए गए हैं। साथ ही पारंपरिक अनाज फसलों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है। भारत विस्तार एआइ किसानों को मौसमी जानकारियां, मिट्टी की सेहत और बाजार कीमतों को एकीकृत करके आवश्यक मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होगा। इसकी सेवाएं कई भाषाओं में होंगी। लाभार्थी दीदी की सफलता के बाद 'शी-मार्ट योजना ग्रामीण महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है। चिकित्सा हब की स्थापना भारत को एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, 1.5 लाख विशेष कर्मियों को प्रशिक्षित करना हेल्थकेयर सेवाओं की बढ़ती मांग के अनुरूप ही है। उच्च शिक्षा से संबंधित एक नई समिति शैक्षणिक ढांचे और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच सेतु का काम करेगी। पर्यटन को प्राथमिकता में रखते हुए 50 महत्वपूर्ण गंतव्यों में प्राचीन पुरातात्विक स्थलों के कायाकल्प और विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण की योजना से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यटन आर्थिकी की संभावनाओं को भुनाना आसान होगा।

कराधान ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सुगमता के तमाम उपाय अवश्य किए गए हैं। कुछ आलोचकों को यह अखरेगा कि बजट में क्रांतिकारी घोषणाएं नहीं की गईं। इस पर यही कहना अधिक उचित होगा कि वित्त मंत्री ने कोई तात्कालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक मजबूती को वरीयता दी। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता के संकेत दे रही हो, लेकिन वैश्विक स्थितियां व्यापक रूप से अनिश्चित एवं अस्थिर बनी हुई हैं। ऐसे फिसलन भरे परिदृश्य में मजबूती देने वाले ऐसे ही बजट की आवश्यकता थी कि भारत के कदम फिसलें नहीं और वह सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चमकता रहे।

(लेखक सेबी एवं एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हैं परीक्षाएं

संजय कुमार

परीक्षा पे चर्चा पहल का यही संदेश है कि परीक्षाएं बोझ नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने एवं खुद को समझने का अवसर हैं

भारत में छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाने के लिए शुरू हुई 'परीक्षा पे चर्चा' पहल आज एक बड़ी जन-भागीदारी बन चुकी है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छात्रों के बीच हुई एक बातचीत से आरंभ हुई यह पहल अब करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 2025 में इस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया, जब एक ही महीने में 3.53 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी के लिए पंजीकरण किया। इसकी कुल पहुंच 21 करोड़ से अधिक दर्शकों तक रही, जिसमें विदेश स्थित भारतीय स्कूल भी शामिल थे। यह कार्यक्रम छात्रों को यह संदेश देता है कि परीक्षाएं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि सीखने की यात्रा का सिर्फ एक प्रमुख चरण हैं। प्रधानमंत्री बार-बार इस पर जोर देते हैं कि परीक्षा केवल किसी विशेष क्षण में आपकी तैयारी को मापती हैं, जबकि सीखना लगातार और आनंददायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'आजीवन सीखने' की अवधारणा पर गहराई से जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अंकों का प्रतिशत बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकता। बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर अलग-अलग कौशल सीखने, नई गतिविधियों को आजमाने और चुनौतियों को डर के बजाय अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जाना है।

इस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है। विशेषज्ञ छात्रों को तनाव कम करने के आसान तरीकों से परिचित करा रहे हैं, जिनमें 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक, पर्याप्त नींद, पानी, व्यायाम और ध्यान जैसी स्वस्थ दिनचर्या शामिल हैं। 5-4-3-2-1 इंद्रिय-आधारित ध्यान अभ्यास है, जिसे पांचों इंद्रियों का उपयोग करके विचारों की दौड़ को शांत करने और अंततः उन्हें एक इंद्रिय तक सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा करने से आपका ध्यान चिंता पैदा करने वाले विचारों से हटकर वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। इस तकनीक को 18वीं शताब्दी में बेट्टी एलिस एरिक्सन ने विकसित किया था। खेल जगत की कई हस्तियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया था कि खेल पढ़ाई में बाधा नहीं, बल्कि तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं।

परीक्षाओं को लेकर दृष्टिकोण बदलना आवश्यक ● फाइल

डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रचलन से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उससे संज्ञान का ह्रास हो रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है। विश्व में 5.66 अरब डिजिटल मीडिया प्रोफाइल हैं। लोग प्रतिदिन डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर सामग्री देखने में 15 अरब घंटे व्यतीत करते हैं, जो मानव जीवन के 17 लाख वर्षों से अधिक के बराबर है। अत्यधिक उपयोग से 'डिजिटल डिमेंशिया' में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ग्रे मैटर की कमी हो जाती है, जो भावनात्मक विनियमन और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम डिजिटल मीडिया को नकारने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें इसके उपयोग के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे मोबाइल और डिजिटल साधनों को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि तकनीक मददगार बने, बोझ नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अभिभावकों को भी महत्वपूर्ण संदेश देता है कि वे बच्चों का ध्यान केवल अंकों पर न लगाएं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। बच्चों की तुलना दूसरों से न करें और अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे खुलकर अपने डर, चुनौतियों और उम्मीदें साझा कर सकें। अभिभावकों का सहयोगी व्यवहार बच्चों की परीक्षा तैयारी में सबसे ज्यादा मदद करता है।

भारतीय शिक्षा दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति को एक एकाकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साझा पथ माना गया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शिक्षकों से अपील करता है कि वे रटने की संस्कृति से आगे बढ़कर आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें छात्र-केंद्रित, तनाव-मुक्त और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की जरूरत है ताकि परीक्षाएं केवल याद्दाश्त नहीं, बल्कि समझ, अनुप्रयोग और विकास को माप सकें। डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग भी शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। स्कूलों और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस पहल के सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए स्कूलों में वेलनेस कमेटियां बनाना, तनाव प्रबंधन और अध्ययन कौशल पर कार्यशालाएं आयोजित करना, अभिभावक-शिक्षक संवाद बढ़ाना और छात्रों की उपलब्धियों को केवल अंकों के बजाय विविध क्षेत्रों में पहचानना जरूरी बताया गया है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभिलेखित एक्जाम वारियर्स जैसे संसाधनों को हर छात्र तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है।

अंततः परीक्षा पे चर्चा मात्र एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका संदेश स्पष्ट है-परीक्षाएं बोझ नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और खुद को समझने का अवसर हैं।

(लेखक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कल्पना शक्ति

मनुष्य का मस्तिष्क अनंत शक्तियों से संपन्न है। कल्पना ऐसी ही एक शक्ति है। कल्पना की शक्ति से व्यक्ति जीवन में मनचाहे रंग भर सकता है। किसी भी विचार का आधार कल्पना ही होती है और विचार ही व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए कल्पनाओं की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे सकारात्मक कल्पना के अभाव में प्रायः मनुष्य कुकल्पनाओं के जंजाल में भारी त्रास झेलने के लिए विवश होता है। भय का भूत मात्र कल्पना के आधार पर जीवित हो उठता है। कल्पना की नकारात्मक शक्ति हमारे सोच को भय, उद्विग्नता एवं वितृष्णा के भाव से भर देती है और जीवन को कष्टदायक बना देती है।

वहीं, सकारात्मक कल्पना शक्ति से हम प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य से लेकर धन, वैभव, ऐश्वर्य को आकर्षित कर सकते हैं। अपनी आदतों को सुधारकर व्यक्तित्व को मनचाहा रूप दे सकते हैं और जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय ला सकते हैं। कल्पना के सहारे ही कवि, लेखक, विज्ञानी और विचारक अपनी सृजन-साधना में नए रंग भरते हैं और संसार को कुछ नया देकर जाते हैं। कल्पना शक्ति के लिए ही कहावत प्रसिद्ध है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि।

कल्पना की इस अमोघ शक्ति को समझते हुए हम जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अपने कल्पित ध्येय को कार्ययोजना के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ लागू करें। आपके प्रयास, चेष्टाएं, संकल्प और विचारणा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे खंडों में विभक्त करें और दृढ़ता के साथ समय-पालन करें। छोटी-छोटी सफलताओं के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े कदम संभव होंगे। साथ ही ज्ञान का दायरा बढ़ाते रहें। प्रतिदिन कुछ नया एवं प्रेरक पढ़ें या सीखें। इससे आपकी कल्पना शक्ति नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसे और व्यापक रूप देने के लिए महापुरुषों के प्रेरक जीवन-चरित्र का अवलोकन भी सार्थक होता है।

गौरीशंकर वैश्य

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बड़ी कूटनीतिक जीत

'विरोध करने की आदत' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में समकालीन राजनीति के स्वरूप को ही रेखांकित किया गया है। यह स्पष्ट है कि अब किसी भी मुद्दे पर विरोध के लिए विरोध का झंडा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसीलिए कांग्रेस का विरोध न तो किसी सार्थक बहस को जन्म देता है और न ही सत्ता पक्ष को अपने रवैये पर विचार को मजबूर करता है। इस तनातनी में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति नया बिंदु बनी है। जब अमेरिका ने टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है तो इसका विरोध करने का क्या तुक है। यह देश हित में, व्यापारियों के हित में और अंततः जनता के हित में ही है। इससे भारत के विकास की गति बढ़ेगी। क्या कांग्रेस और उसके नेता चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध बना रहे। अमेरिका के साथ दूर हुआ व्यापारिक गतिरोध तो पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिन्होंने दिखाया कि भारत किसी के समक्ष झुकने वाला नहीं, भले ही वह देश कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।

अतिवीर जैन 'पराग', कंकर खेड़ा, मेरठ कैंट

मोदी सरकार की सफल कूटनीति

पिछले 11 महीने से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर जमी हुई बर्फ पिघलती हुई दिख रही है। जब विदित हुआ कि अमेरिका ने भारत पर लगे हुए 50 प्रतिशत शुल्क दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता एवं कूटनीतिक दबाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आनाकानी का प्रदर्शन किया जा रहा था। जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत-अमेरिकी संबंधों के बारे में गलत संदेश दे रहा था। प्रतिस्पर्धी शुल्क दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना दोनों देश के बीच हुए सम्मति का मार्ग प्रशस्त होने को दर्शाता है। भारत द्वारा अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात बढ़ाना व्यापार खाते को भारत के पक्ष में होना प्रतीत हो रहा है। मंद पड़ गई निर्यात की गति को पंख लगाना दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रवैये के कारण डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर गिरती चली जा रही थी। विगत छमाही में अमेरिका के असहयोग के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में घटोतरी का प्रदर्शन दिख रहा था। देर आयद दुरुस्त आयद की मुद्रा में अमेरिका के नीति निर्धारकों को भारत से लंबे समय तक आर्थिक कूटनीतिक संबंध बिगाड़ने में अपनी छवि में नुकसान होता दिखने लगा तो अंतत अक्ल आ ही गई। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश ब्राजील 50 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका 30 प्रतिशत से कम शुल्क दर नहीं करा पाए। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य होते हुए 18 प्रतिशत कराने में सफल हो गया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार की दमदार कूटनीति का परिचायक है। चीन भी 37 प्रतिशत शुल्क दर देने को बाध्य है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

कांग्रेस की वैचारिक उलझन

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं होती, वह देश की सामूहिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का आईना भी होती है। बजट सत्र में लोकसभा के भीतर जो कुछ देखने को मिला, उसने इस आईने को धुंधला कर दिया। बार-बार का स्थगन, नारेबाजी, वेल में उतरना और संवाद के बजाय अवरोध की राजनीति यह सब किसी एक घटना या मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। यह एक गहरी वैचारिक बेचैनी का संकेत है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक धारा होने का दावा करती है। कांग्रेस की विचारधारा ऐतिहासिक रूप से समावेशन, संस्थागत लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में यही पार्टी विभिन्न विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक मंच पर लाने में सफल हुई। लेकिन समय के साथ इस विचारधारा में स्पष्टता के बजाय विरोधाभास बढ़ते चले गए। आज कांग्रेस का आचरण यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी अब भी उसी राष्ट्रीय दायित्वबोध के साथ राजनीति कर रही है, या वह केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं को दबाव में लेने की रणनीति अपना चुकी है। हालिया सत्र में सेना प्रमुख की कथित किताब को लेकर कांग्रेस का रुख इसी उलझन को उजागर करता है। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

पोस्ट

नशा और आनलाइन गेम्स फिलहाल हमारे देश के लिए दो नई महामारी हैं। डा. अनुज कुमार@dranuj_k

वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि गेम्स की लत लग जाने का दिमाग पर बुरा असर होता है। एमआरआइ स्कैन में पाया गया कि वीडियो गेम्स की लत का असर वैसा ही होता है, जैसे ड्रग्स या शराब की लत का। रजत शर्मा@RajatSharmaLive

गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही केवल 63 सेकंड ही चली। देखा जाए तो जीवन का असली आनंद तो हमारे सांसद उठा रहे हैं। अद्वैता काला@AdvaitaKala

संसद में नेता इतिहास की किताबें लहराकर वर्तमान की कब्र खोद रहे हैं। यह हंगामा नहीं जनता को बेवकूफ बनाने का प्रोजेक्ट है। जरूरी मुद्दों पर कोई बात ही नहीं। अनुरंजन झा@anuranjanj

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कन्हैयालाल की निर्मम हत्या का मुद्दा संसद में उठाया। नुपुर शर्मा का नाम राज्यसभा में लिया गया। अर्से बाद किसी ने तो दिलेरी दिखाई। मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

जनपथ

मोबाइल पकड़ा रहे हम बच्चों के हाथ,
या फिर स्वयं छुड़ा रहे उनसे अपना साथ।
उनसे अपना साथ सुनाते ना हम लोरी,
दिखला रही मशीन उन्हें बकवासें कोरी!
बच्चों की इक बार खोलकर देखो फाइल,
क्या-क्या उन्हें सिखाय रहा दुश्मन मोबाइल!!

– **ओमप्रकाश तिवारी**

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 203

एअर इंडिया के 267 विमानों में से लगभग तीन-चौथाई विमानों में बार बार सामने आईं गड़बड़ियां

- नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने लोकसभा को दी जानकारी
- छह एयरलाइन कंपनियों के 377 विमानों में गड़बड़ियां मिलीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने लोकसभा में बताया कि एअर इंडिया ग्रुप के 267 विमानों से संबंधित विश्लेषण से पता चला कि इनमें से लगभग तीन-चौथाई विमानों में बार बार गड़बड़ियां सामने आईं। छह एयरलाइन कंपनियों के कुल 754 विमानों में से पिछले जनवरी से कुल 377 विमानों में बार बार गड़बड़ियों का पता चला है। इंडिगो के 405 विमानों में से 148 विमानों में बार बार समस्याएं आईं।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहाल ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि एअर इंडिया के 166 विमानों में से 137 विमानों में बार बार गड़बड़ियों की पहचान की गई, जबकि एअर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 विमानों में बार बार समस्याएं आईं। कुल मिलाकर, एअर इंडिया समूह के 267 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 191 में बार बार गड़बड़ियों की पहचान हुई। स्पाइसजेट के 43 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 16 विमानों में बार बार समस्याओं की पहचान की गई। अकासा एयर के विमानों 32 विमानों में से कुल 14 विमानों में बार बार दिक्कतें आईं। इस डाटा पर एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, हमने पूरी बेड़े में सावधानी बरतते हुए जांच की है। इसलिए संख्या अधिक है। अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि 2022 में डीजीसीए में 637 स्वीकृत तकनीकी पद थे। स्वीकृत तकनीकी पदों की संख्या बढ़ाकर 1063 कर दी गई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में उड़ानों में तकनीकी समस्याओं के मामलों में कमी आई है। 2024 में 421 तकनीकी समस्याएं सामने आईं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और तीन विमानन नियामकों डीजीसीए, बीसीएएस और एईआरए में 2,645 पद रिक्त हैं।

भारत-श्रीलंका गहरे सभ्यतागत व आध्यात्मिक बंधनों से जुड़े : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका "गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक बंधनों" से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोलंबो में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके को धन्यवाद दिया। गुजरात स्थित देवनीमोरी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त इन पवित्र अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी चार से 11 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। मोदी ने संदेश में लिखा, "अप्रैल 2025 को मेरी यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ये अवशेष श्रीलंका लाए जाएंगे, जिससे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो

मलेशिया संग रक्षा, समुद्री सहयोग व अन्य क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद

जाब्यू नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी की सात-आठ फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सहयोग, सेमीकंडक्टर और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में अहम समझौता होने की उम्मीद है।

स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल, कहा- उत्तर भारतीय यहां गोलगप्पे बेचने आते हैं

कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम

- पन्नीरसेल्वम ने कहा- दो भाषाओं में पारंगत तमिल छात्र देश-विदेश में पा रहे हैं करोड़ों की नौकरियां
- उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी के बाद मंत्री घिरे, भाजपा व सहयोगियों ने की आपत्ती

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम के उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों पर दिए गए 'पानी-पूरी (गोलगप्पे)' के संदर्भ वाले बयान के बाद राज्य में 'हिंदी बनाम गैर हिंदी' और 'उत्तर बनाम दक्षिण' का विवाद और भी गहरा गया है। घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब चेंगलपट्टू में एक कार्यक्रम में मंत्री पन्नीरसेल्वम ने तीन भाषाओं के मुद्दों फिर से हवा देते हुए दावा किया कि तमिलनाडु की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग राज्य में आकर निम्न स्तर के काम कर रहे हैं। बुधवार को पन्नीरसेल्वम ने कथित तौर पर कहा, "उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में मेजें साफ करने आ रहे हैं... वे यहां निर्माण मजदूर, पानी-पूरी बेचने वाले बनकर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी ही सीखी है। बयान सामने आते ही भाजपा ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर द्रमुक नेता का साथ देने का आरोप लगाया। द्रमुक ने बचाव की रणनीति अपनाई। पार्टी के लोकसभा सांसद टीआर बालू ने कहा कि मंत्री के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

माउंट एकोनकागुआ के संयुक्त अभियान को रक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली, एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लाक से अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ के लिए संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6,961 मीटर ऊंचा यह पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत है। यह संयुक्त अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम द्वारा संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दुर्गम शिखर पर चढ़ाई करना केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। यह सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों की पहचान है।

संसद प्रश्नोत्तर

22 भाषाओं में सेवा देने में सक्षम हो जाएगा स्वदेशी एआइ भारतजेन : जितेंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश का स्वदेशी बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) सिस्टम भारतजेन इस महीने के अंत तक भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में सेवा देने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारतजेन एआइ का विकास गतिशील प्रक्रिया है व इसमें और अधिक भाषाएं एवं बोलियां भी जोड़ी जा सकती हैं। इनमें से 15 भाषाओं में लिखने के साथ-साथ बोलने और तस्वीरों को पहचानने की सुविधा विकसित कर ली गई है।

दूध में यूरिया, आइसक्रीम में डिटर्जेंट : राघव चड्ढा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया। कहा कि बाजार में शुद्धता का झूठा लेबल लगाकर जहर बेचा जा रहा है। दूध में यूरिया, आइसक्रीम में डिटर्जेंट, सब्जियों में आक्सीटोसिन और पनीर में कास्टिक सोडा की मिलावट की जा रही है। आक्सीटोसिन एक हानिकारक रसायन है, जो चक्कर आना, हृदय गति रुकना, बांझपन व कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। राघव चड्ढा ने संसद में अपने भाषण का वीडियो एक्स पर भी साझा किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है।

महिलाओं पर 'लक्ष्मी' की वर्षा, युवाओं को 'भत्ता'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के बीच गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ममता और वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट के जरिए महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों व किसानों को साधने की कोशिश की है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य की फ्लैगशिप 'लक्ष्मी भंडार' योजना में बढ़ोतरी है। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 की जगह 1500 रुपये और एससी/एसटी वर्ग को 1200 की जगह 1700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

पहले बीएसएफ का बढ़ा हुआ दायरा घटाए केंद्र फिर फेंसिंग के लिए देंगे जमीन : बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता ने केंद्र सरकार के उस फैसले को मनमाना बताया, जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। उन्होंने शर्त रखी कि केंद्र को सबसे पहले इस विस्तारित दायरे को वापस लेना होगा।

'कांग्रेस का रुख देख मैंने पीएम को आने से रोका'

बिरला बोले, कांग्रेस सदस्य ऐसा करने वाले थे कि लोकतंत्र तार-तार हो जाता

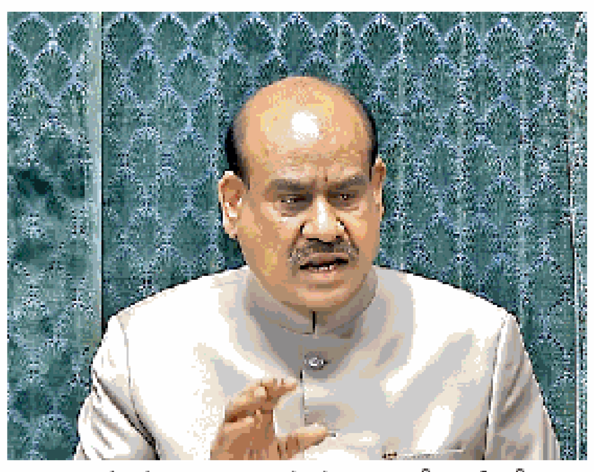

बजट सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ● एएनआइ

- मोदी को बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर देना था लोकसभा में चर्चा का जवाब
- कांग्रेस की महिला सदस्य बैनर लेकर पीएम की सीट के पास पहुंचने लगी थीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में दो दिनों से कांग्रेस नेतृत्व में विपक्ष का जो शोर-शराबा चल रहा था, उसके पीछे और भी आपत्तिजनक घटना का ताना-बाना बुना जा रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अनुसार कांग्रेस सदस्य प्रधानमंत्री की सीट के पास कुछ 'अप्रत्याशित' कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए आने से मना किया था। ध्यान रहे कि बुधवार को प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए आना था, लेकिन कांग्रेस की महिला सदस्य बैनर लेकर उनकी सीट के पास पहुंचने लगी थीं। गुरुवार को लोकसभा में ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

गुरुवार को अवरोध के बाद जब सदन बैठा तो बिरला ने कहा कि उन्हें इसकी पक्की जानकारी मिली थी। अगर विपक्ष की रणनीति अंजाम तक पहुंचती तो लोकतंत्र तार-तार हो जाता, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से नहीं आने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने इस आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद।

उन्होंने विस्तार से बताया कि विपक्षी सदस्यों का आचरण बहुत गंभीर है। सदन में व्यवधान के बाद लोकसभा स्पीकर के कक्ष में भी उनको व्यवहार निंदनीय था। उसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। गुरुवार को भी कांग्रेस कार्यालय में लंबी बैठक चली थी और लोकसभा के विरोध को राज्यसभा तक लाने की तैयारी थी। हालांकि लोकसभा से भिन्न राज्यसभा में कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई। बहरहाल, बिरला के बयान का प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाहर विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री आसन के पीछे छिप रहे हैं। विपक्ष की प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन अगर विपक्ष के साथ भेदभाव होगा तो विरोध होगा।

'सरकार ने ठान लिया है कि नेता विपक्ष को नहीं बोलने देंगे'

राज्यसभा में प्रधानमंत्री के धन्यवाद अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामे के बाद किया वाकआउट ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भी इसको लेकर सरकार पर न केवल हमला बोला, बल्कि अभूतपूर्व एकजुटता दिखाते हुए वाकआउट करके विरोध दर्ज कराया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए एक सदन को पंगु बनाकर उसे चलने नहीं दे रही। चार दिनों से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जो देश और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।

राज्यसभा में खरगे ने भी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की उसी अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने का प्रयास किया, जिसका प्रयास राहुल गांधी ने लोकसभा में किया था। मगर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अनुमति नहीं दी। तब खरगे ने सत्तापक्ष के विरोध के बीच सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले चार दिनों से लोकसभा काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। सभापति ने दूसरे सदन का मामला नहीं उठाने की बात कही तो खरगे ने कहा कि दोनों सदनों से मिलकर संसद बनती है। जब राहुल इस बारे में बात करते हैं, तो आपको खुजली उठती है...। नेता सदन जेपी नड्डा व संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने आपत्ति व्यक्त की। नड्डा ने पलटवार किया और राहुल पर निशाना साधते हुए खरगे से कहा कि वह अपनी पार्टी को किसी अबोध बालक का बंधक नहीं बनने दें। कहा, 'यहां पर अभिमान, अहंकार व अबोध होकर काम नहीं करना चाहिए।' इस पर खरगे ने राहुल के लिए "अबोध बालक" शब्द के इस्तेमाल की निंदा की।

मोदी को बोलने से नहीं रोक पाई कांग्रेस, नहीं मिला साथ

नई दिल्ली : जैसे ही तय हुआ कि प्रधानमंत्री गुरुवार शाम पांच बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे, वैसे ही संसद के गलियारों में यह चर्चा के केंद्र में आ गया। खास तौर पर विपक्षी खेमा जैसे तय वक्त की प्रतीक्षा कर रहा हो, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को न बोलने देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस इस राजनीतिक रार को राज्यसभा तक ले ही जा चुकी थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने सहयोगी दलों की बैठक भी बुलाई। राजग खेमे ने एकजुटता प्रदर्शित की, लेकिन कांग्रेस अपने नेता के कथित अपमान के मुद्दे पर अलग-थलग दिखाई दी।

पीएम ने कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए किया जा रहा कोर्ट का इस्तेमाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी सदस्यों को भी आड़े हाथों लिया। बंगाल में तृणमूल और केरल में माकपा सत्ता में है, जहां अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री ने तृणमूल सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि पतन के सभी पैरामीटर पर वह राज्य को गर्त में ले जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसआइआर की सुनवाई के दौरान खुद बहस करने पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया घुसपैठ रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं बंगाल में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। घुसपैठिये युवाओं का रोजगार और आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, उसे बचाने की जगह तृणमूल के सदस्य संसद में उपदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों कृत्रिम पैर सामने रखकर राज्यसभा में बोलने वाले नामित सदस्य सदानंद मास्टर के दृश्य को पूरे देश के लिए पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा, 'राजनीतिक दुश्मनी के कारण जवानी में उनके पैर काट दिए गए थे।" उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले और शीशमहल का उल्लेख कर आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह के उपदेश देने पर भी कटाक्ष किया।

पीएम पद पर टिके रहने से कांग्रेस परेशान : कांग्रेसी सरकारों की छोड़ी समस्याओं का पिछले 12 वर्षों में किए समाधान गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस की परेशानी उनके प्रधानमंत्री बनने और उस पर टिके रहने को लेकर है। गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री के पद को अपना पैतृक अधिकार मानता था। सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए इतनी नफरत कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का मजाक उड़ाने के लिए भी कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आज भारत पूरी दुनिया के साथ स्पर्धा के लिए तैयार है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ डील का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, विकसित देशों का विकासशील देश के साथ ट्रेड डील करना अपने-आप में अहम है। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले पांच वर्षों में दूसरे विश्व युद्ध के समय से चली आ रही वैश्विक व्यवस्था बदलने लगी है और भारत ग्लोबल साउथ के मजबूत लीडर के रूप में सामने आया है। भारत अब 'रिफार्म एक्सप्रेस' पर सवार है व 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

कांग्रेस मानती थी देश के लोगों को समस्या : मोदी

मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने एक बार एक घटना का जिक्र किया था, जब किसी ने उनसे पूछा कि उनके पिता नेहरू को भारत में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा व उन्होंने जवाब दिया था- 35 करोड़ आबादी। मोदी ने कहा, 'और जब इंदिरा गांधी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा 57 करोड़, उस समय भारत की आबादी इतनी थी।' मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारतीयों को 'समस्या' मानती थी, जबकि उनकी सरकार उन्हें ताकत व चुनौतियों का समाधान मानती है।

चुनावी रेवड़ियों के वादों के विरुद्ध अर्जी पर शीर्ष कोर्ट में अगले माह सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट मार्च में उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें चुनाव से पहले तर्कहीन रेवड़ियां बांटने या वादा करने वाले वाले राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह जब्त करने या उसे अपंजीकृत करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वकील एवं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि उनकी जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को 2022 में ही नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया हमें याद दिलाएं और अंत में उल्लेख करें। इसे मार्च में सूचीबद्ध करेंगे।" 25 जनवरी, 2022 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था।

जन सुराज पार्टी ने शीर्ष कोर्ट में दी चुनौती : जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। याचिका में पार्टी ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव के एलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए।

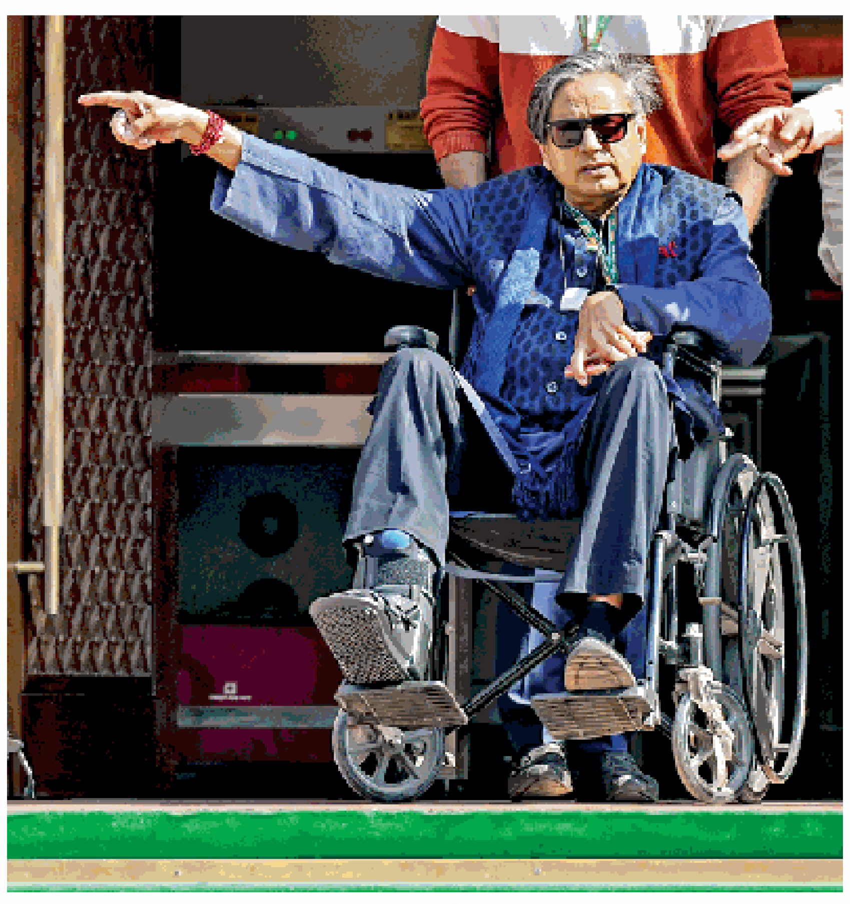

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर संसद में व्हीलचेयर पर नजर आए। एक दिन पहले वह संसद परिसर में लड़खड़ा गए थे। इससे उनके पैर में चोट लग गई थी ● प्रेट्र

कांग्रेस का बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला

संजय मिश्र ● जागरण

- खरगे-राहुल के साथ बंगाल के नेताओं की बैठक के बाद 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान
- राज्य में वामपंथी दलों से खींचा दोस्ती का हाथ, तृणमूल कांग्रेस से भी रखेगी दूरी

नई दिल्ली : बंगाल में गठबंधनों के प्रयोग का लाभ नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने अंततः 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही पार्टी ने बंगाल में वामपंथी दलों से चले आ रहे गठबंधन को विराम दे दिया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस से तालमेल नहीं करने का एलान किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के अधिकांश नेताओं की एकला चलो की राह पर लौटने की राय पर मुहर लगा दी है। बंगाल कांग्रेस के प्रभारी पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने के निर्णय की घोषणा कर सियासी तस्वीर साफ कर दी। बंगाल में वामपंथी दलों से सियासी दोस्ती का हाथ खींच कर कांग्रेस ने केरल के चुनाव में सियासी पांव पसारने के लिए कांग्रेस-लेफ्ट के एक ही होने के सियासी विमर्श को आगे बढ़ाने की भाजपा की तैयारी को रोकने का भी दांव चल दिया है।

मल्लिकार्जुन खरगे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर बंगाल कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर ने पत्रकारों के समक्ष अप्रैल-मई में होने वाले चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर पार्टी के अकेले लड़ने के निर्णय की घोषणा की। बैठक में राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्य से कांग्रेस के एकलौते लोकसभा सदस्य ईशा खान चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे।

बैठक में बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने एकला चलो को संगठन ही नहीं, जमीनी सियासत के लिहाज से भी जरूरी बताया। बंगाल के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक सुदीप राय बर्मन ने भी शुभंकर सरकार तथा गुलाम अहमद मीर का समर्थन किया कि राज्य में तृणमूल सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, मगर भाजपा की पूरे प्रदेश में अभी पूर्ण स्वीकार्यता नहीं है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा- महंगाई भत्ता कर्मचारी का हक, भुगतान करे बंगाल सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त फायदा नहीं, बल्कि यह जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। शीर्ष अदालत ने बंगाल के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पाने के अधिकार पर मुहर लगाते हुए कहा है कि जब डीए को एक बार वैधानिक नियमों के अनुसार आल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स से जोड़कर परिभाषित कर दिया जाता है तो राज्य बाद में आफिस मेमोरेंडम के जरिए इसकी गणना के तरीके को नहीं बदल सकता।

सर्वोच्च अदालत ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि का महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को छह मार्च तक डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को डीए देने के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी इस फैसले के अनुसार 2008-2019 की अवधि के महंगाई भत्ते की बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी साल में दो बार डीए पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने फैसले में महंगाई भत्ते के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता एक वेलफेयर स्टेट के हाथों सुरक्षा के एक व्यावहारिक साधन के रूप में सामने आता है, जो अपने कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के बुरे असर से बचाता है।

- बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि का महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश इंदु के नेतृत्व में समिति गठित

कोर्ट ने कहा कि डीए कोई अतिरिक्त फायदा नहीं है, बल्कि ये जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। हालांकि डीए देने के आदेश के वित्तीय असर को देखते हुए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और गौतम भादुड़ी तथा कंपट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया या उनके द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी होंगे। कमेटी समय-समय पर राशि जारी होने की पुष्टि करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भुगतान राशि और शेड्यूल छह मार्च 2026 से पहले तय हो जाना चाहिए।

बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव में 1400 पर्यवेक्षक संभालेंगे मोर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बंगाल, असम सहित पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा में अभी भले ही वक्त है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन राज्यों से जुड़ी चुनावी तैयारियों को तेज कर किया है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने इन राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों के साथ गुरुवार से चर्चा शुरू कर दी है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 1400 से अधिक अधिकारियों को बुलाया गया है। इनमें सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक आदि के रूप में तैनात किए जाने वाले अधिकारी शामिल हैं।

पर्यवेक्षकों के साथ दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक के पहले दिन यानी गुरुवार को उन्हें संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें आयोग की ओर से पथ-प्रदर्शन के रूप में सेवाएं देने के लिए चुना गया है। पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें। चुनाव से जुड़े नियमों व दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं।

बंगाल में एसआइआर के दौरान हिंसा और बाधा डालने की घटनाएं हुईं : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हिंसा, डराने-धमकाने और काम में बाधा डालने की कई घटनाएं हुईं। अपने हलफनामे में, चुनाव आयोग ने दावा किया कि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में हुए एसआइआर के एकदम विपरीत थी। वहां बिना किसी रुकावट और बिना किसी घटना के एसआइआर हुआ। आयोग ने कहा कि 2025 की चुनावी मतदाता सूची आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि 58 लाख से अधिक अनुपस्थित, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई और लगभग 1.51 करोड़ नोटिस चुनावी पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। हलफनामे के अनुसार, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा बीएलओ की ओर से गई शिकायतों पर मामले दर्ज करने में आनाकानी की गई और कुछ एफआइआर केवल जिला चुनाव अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की गईं। आयोग ने कहा कि राज्य ने एफआइआर दर्ज करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने में जानबूझकर लापरवाही बरती। पिछले वर्ष 24 नवंबर को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कोलकाता कार्यालय का घेराव करने के संबंध में हलफनामे में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने वहां जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया, पुलिस बैरिकेड तोड़े, कार्यालय को नुकसान पहुंचाया, परिसर को बंद किया और अधिकारियों को अंदर और बाहर जाने से रोका, जिससे कामकाज पूरी तरह बाधित हुआ।

आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा- राज्य में 58 लाख से अधिक अनुपस्थित, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई

आयोग की बंगाल के मुख्य सचिव को कड़ी चिट्ठी, अमल न होने पर मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामले में खुद पैरवी करने के चंद घंटे बाद ही चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को कड़ी चिट्ठी लिखी है। आयोग ने पूछा है कि उसके विभिन्न निर्देशों पर राज्य प्रशासन की ओर से अब तक अमल क्यों नहीं किया गया है? आगामी सोमवार तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने पूछा है कि उसके निर्देश के बावजूद मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपित दो चुनाव पंजीकरण अधिकारियों, दो सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आयोग ने यह भी पूछा कि बशीरहाट-2 की सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी व प्रखंड विकास अधिकारी सुमित्रा प्रतिम प्रधान को निलंबित क्यों नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

दर्दनाक वाकया

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों का नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना को महज 'आत्महत्या' कहना हकीकत से आंखें मूंदने जैसा होगा। बारह, चौदह और सोलह की उम्र तो सपनों के पंख लगाकर उड़ने की होती है। उस उम्र में मौत को गले लगाना भला किसके गले उतर सकता है? दरअसल, हालात, स्थितियों और आभासी भावनाओं के झूठे संसार ने इन मासूमों को मौत की दर तक पहुंचाया। यह एक 'डिजिटल मर्डर' है। इस खतरनाक गेम और इसे बच्चों तक परोसे जाने के जिम्मेदार लोगों के लिए कानून को नई दफाएं गढ़नी होंगी। यह दुखद हादसा खूनी डिजिटल एल्गोरिदम का परिणाम है, जो मोबाइल के जरिये हम सबके घरों में घुस आया है।

यह घटना 'कोरियन लव गेम' की लत और उसके पीछे छिपे एल्गोरिदम की कारगुजारी है। यह डिजिटल एल्गोरिदम मासूमों के दिमाग को पूरी तरह से अपहृत कर लेता है और विवेक पर झूठी भावनाओं का पर्दा डाल देता है। इसे समझने के लिए इन बहनों के आठ पन्नों के सुसाइड नोट पर नजर डाल देखिए। यह जीवन से हताश किसी नासमझ बच्ची का सुसाइड लेटर नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया के खिलाफ एक आरोप पत्र है। 'मम्मी-पापा सॉरी... गेम नहीं छोड़ पा रही हूं।' यह वाक्य साबित करता है कि ये किशोरियां किसी मानसिक रोग की गिरफ्त में नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग का शिकार थीं, जिसे बनाया ही लत लगाने के लिए गया है। 'टास्क-बेस्ड गेम्स' इनको खेलने वाले बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा स्तर पैदा करते हैं कि उन्हें वास्तविक दुनिया बेमानी और डिजिटल खेल की चुनौतियां ही जीवन का एकमात्र सत्य लगने लगती हैं। जब कोई गेम बच्चों से स्कूल और किताबें छुड़वा दे, तो वह मनोरंजन नहीं करता, मानसिक गुलाम बनाता है। गाजियाबाद की घटना में जब पिता ने तीनों बेटियों को रोकने की कोशिश की, तो उनके लिए वह टोकना एक दुश्मन के वार जैसा था। यह उस गेम की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो खिलाड़ी को बाहरी दुनिया से काट देती है। यह सच है कि आज बिना मोबाइल के हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि स्मार्टफोन उपयोगी होने के साथ-साथ एक 'साइलेंट किलर' भी है।

गाजियाबाद में तीन बहनों की एक साथ खुदकुशी हर माता-पिता के लिए चेतावनी है। वे यह सोचकर निश्चिंत न बैठें कि उनका बच्चा सुरक्षित मोबाइल चला रहा है।

गाजियाबाद की घटना हर उस माता-पिता के लिए एक चेतावनी है, जो यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनका बच्चा कमरे में सुरक्षित मोबाइल चला रहा है। कोरियन लव गेम जैसे डिजिटल खेल बच्चों की भावनाओं और असुरक्षा बोध का फायदा उठाकर उन्हें 'टास्क' पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। निगरानी के अभाव में गेमिंग कंपनियां मुनाफे के लिए ऐसे-ऐसे फीचर डालती हैं, जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रहार करते हैं और उनको इस कदर लती बना देते हैं कि उन्हें मौत को गले लगाने से भी गुरेज नहीं हो रहा। गाजियाबाद की तीनों बहनों की चिता की आग ठंडी होने से पहले हमें जागना होगा। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि बड़ा सामाजिक संकट है। हमें 'डिजिटल पेरेंटिंग' को अब गंभीरता से लेना होगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव, एकांत-प्रियता और पढ़ाई से दूरी को मामूली न समझें। उन्हें तकनीक के साथ-साथ तनाव से लड़ना भी हमें सिखाना होगा। अगर हम अब भी नहीं चेते, तो आभासी दुनिया के ये गेम असल दुनिया की मासूम जिंदगियों को निगलते रहेंगे। याद रखिए, मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा खतरा आपके घर की दहलीज पार कर चुका है।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 06 फरवरी, 1951

राजाओं का संघ

भारतीय राजनीति में अनेक दल काम कर रहे हैं और हरेक न्यूनाधिक मात्रा में जनता के किसी न किसी अंग से समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किन्तु राजाओं का संघ किस बीमारी की दवा है। यह हम अभी तक नहीं समझ पायें।

इस संस्था का अध्यक्ष महाराजा बड़ौदा को बनाया गया है और केवल इसी बात ने जनता में उसके खिलाफ एक आम धारणा उत्पन्न कर दी है। महाराजा के हाथ में जब रियासत की शासन सत्ता थी, तब उनका अधिकतर समय विदेशों में ही बीतता था। प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा वह विलायत में घोड़े दौड़ाने में फूंकते रहते थे। किन्तु अब उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि उनमें जन-सेवा की भावना बड़े वेग से उमड़ पड़ी है। अभी-अभी वह विलायत के अपने ताजा सफर से लौटे हैं और उन्होंने अपने एक वक्तव्य द्वारा राजाओं के संघ को जनता की निगाह में लाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान ने जिन मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी है, उनमें सभा-संस्था बनाने का अधिकार भी शामिल है। राजाओं ने अपना संघ स्थापित कर सभा-संस्था बनाने के उसी मूलभूत अधिकार का उपयोग किया है।

जब तक राजा लोग संविधान की मर्यादा के भीतर रहकर काम करेंगे और संविधान को उलटने की नीयत से कोई काम नहीं करेंगे, तब तक उनके आपस में मिलने-जुलने और विचार-विमर्श करने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। किन्तु राजाओं की एक विशिष्ट सत्ताभोगी श्रेणी रही है और उन्हें स्वेच्छापूर्वक अथवा बाध्य होकर अपनी सत्ता का परित्याग करना पड़ा है।...

राजाओं के संघ का मुख्य उद्देश्य राजाओं के हितों की रक्षा करना है। यह विचारणीय है कि नयी व्यवस्था में राजाओं के कौन से हित हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए राजाओं को संगठित होने की आवश्यकता अनुभव हुई है। राजाओं का जेब खर्च निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसके समय पर मिलने पर कोई अड़चन पेश आये, तो यह उनके लिए चिन्ता का विषय हो सकता है। किन्तु अभी तक कोई ऐसा उदाहरण प्रकाश में नहीं आया, जिसमें किसी राजा को अपना निश्चित जेब खर्च समय पर प्राप्त करने में बाधा आयी हो। उनकी मान-मर्यादा जितनी नयी परिस्थितियों में कायम रह सकती है, उतनी बनी हुई है।

मणिपुर में देर से दुरुस्त फैसला

यहां स्कैन करें

चंदन कुमार शर्मा | प्रोफेसर, तेजपुर विवि, असम

उदार छवि के मुख्यमंत्री के साथ-साथ कुकी और नागा समुदाय से उप-मुख्यमंत्री बनाने से यह संकेत गया है कि पहली प्राथमिकता सामान्य स्थिति की बहाली है।

मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ एक लोकतांत्रिक सरकार फिर से कायम हो गई है। इसके साथ ही लगभग एक साल से जारी राष्ट्रपति शासन का अंत हो गया है। दरअसल, राज्य में 13 फरवरी, 2025 को उस समय राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, जब मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर 9 फरवरी, 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर की हिंसा में लगभग 300 लोगों की मौत हुई, हजारों विस्थापित हुए और उनके घर या दूसरी संपत्तियां स्वाहा हो गईं।

इस हिंसा ने राज्य के अलग-अलग नस्लीय समूहों, खासकर मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और पहाड़ियों पर बसने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच गहरी दरार पैदा कर दी है। हिंसा का तात्कालिक कारण मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा 14 अप्रैल, 2023 को दिए एक फैसले से उपजा विवाद था, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी।

बहरहाल, सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र के 62 वर्षीय भाजपाई विधायक खेमचंद सिंह पहले मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और बाद में बीरेन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखा जाता है और अपेक्षाकृत 'उदार मैतेई' चेहरा बताया जाता है। गौर करने लायक बात यह है कि उन्होंने नस्लीय संघर्ष को नियंत्रित करने के बीरेन सिंह के तरीके की आलोचना की थी और कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें शुरू में ही इस्तीफा देने का सुझाव दिया था। उनके इन्हीं विचारों के कारण उनके नेतृत्व में उम्मीद की किरण दिखी हैं। मणिपुर में गहरी हो चुकी नस्लीय खाई को प्रतीकात्मक और राजनीतिक रूप से पाटने के प्रयास के तहत नई सरकार ने सत्ता में साझेदारी की नीति अपनाई है। इसमें कुकी-जो समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी तक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।

मणिपुर में सालों की हिंसा से पैदा हुए दुख व अविश्वास के चलते इस नई राजनीतिक पहल के प्रति नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं की ओर से मिली-जुली और बेहद सतर्क प्रतिक्रियाएं आई हैं। घाटी में मैतेई समुदाय के नागरिक समूहों के बीच लोकतांत्रिक सरकार की बहाली को लेकर नपी-तुली स्वीकृति है। हालांकि, मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (कोकोमी) जैसे संगठन भाजपा के इस कदम को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं और इस कवायद को पार्टी की छवि सुधारने की सियासी पैंतरेबाजी मान रहे हैं। मैतेई समुदाय के इस संगठन ने दिखावा करने के बजाय सुरक्षा और विश्वास-निर्माण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। मैतेई समुदाय का मानना है कि भाजपा की यह नई रणनीति राज्य में चल रहे नस्लीय संघर्ष के ठोस या तत्काल समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं है। फिर भी, मैतेई आबादी के एक हिस्से में इस बात को लेकर उम्मीद है कि एक नया और कम विवादास्पद नेता शासन-प्रशासन के कामकाज में सुधार कर सकता है।

इसके विपरीत, पहाड़ियों पर बसे कुकी-जो समुदाय की प्रतिक्रिया खारिज करने वाली है। इसके नेताओं का तर्क है कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से अलग प्रशासन या केंद्र शासित क्षेत्र की उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती है। कुकी-जो समुदाय मणिपुर में चल रहे इस संकट के लिए पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं। राज्य में मुख्य विपक्षी कांग्रेस भी आलोचनात्मक रही है। उसका तर्क है कि इस बदलाव का राजनीतिक परिदृश्य पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और इस समस्या ने राज्य और केंद्र, दोनों जगह सत्ता में बैठी भाजपा की अक्षमता को उजागर कर दिया है।

बहरहाल, इस पूरे परिदृश्य में नवनियुक्त मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं। उनकी तात्कालिक चुनौतियों में कानून-व्यवस्था बहाल करना, मानवीय संकट से निपटना, बुरी तरह विभाजित राज्य के समुदायों के बीच भरोसा बहाल करना, हजारों विस्थापित लोगों की वापसी और उनका पुनर्वास शामिल है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह इस गहरे तौर पर बंटे हुए समाज में एक भरोसेमंद और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में काम कर पाएंगे? यकीनन, उनकी 'उदार' छवि कुकी-जो समुदाय के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की उम्मीदों और चिंताओं पर भी ध्यान देना व उनका समाधान करना होगा। भाजपा के अंदर, इस बात को लेकर उम्मीद है कि उनका अनुभव और सुलहकुल की छवि राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकती है, लेकिन समुदायों के बीच लगातार अलगाव के माहौल में उन्हें कड़ी निगरानी में काम करना होगा।

खेमचंद सिंह की ताजपोशी विकट परिस्थितियों में 'डैमेज-कंट्रोल' जैसी लग रही है, मगर इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उनका चुनाव इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राज्य का पिछला नेतृत्व अपनी वैधता खो चुका था। अलबत्ता, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उसी पार्टी और राजनीतिक संस्कृति से आते हैं, जिसके दौर में राज्य में अविश्वास का माहौल बना, हिंसा हुई और लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। उनकी नियुक्ति से इतना तो स्पष्ट है कि कुकी-जो समुदाय की अलग प्रशासनिक व्यवस्था जैसी मुख्य राजनीतिक मांग पूरी नहीं होने जा रही है और न ही मूल संघर्ष की राजनीतिक स्थिति में इससे कोई मौलिक बदलाव होने वाला है।

खेमचंद सिंह की नियुक्ति का राजनीतिक निहितार्थ इस संघर्ष को सुलझाने के बजाय शासन को स्थिर करना, राजनीतिक नुकसान को कम करना और संस्थागत चैनलों को फिर से खोलना लगता है। कुकी और नागा समुदाय से उप-मुख्यमंत्री बनाने की कवायद दोनों खेमों के मर्म को सहलाना है, भले ही मणिपुर के भविष्य को आकार देने वाले गहरे राजनीतिक सवाल अभी भी अनसुलझे रहें। इस पहल को राज्य में लंबे समय से नस्लीय अलगाव के बीच समावेशी और साझा सरकार के विचार के रूप में देखा जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लोकतंत्र की सफलता के लिए पढ़ने वाला समाज चाहिए

यहां स्कैन करें

पंकज पराशर | प्राध्यापक, अलीगढ़ मुस्लिम विवि

किसी भी समाज की बौद्धिक स्थिति का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि वहां सूचना के कितने स्रोत उपलब्ध हैं, बल्कि इससे किया जाता है कि लोग उन सूचनाओं को किस गहराई से पढ़ते, समझते और आत्मसात करते हैं। सवाल यह नहीं है कि शब्द कम हो गए हैं, वास्तव में शब्द पहले से कहीं अधिक हैं। सवाल यह है कि क्या उन शब्दों के पीछे विचार भी बचा है?

आज का भारत तकनीकी रूप से अधिक सक्षम है, साक्षरता का दायरा पहले से बढ़ा है और सूचनाओं तक पहुंच अभूतपूर्व रूप से आसान हुई है। इसके बावजूद पढ़ने की आदत में आई गिरावट एक गंभीर सामाजिक संकेत है। लंबे लेख धैर्य की परीक्षा लगने लगे हैं, किताबें समय की बर्बादी समझी जाने लगी हैं और गहराई से सोचने वाली सामग्रियों को अक्सर 'भारी' या 'अप्रासंगिक' कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम शीर्षक और निष्कर्ष पढ़कर अपनी राय बना लेना चाहते हैं, बिना उस वैचारिक प्रक्रिया से गुजरे, जो किसी भी लेखन का वास्तविक उद्देश्य होती है। यह बदलाव केवल जीवन-शैली का नहीं है, मानसिक अनुशासन का है। पढ़ना एक सक्रिय बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके लिए एकाग्रता, समय और आत्म-संवाद की आवश्यकता होती है। जब कोई समाज पढ़ने से बचने लगता है, तो वह धीरे-धीरे गहराई से सोचने से भी कतराने लगता है। ऐसे में, विचार की जगह त्वरित प्रतिक्रिया ले लेती है और संवाद की जगह शोर। यह स्थिति लोकतांत्रिक समाज के लिए शुभ संकेत नहीं कही जा सकती।

क्या हमें ऐसे नागरिक तैयार करने चाहिए, जो केवल सूचना का उपभोग करते हों या ऐसे नागरिक चाहिए, जो विचार करने का साहस रखते हों?

पढ़ने की घटती प्रवृत्ति ने सार्वजनिक बहस की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। आज विमर्श का केंद्र तथ्य या तर्क नहीं, बल्कि प्रभाव व प्रतिक्रिया बन गया है। गहन अध्ययन के बिना बनी राय अक्सर कट्टरता की ओर झुकती है। असहमति संवाद का माध्यम बनने के बजाय टकराव का कारण बन जाती है। लोकतंत्र के लिए यह गंभीर चुनौती बन गई है, क्योंकि लोकतंत्र केवल मतदान से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण संवाद से जीवित रहता है। जब पढ़ना कम होता है, तो समाज में सहनशीलता और संवेदनशीलता भी घटने लगती है। तब 'दूसरा' व्यक्ति या विचार सहज संदेह और विरोध का विषय बन जाता है। इसीलिए पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना केवल शैक्षिक या सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है, यह सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब नागरिक पढ़ते हैं, तब वे केवल सूचित नहीं होते, बल्कि जिम्मेदार भी बनते हैं और जिम्मेदार नागरिक ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।

आज नई पीढ़ी अपनी ही भाषा में लंबे लेख या पुस्तकें पढ़ने से असहज महसूस करने लगी है। शब्दावली सीमित हो रही है, वाक्य छोटे होते जा रहे हैं और अभिव्यक्ति की क्षमता कमजोर पड़ रही है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि समय बदल गया है और पढ़ने के तरीके भी बदलेंगे। यह बात आंशिक रूप से सही हो सकती है। माध्यम बदलना स्वाभाविक है, पर अध्ययन की गहराई का समाप्त हो जाना स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे नागरिक तैयार करें, जो केवल सूचना का उपभोग करते हैं या हमें ऐसे नागरिक चाहिए, जो विचार करने का साहस रखें? तकनीक से दूरी समाधान नहीं है, लेकिन तकनीक के साथ पढ़ने की संस्कृति को जीवित रखना अनिवार्य है। स्कूलों-विश्वविद्यालयों में पठन को फिर से केंद्रीय स्थान देना होगा। पढ़ना केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा न रहकर एक बौद्धिक आदत बने, इस दिशा में प्रयास आवश्यक हैं। घरों में किताबें फिर से बातचीत का विषय बनें, वे केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का साधन न रहें। मीडिया को भी विचारोत्तेजक लेखन के लिए स्थान बनाना उसकी जिम्मेदारी है।

भारत यदि स्वयं को ज्ञान आधारित समाज के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो उसे पाठक आधारित समाज भी बनना होगा। पढ़ना कोई विलास या विशिष्ट वर्ग की आदत नहीं है, यह एक जागरूक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है। जो समाज पढ़ता है, वही सवाल करता है और जो सवाल करता है, वही अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय करता है। अपढ़ समाज में विचार भी धीरे-धीरे मौन हो जाते हैं और विचारों का मौन हो जाना किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपने ही शरीर से गाफिल

जो कुछ इस धरती के साथ होता है, वही आपके साथ भी होता है, क्योंकि अपने भौतिक शरीर में आप इस धरती से अधिक कुछ नहीं हैं। आपका शरीर वही है, जो भोजन आप खाते हैं। आप जो भोजन खाते हैं, वह धरती ही तो है। आप इस धरती की छोटी सी लहराती फसल हैं। इस धरती पर जो होता है, वही आपके साथ भी होता है, बस एकदम सूक्ष्म रूप में।

मैं कुछ वर्षों तक एक फार्म में रह रहा था। वहां पास के गांव में एक व्यक्ति था, जो ठीक से सुन नहीं पाता था। चूंकि वह बमुश्किल ही सुन पाता था, इसलिए लोगों की बातों का जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे में, गांव वाले उसे मूर्ख समझते, उससे अलग-थलग रहते और उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने उसे अपने फार्म पर नौकरी दे दी। वह एक अच्छा साथी था, क्योंकि मैं बातें करना पसंद नहीं करता और वह सुन नहीं पाता था, इसलिए बात भी नहीं करता था। इसलिए, कभी कोई समस्या ही नहीं हुई!

तब बैलों से खेत जोते जाते थे। एक दिन सुबह चार बजे मैंने उसे हल-बैल तैयार करते देखा। मैंने ऊंची आवाज में उससे पूछा, 'क्या कर रहे हो?' उसने कहा, 'मैं जुताई के लिए तैयार हो रहा हूं।' मैंने पूछा, 'जुताई किसकी करोगे, बारिश तो हो नहीं रही?' उसने कहा, 'आज बारिश होने वाली है।' मैंने ऊपर की तरफ देखा। आसमान साफ था। मैंने पूछा, 'कहां है बारिश?' उसने कहा, 'स्वामी, आज बारिश होगी।' उस दिन बारिश हुई।

मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि जो कुछ वह व्यक्ति महसूस कर सका, वह मैं क्यों न कर सका? मैं अपने हाथों को अलग-अलग दिशा में घुमाकर नमी व तापमान का अंदाज लेने लगा, आसमान को पढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने मौसम संबंधी तमाम किताबें पढ़ीं, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने अपने ही शरीर पर गौर किया। इसके बाद मैंने उस सबसे बड़ी भूल का पता लगाया, जो हममें से अधिकतर लोग करते हैं। हम धरती, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्वों को जीवन की प्रक्रिया का जरूरी अंग मानने के बजाय वस्तु के रूप में देखते हैं। इन्हीं तत्वों से तो हमारा शरीर बना है।

लगभग अठारह महीने तक कठोर प्रयास के बाद आखिरकार मैं समझ गया। अब अगर मैं कहता हूं कि बारिश होने वाली है, तो पंचानबे फीसदी बार बारिश होती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि अपनी ही प्रणाली का, धरती का, उस हवा का, जिसे आप सांस में भरते हैं और उन सबका, जो आपके आस-पास है, गहराई से किया गया अवलोकन है। अगर आज बारिश होनी है, तो आपके शरीर में जरूर बदलाव होंगे। शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन कई ग्रामीण लोगों को अनायास ही इसकी जानकारी हो जाती है।

अगर आज बारिश होनी है, तो आपके शरीर में जरूर बदलाव होंगे। ज्यादातर शहरी लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते, पर कई ग्रामीण लोगों को अनायास ही इसकी जानकारी हो जाती है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

इमैनुएल मैक्रों | राष्ट्रपति, फ्रांस

हम विज्ञान में विश्वास करते हैं। चंद माह पहले मैंने दुनिया से यह अपील की थी कि विज्ञान के लिए फ्रांस को चुनिए! मुझे गर्व है कि करीब चालीस विश्व-स्तरीय शोधार्थियों और वैज्ञानिकों ने फ्रांस को चुना है। विज्ञान को भविष्य की अपनी जमीन मिल गई है।

अवरोध की राजनीति में दबता दायित्व

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं होती। वह देश की सामूहिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का आईना भी होती है। अभी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर लोकसभा के भीतर जो कुछ देखने को मिला, उसने इस आईने को धुंधला कर दिया। बार-बार का स्थगन, नारेबाजी, वेल में उतरना और अवरोध की राजनीति, यह सब किसी एक घटना या मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। यह विपक्ष की गहरी वैचारिक बेचैनी का संकेत है।

कांग्रेस की विचारधारा ऐतिहासिक रूप से समावेशी, संस्थागत लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। आज संसद के भीतर कांग्रेस का आचरण यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी अब भी उसी राष्ट्रीय दायित्व-बोध के साथ राजनीति कर रही है या वह तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं को दबाव में लेने की रणनीति अपना चुकी है? व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख की कथित किताब को लेकर कांग्रेस का रुख इसी उलझन को उजागर करता है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल किस मंच पर, किस भाषा में और किस उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं? जब सदन में चर्चा के बजाय हंगामा प्राथमिक हथियार बन जाए, तो संदेश सरकार तक कम और जनता तक ज्यादा जाता है। संदेश यह होता है कि विपक्ष के पास तर्कों से अधिक शोर है। मुद्दों की गंभीरता को नारेबाजी की तीव्रता से मापा जाने लगा। चीन सीमा विवाद जैसा संवेदनशील विषय हो या एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता, इन पर राष्ट्रीय हित के व्यापक फ्रेम में बात करने के बजाय विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने तक सीमित रह जाता है। इससे यह धारणा बनती है कि उसका फोकस देश की रणनीतिक स्थिति पर कम और राजनीतिक बढ़त लेने पर अधिक है।

देश के प्रति निष्ठा केवल सरकार के समर्थन या विरोध से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कठिन मुद्दों पर देश को कितना भरोसा दिया जा रहा है। जब संसद में सेना, कूटनीति या अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे विषयों पर चर्चा होती है, तो विपक्ष से यह अपेक्षा होती है कि वह सवाल पूछे, विकल्प रखे और सरकार को जवाबदेह बनाए, लेकिन जब वही विपक्ष इन मुद्दों को सदन ठप करने का माध्यम बना ले, तो राष्ट्रीय विमर्श कमजोर पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह संसद को संघर्ष का अखाड़ा नहीं बनाए, बल्कि विचारों का मंच बनाए।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
संसद में शोर

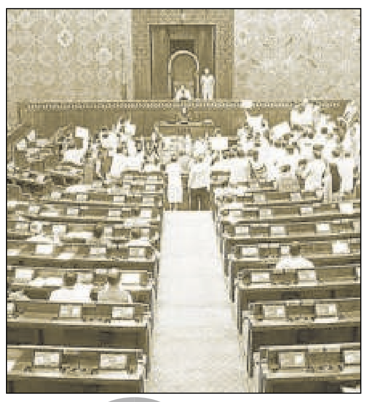

सवाल लोकतंत्र, संप्रभुता और रणनीति का

भारत-अमेरिका डील देश में विवादों और सवालों के घेरे में है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही और प्रधानमंत्री का संबोधन स्थगित किया जाना इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ व्यापार नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संप्रभुता और राजयनिक रणनीति से जुड़ चुका है।

इस समझौते को लेकर सबसे पहला और तीखा सवाल प्रक्रिया और पारदर्शिता का है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस डील की घोषणा भारत की संसद से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुई। ऐसे में, सवाल स्वाभाविक है कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, तब उसकी पूरी जानकारी पहले संसद के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? सरकार ने केवल संक्षिप्त बयान देकर औपचारिकता पूरी की, जबकि मूल दस्तावेज, शर्तें, अपवाद और सुरक्षा के उपाय संसद से साझा नहीं किए गए। आपत्ति केवल राजनीतिक शोर नहीं है, बल्कि भारत की संसदीय परंपरा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। अतीत में चाहे डब्ल्यूटीओ समझौते हों, परमाणु करार हो या यूरोपीय संघ के साथ एफटीए, हर बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते पर संसद में विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसे में, विपक्ष का यह पूछना कि डील का 'टेक्स्ट आधारित विवरण' क्यों नहीं दिया गया, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के दायरे में आता है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़कर देख रहा है, इसीलिए विरोध उग्र हुआ।

दूसरा बड़ा विवाद कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर है। टैरिफ कटौती का सीधा लाभ अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी और अन्य संवेदनशील वस्तुओं को मिलेगा, जिससे भारतीय बाजार में उनकी आसान पहुंच हो सकती है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का आधार है। छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पहले ही महंगाई, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में, यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा भारतीय किसानों को और कमजोर कर सकती है। विपक्ष ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। क्या इस डील के तहत भारत ने अपनी ऊर्जा नीति से किसी तरह का नकारात्मक समझौता किया है?

इसका विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026 केवल टैरिफ कटौती का मामला नहीं है। यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता, घरेलू राजनीति, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा व भू- राजनीतिक समीकरणों का संगम है। विपक्ष के सवाल लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए जरूरी हैं।

किशन भावनानी, टिप्पणीकार

बगैर ब्रेक काम बीमारी को बुलावा

भारत में 60 फीसदी कर्मचारी बर्नआउट के शिकार हैं। बर्नआउट यानी कामकाज से उपजा अनियंत्रित तनाव। दुनिया भर में यह तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर समय रहते ध्यान न देना युवाओं को बीमार ही नहीं, भावनात्मक स्तर पर भी कमजोर बना सकता है। बर्नआउट सिंड्रोम से कैसे बचें, बता रही हैं शमीम खान

गायक अरजीत सिंह, कॉमेडियन जाकिर खान और गायिका नेहा कक्कड़... हाल में इन तीनों द्वारा करिअर के सफल मुकाम पर पहुंचकर काम से ब्रेक लेने की खबरें चर्चा में रहीं। इसने एक बार फिर से कामकाजी लोगों में बढ़ते तनाव और बर्नआउट के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। बात महज सेलिब्रिटीज की नहीं है। बीस से पच्चीस साल के युवा अच्छे पैकेज, ऊंचे पद व सुविधाओं के पीछे दौड़ते हुए अपनी सेहत और निजी जीवन दांव पर लगा रहे हैं। इतना कि एक सीमा के बाद उनके लिए अपने मनपसंद काम को करना ही मुश्किल हो जाता है। मैकिंजे हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार, दुनियाभर में 20 प्रतिशत कर्मचारी बर्नआउट की शिकायत करते हैं। वहीं भारत में यह आंकड़ा कहीं अधिक है।

गंभीर स्थिति बर्नआउट सिंड्रोम

बर्नआउट एक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना थक जाता है कि कार्य में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। बर्नआउट के शिकार अक्सर वो लोग और पेशेवर होते हैं, जो काम को ही अपना जीवन बना लेते हैं। पहले बर्नआउट को अत्यधिक थकान की स्थिति माना जाता था, अब इसे सिंड्रोम की संज्ञा दी गई है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार बर्नआउट तनाव की वो गंभीर स्थिति है, जिसका रणनीति बनाकर सही तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए। विभिन्न शोधों के अनुसार लगातार तनाव में रहना हार्मोन्स विशेषकर कार्टिसोल और मेलेटोनिन के संतुलन को प्रभावित करता है। समय के साथ तनाव से लड़ने की क्षमता, ऊर्जा, नींद और इम्यूनिटी कम होने लगती है। हृदय और पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है।

50 प्रतिशत कर्मचारी भारत में बर्नआउट और असंतोष के कारण नई नौकरी की तलाश करते हैं, गैलप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार। एक अन्य अध्ययन के अनुसार हर तीन में से एक कर्मचारी तनाव की अधिकता और नींद की कमी से जूझ रहा है।

बर्नआउट से ऐसे बचें

नींद से समझौता नहीं
- 7-9 घंटे की नींद जरूरी।
- आराम को विलासिता न समझें।

लाभ: कार्यक्षमता बेहतर होगी। समग्र सेहत के लिए बेहद जरूरी।

प्राथमिकताएं तय करें
- जरूरी काम पहले करें।
- अपनी क्षमता का ध्यान रखें।
- मल्टीटास्किंग से बचें।

लाभ: जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। तनाव कम रहेगा। गलतियां कम होंगी।

काम के दौरान माइक्रो ब्रेक लें
- ब्रेक के दौरान शरीर हिलाएं-डुलाएं। सीट से खड़े हो जाएं। फोन न देखें।

लाभ: उत्पादकता बढ़ेगी। तन-मन तरोताजा रहेंगे।

डिजिटल डिटॉक्स जरूरी
- स्क्रीन से नियमित ब्रेक लें। सोशल मीडिया कम देखें।
- अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद रखें।

लाभ: मानसिक थकान में कमी, एकाग्रता में सुधार और मूड पर बेहतर नियंत्रण रहेगा।

शरीर का ध्यान रखें
- नियमित व्यायाम करें।
- पौष्टिक भोजन खाएं। खूब पानी पिएं, समय पर खाएं-पिएं।
- सही उपचार में देरी न करें।
- नशीली चीजों से दूर रहें।

लाभ: भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी।

मजबूत रिश्ते बनाएं
- दूसरों की मदद करें।
- सहकर्मियों के अच्छे काम की प्रशंसा करें।
- दूसरों को सुनें, उनकी सुविधा का ध्यान रखें।

लाभ: अकेलेपन से बचेंगे। काम का माहौल सकारात्मक रहेगा।

समय रहते मदद लें
- परिवार के सदस्यों व मित्रों से बात करें
- थेरेपी, काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन के गुर सीखने के लिए पेशेवर से मिलें।

लाभ: शुरू में ही स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

सफलता को नए सिरे से परिभाषित करें
- सफलता को केवल पैसे या पद तक सीमित न रखें।
- अपनी खूबियों पर ध्यान दें, नया सीखें, तुलना न करें।

लाभ: मानसिक शांति रहेगी और व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी।

बर्न आउट थर्मामीटर

नीचे दिए गए सवालों पर खुद को एक से पांच तक नंबर दें:
- आपको लगता है कि आराम करना आपके लिए मुश्किल है?
- हर समय भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं?
- इन दिनों नींद आने में परेशानी होती है?
- क्या सिरदर्द, पाचन समस्याएं और दर्द ज्यादा रहता है?
- आप जीवन में मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं?
- याददाश्त कमजोर हो रही है, फोकस नहीं कर पाते?
- आप जॉब छोड़ने या अपने आज से भागने के बारे में सोचते हैं?
- अपने काम से संतुष्टि नहीं मिलती?
- काम के कारण आपका निजी जीवन प्रभावित हो रहा है?
- काम में सुधार के लिए ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं?

क्या कहता है स्कोर?

0-10	आपकी स्थिति सामान्य हैं।
11-20	आपको काम के बीच में माइक्रो-ब्रेक लेने और पर्याप्त आराम की जरूरत है।
21-30	आपके जीवन की लय गड़बड़ा रही है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएं।
31-40	आप बर्नआउट के शिकार हैं। एक लंबे ब्रेक पर जाने और पेशेवर रणनीतियों में ठोस बदलाव करें।
41-50	आपकी स्थिति बहुत गंभीर है। आपको उपचार की जरूरत है।

इन संकेतों पर रखें नजर
- चीजों के मायने खत्म हो जाना।
- बिना काम किए भी थके हुए रहना।
- काम करने के लिए प्रेरणा की कमी।
- काम समय पर पूरा करने में दिक्कत होना।
- अचानक गुस्सा व चिड़चिड़ापन बढ़ना।
- शरीर में दर्द बढ़ना, बार-बार बीमार पड़ना।
- दूसरों से भावनात्मक लगाव में कमी आना।
- सहकर्मियों से रिश्ते प्रभावित होना।
- कमजोर और असहाय महसूस करना।
- नींद न आना, नींद आने में परेशानी होना।

दिल, दिमाग समेत पूरे शरीर पर असर
- हार्मोन असंतुलन के कारण 'ब्रेन-गट एक्सिस' प्रभावित, इसके कारण पाचन समस्याएं होती हैं। मूड स्विंग्स, अनिर्णय की स्थिति, उदासी और नींद संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं।
- मांसपेशियों में दर्द रहने के अलावा हृदय रोग, मोटापा, हाईबीपी, शुगर आदि मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ता है।
- नशीली चीजों की लत का खतरा।

3 एसः काम करने का सही तरीका
स्टेनफोर्ड एन्वायर्नमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी (एसईएचएस) ने कर्मचारियों को काम के दौरान माइक्रो ब्रेक्स लेने की सिफारिश की है। इसके अनुसार ये छोटे-छोटे ब्रेक शरीर को आराम पहुंचाते हैं और मस्तिष्क को तरोताजा रखते हैं। एसईएचएस ने विश्वभर के कर्मचारियों के लिए एक आदर्श वर्क पैटर्न भी दिया है। जिसमें 8 घंटे की वर्क शिफ्ट को साढ़े सात घंटे काम और आधे घंटे के लंच ब्रेक में बांटा गया है। 7.5 घंटे के काम करने की अवधि को 30-30 मिनट के 15 भागों में बांटा है।

3 एस यानी स्टैंडिंग, सिटिंग और स्ट्रेचिंग: 30 मिनट के हर भाग को ऐसे बांटें:
- **20** मिनट बैठकर काम करें।
- **8** मिनट खड़े होकर
- **2** मिनट का ब्रेक लें, जिसमें स्ट्रेचिंग करें।

इस पैटर्न को अपनाने पर आप 7.5 घंटे की अवधि में 5 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे खड़े होंगे, 30 मिनट शरीर को हिला-डुला सकेंगे।

सवाल-जवाब

ज्यादा सांस फूलने पर दिल की जांच जरूरी

डॉ. पुलिन गुप्ता
प्रोफेसर (मेडिसिन), राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली

सवाल: मेरी मां की उम्र 78 साल है। 2012 में हृदयाघात के कारण स्टेंटिंग हुई थी। दवा चल रही है। सीवीसी टेस्ट में प्लेटलेट्स काउंट 60 हजार आए हैं, तीन दिन से सांस भी फूल रही है। उनके प्लेटलेट्स 90000 से ज्यादा नहीं होते। क्या करें?

जवाब: अगर किसी मरीज के प्लेटलेट्स 90 हजार के आसपास रहते हैं और उन्हें किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कई मरीजों में प्लेटलेट्स सामान्य तौर पर कम ही रहते हैं। इतना जरूर है कि अगर इन मरीजों में किसी सर्जरी की जरूरत होती है, तो उससे पहले प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाना जरूरी होता है। अब अगर उनके प्लेटलेट्स 60000 हैं, तो टेस्ट करके पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है। बोन मैरो टेस्ट की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है। प्लेटलेट्स कम होने से सांस नहीं फूलती। अगर सांस फूल रही है, तो उनमें खून की कमी है या फिर, उनकी समस्या के अनुसार यह देखना होगा कि दिल कमजोर तो नहीं हो रहा है। इसके लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। वे कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। इको टेस्ट में देखना होगा कि कार्डिएक पंपिंग कम तो नहीं हो रही है। कुछ दवाएं आती हैं, जो यूरिन अधिक निकालती हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं। इससे सांस फूलने में आराम आता है। पर लगातार सांस फूल रही है, तो यह एंजाइना इक्विलिब्रियम हो सकता है। बेहतर है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं।

सवाल: मेरी पत्नी की उम्र 62 साल है, कद 5.4 है। पिछले 14 साल से उन्हें रेस्टलेस लेग की समस्या है। उन्हें बीपी, शुगर और थायरॉइड नहीं है। घुटनों में दर्द रहता है। हाल में पथरी के लिए गॉल ब्लेडर सर्जरी हुई है। उसके बाद से वो कमजोर हो गई हैं। रेस्टलेस लेग के लिए बीते साल न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज चला था। एक साल से उन्हें आराम था। अब यह समस्या दोबारा होने लगी है। इस कारण रात में नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है। अब क्या करना चाहिए? क्या वही दवाएं फिर से ले सकते हैं?

जवाब: आमतौर पर महिलाओं में पैरों की दर्द की समस्या मेनोपॉज यानी 45 से 50 की उम्र में होती है। या फिर जिन महिलाओं को लंबे समय से डायबिटीज है, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। उन्हें अन्य कोई समस्या नहीं है। गॉल ब्लेडर की सर्जरी से रेस्टलेस लेग की समस्या का कोई संबंध नहीं है। जहां तक घुटने की बात है, यह उम्र संबंधी है। बेहतर है कि वे व्यायाम करें, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। रेस्टलेस लेग के कारण रात में नींद न आना, बेचैनी व पैर में ऐंठन हो जाती है। इसके लिए दवाएं दी जाती हैं। एक बार आराम आने के बाद यह समस्या फिर से भी हो सकती है। आप खुद से पहली वाली दवाएं शुरू न करें, यह समस्या कुछ और भी हो सकती है। यह लक्षण उनमें भी दिखते हैं, जो ज्यादा चिंता करते हैं या फिर जिन्हें बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती। आप डॉक्टर को दिखाएं। मनोचिकित्सक से मिलें।

सवाल: मुझे एक पैर में सेल्युलाइटिस की समस्या है। इसका क्या उपचार है?

सेल्युलाइटिस की समस्या आमतौर पर उन्हें होती है, जिनके पैरों में बहुत सूजन रहती है, जैसे फाइलेरिया या डीवीटी। सूजन के कारण त्वचा के निचले टिश्यू में संक्रमण हो जाता है, इसे सेल्युलाइटिस कहते हैं। आमतौर पर यह बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, जिसके लिए मरीज को तुरंत एडमिट किया जाना चाहिए। उन्हें अच्छी एंटीबायोटिक दी जाती है। कई बार जो हिस्सा खराब हो गया है, उसे अलग करने के लिए सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर किसी को यह समस्या है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि संक्रमण ज्यादा न बढ़े।

भेजें अपने सवाल
सेहत से जुड़े सवाल tanmanhindustan@gmail.com पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

दिमाग में हो जब हर समय खाने का शोर

क्या है 'फूड नॉइज?' क्यों मोटापे से जूझ रहे लोग खाने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं?

क्या पेट भरा होने के बावजूद दिमाग बार-बार खाने के बारे में सोचता रहता है? या हर समय खाने की ललक होती है। खाने की तस्वीरें और स्वाद दिमाग से जाता नहीं? अगर हां, तो यह इच्छाशक्ति की कमी नहीं है, इसे 'फूड नॉइज' कहा जाता है। ब्रिटेन में सर्जन व हेल्थ कंटेंट क्रिएटर डॉ. करण राजन के मुताबिक, फूड नॉइज भूख से अलग है। यह पेट से नहीं, दिमाग से जुड़ा मामला है। आपका पेट भरा है, तो भी दिमाग खाने के बारे में सोचता रहता है।

मोटापा व फूड नॉइज का संबंध

डॉ. राजन के अनुसार, 'फूड नॉइज' की समस्या मोटापे से जूझ रहे लोगों में अधिक देखी जाती है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि जब मोटापे से ग्रसित व्यक्ति भोजन की तस्वीरें देखते हैं, तो उनके दिमाग का रिवार्ड सेंटर्स सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में ज्यादा सक्रिय हो जाता है।

हार्मोन और दिमाग का खेल

फूड नॉइज केवल भूख का मामला नहीं है। इसमें कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं- डोपामाइन हार्मोन, आंतों के हार्मोन जैसे जीएलपी-1, पीवाईवाई और घ्रेलिन, तनावकारी हार्मोन कोर्टिसोल, गट माइक्रोबायोम, जेनेटिक्स इन सबकी इसमें भूमिका देखने को मिलती है। यही कारण है कि शारीरिक भूख खाने से शांत हो जाती है, लेकिन फूड नॉइज खाने के बाद भी बना रहता है।

डॉ. राजन के अनुसार, जीएलपी-1 आधारित उपचार से सिर्फ भूख कम नहीं होती, बल्कि खाने के बारे में सोचने की तीव्रता भी घटती है।

इन तरीकों से मिलेगी राहत
- उच्च फाइबर व प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। इससे भूख काबू करने वाले हार्मोन संतुलित रहते हैं। अत्यधिक डाइटिंग से बचें।
- ज्यादा रोक-टोक खाने की ललक को ज्यादा बढ़ा सकती है।
- नियमित समय पर भोजन करें।
- अच्छी नींद लें। नींद की कमी भूख और क्रेविंग दोनों बढ़ाती है।
- तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें।

त्वचा के तीन दुश्मन

अगर आप त्वचा की सही देखभाल के बावजूद त्वचा समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो अपने खानपान पर ध्यान दें। खासकर इन तीन चीजों को शामिल करने से बचें:

1 फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप
- **स्रोत:** सोडा, पैकेज्ड जूस, बिस्कुट और जंक फूड में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह एक सिंथेटिक शुगर है।

नुकसान: यह सामान्य चीनी की तुलना में त्वचा को 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह शरीर में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स (एजीई) बनाता है। यह त्वचा से कोलेजन को खत्म करता है, इससे त्वचा सख्त हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां जल्दी आती हैं। यह लिवर के लिए भी बेहद हानिकारक माना जाता है।

2 बार-बार गर्म किया गया रिफाइंड तेल
- **स्रोत:** सड़क किनारे बेची जाने वाली तली-भुनी चीजें, गहरे तले हुए स्नैक्स (जैसे समोसा, पकौड़े) में।
- **नुकसान:** तेल को बार-बार गर्म करने से उसमें मौजूद विटामिन-ई खत्म हो जाता है। बचा हुआ 'ऑक्सीडाइज्ड फैट' शरीर और त्वचा में अंदरूनी सूजन पैदा करता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा आता है।

3 कुरकुरी और ज्यादा तली हुई चीजें
- **स्रोत:** फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और पकौड़े जैसे सुनहरे-भूरे या ज्यादा कुरकुरे खाद्य पदार्थ।
- **नुकसान:** भोजन जितना ज्यादा कुरकुरा होगा, उसमें एक्रिलामाइड और एजीई की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ये तत्व त्वचा की संरचना को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं और कोलेजन को तोड़कर त्वचा के कसाव को कम करते हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

वृष: मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन: मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति रहेगी, परंतु सेहत के प्रति सचेत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सुधार होगा।

कर्क: मन परेशान रहेगा। संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह: वाणी में मधुरता तो रहेगी, लेकिन मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

कन्या: मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है।

तुला: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। यात्रा के योग हैं।

वृश्चिक: मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी बहुत रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव तथा साज-सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे।

धनु: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं।

मकर: आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। लाभ के अवसर बढ़ेंगे।

कुंभ: मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। माता का साथ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी।

मीन: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में बाधा आ सकती है। सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव आ सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

06 फरवरी, शुक्रवार, **शक संवत्:** 17 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 24 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 17 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन कृष्ण पंचमी तिथि रात्रि 01.19 बजे तक पश्चात षष्ठी तिथि, हस्त नक्षत्र रात्रि 12.24 बजे तक पश्चात चित्रा नक्षत्र, कौलव करण, चंद्रमा कन्या राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रात: 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

फार्मिंग से जुड़ी वस्तुओं को किस दिशा में रखें? -राज किशोर सिंह, बलिया
- **ट्रैक्टर शेड एवं भारी मशीनरी:** ये चीजें फार्म के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिएं, जिससे वास्तु के अनुसार भार का संतुलन बना रहे।
- **बेल एवं कृषि उपकरण:** यह फार्म की पश्चिम दिशा में रखना बेहतर रहता है।
- **गाय का शेड:** यह उत्तर पश्चिम दिशा में उपयुक्त रहता है। यहां हवा का आवागमन ठीक रहता है, जिसके कारण बदबू आदि ज्यादा देर तक नहीं रहती।
- **बायो गैस प्लांट:** इसे पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनाना ठीक रहता है।
- **सौर ऊर्जा पैनल:** इनको फार्म के दक्षिण या पश्चिम भाग में रखना उचित रहता है।

वर्ग पहेली: 8232

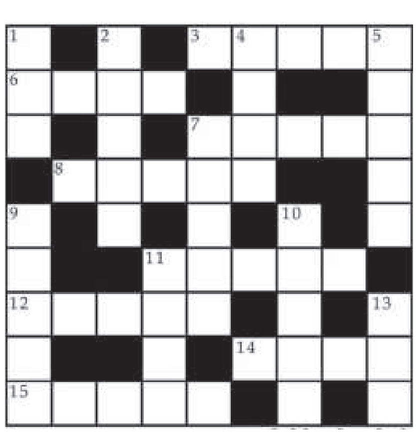

बाएं से दाएं
3. सबसे निकट; सबसे पास; सबसे समीप (5)
6. अविरामता; गट-गट की आवाज के साथ; जल्दी-जल्दी पीने का कार्य (4)
7. गंभीर होना; तल नीचे होना; थाह काफी नीचे होना; गाढ़ा होना (3,2)
8. मतदान के बाद की जाने वाली मतों की गिनती (5)
11. जो खाने-पीने में अच्छा लगे; जायके वाला; रसीला; स्वादिष्ट (5)
12. अश्लील; लज्जाकर; शर्मनाक; शर्मिंदा करने वाला (5)
14. ऊंचे स्वर में संबोधन करना; आवाज देना; बुलाना (4)
15. नाम रखा जाना; नाम रखने का काम (5)

ऊपर से नीचे
1. निर्जन स्थान; आखेट स्थल; अरण्य; वन (3)
2. समुद्र तट; सागर का किनारा; सागर तीर (3,2)
4. पीड़ा के कारण मुंह से शब्द निकालना; कांखना (4)
5. मरने वाला; मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ (5)
7. दलनायक; गणस्वामी; गणेश; शिव (5)
9. कुटैव का शिकार होना; दुर्व्यसन में पड़ना; बुरी आदत लगना (2,3)
10. किसी पद पर नियुक्त अधिकारी; पदस्थ व्यक्ति; ओहदेदार (5)
11. जंतु; पशु (4)
13. तानने का भाव, खिंचाव; रस्सी (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली: 8231

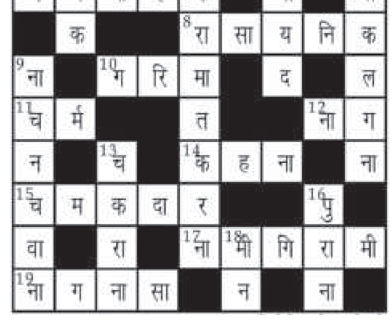

सुडोकू: 8214
*कठिन

9					6	2		
	8	1		7			5	3
7				5				
		2			8		1	
	6		1			3		
				8				5
1	7			4		9	6	
		8	7					1

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू: 8213

4	8	5	2	7	3	6	9	1
9	3	6	8	4	1	2	5	7
2	1	7	9	6	5	4	3	8
5	4	2	6	3	7	1	8	9
6	7	3	1	9	8	5	2	4
1	9	8	5	2	4	3	7	6
8	5	4	3	1	9	7	6	2
7	6	9	4	5	2	8	1	3
3	2	1	7	8	6	9	4	5

अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ■ आगरा
नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 6 फरवरी 2026

निजता बिकने के लिए नहीं है। डर या लालच के कारण उससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। -पावेल ड्यूरोव

शुचिता और सवाल

आज संसद को ऐसा दिन देखना पड़ा, जब विपक्ष की नारेबाजी और वॉकआउट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर जवाब दिया और उससे पहले लोकसभा में भारी शोर-शराबे के बीच उनके भाषण के बगैर ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। सरकार और विपक्ष के बीच यह तनातनी संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और गरिमा के लिहाज से अत्यंत क्षोभजनक और चिंताजनक भी है। उल्लेखनीय है कि 2004 के बाद यह पहली बार है, जब यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बगैर पारित हुआ है। विपक्ष के सवाल उठाने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर वे अवसर, सांविधानिक मूल्यों और संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप हों। ऐसा होने पर सरकार भी उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य होगी। बेवजह के हंगामे में मूल प्रश्न तो खो ही जाते हैं, सदन का कीमती समय भी नष्ट होता है। संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना दोनों सदनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री बहस के अंत में जवाब देते हैं, जिसमें वे सरकार की उपलब्धियों का बचाव करते हैं, विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हैं और भविष्य की दिशा स्पष्ट करते हैं। यह न केवल सदन की कार्यवाही को पूर्णता प्रदान करता है, बल्कि जनता को भी सरकार और विपक्ष, दोनों की स्थिति समझने का अवसर देता है। संसद को चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, पर सही मायनों में सदनों का सुचारु संचालन सरकार और विपक्ष, दोनों से परिपक्वता की मांग करता है। शोर-शराबा और वॉकआउट संसद को कमजोर ही करते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है, और ऐसी तस्वीरें देश-विदेश में लोकतंत्र की छवि को धूमिल तो करती ही हैं, संसदीय संस्कृति के क्षरण की ओर भी इशारा करती हैं। संसदीय लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब सभी दल नियमों का पालन करें, एक-दूसरे का सम्मान करें और जनहित को सर्वोपरि रखें। विपक्ष की भूमिका

सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, न कि सदन को ठप करना। दोनों को मिलकर ही संसद की गरिमा बहाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और प्रधानमंत्री का जवाब लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है। अगर यह बाधित हो रहा है, तो यह सरकार और विपक्ष, सभी के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। मूल सवाल संसद की शुचिता का है, वरना एकतरफा बहिष्कार और संवादहीनता की स्थिति कहीं नहीं ले जाएगी।

पारदर्शिता तो बरतनी ही होगी

जब तक व्हाट्सएप पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को आश्वस्त नहीं कर देता कि वह लोगों का डाटा इस्तेमाल नहीं करता, तब तक यह कैसे मान लिया जाए कि वह सच बोल रहा है? ऐसे में हम एक बड़े तकनीकी दिग्गज की मनमर्जी के गुलाम न बन जाएं, इसलिए पारदर्शिता की मांग जरूरी है।

व्हाट्सएप को क्या भारत छोड़ना पड़ेगा? और यदि ऐसा हुआ, तो बिन व्हाट्सएप जीवन कैसा होगा? परिवार के लोगों से वीडियो कॉल से लेकर ऑफिस ग्रुप तक, आप चाहें भी तो व्हाट्सएप नहीं छोड़ सकते। इसने जीवन सरल तो बनाया ही है। शायद इसीलिए बहुत तेजी से यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैसेंजर बनकर उभरा। लेकिन फेसबुक की कंपनी मेटा द्वारा खरीद लिए जाने के बाद से यही व्हाट्सएप अब शक के घेरे में है। आइए, पूरा इतिहास जानते हैं। वह साल था 2009। जैन कौम और ब्रायन एक्टन नाम के दो याहू कर्मचारियों ने एक मैसेजिंग सर्विस के रूप में व्हाट्सएप की परिकल्पना की। फोन में इंटरनेट आ जाने की वजह से साल भर में ही व्हाट्सएप लोगों के फोन में आने लगा। चूंकि एसएमएस के लिए पैसे लगते थे, तो लोगों ने संदेश व्हाट्सएप पर भेजना शुरू किया। कंपनी के लॉन्च के पांच साल के अंदर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की नजर व्हाट्सएप पर पड़ी। उन्होंने 21.8 अरब डॉलर में व्हाट्सएप खरीद लिया।

संकेत उपाध्याय
वरिष्ठ पत्रकार

उनकी कंपनी ने वादा किया कि लोगों की निजता सर्वोपरि होगी। व्हाट्सएप के संस्थापक भी फेसबुक से संतुष्ट ही दिखे, क्योंकि विलय के बाद भी वह व्हाट्सएप से जुड़े रहे, लेकिन 2018 में मोनेटाइजेशन एवं डाटा प्राइवेसी पर चिंता व्यक्त करते हुए एक संस्थापक अपनी ही कंपनी में से निकल गए। सोचिए जरा, जब फेसबुक ने 21.8 अरब डॉलर में व्हाट्सएप खरीदा, तो खैरात के लिए तो नहीं ही खरीदा होगा। व्हाट्सएप फेसबुक के लिए एक व्यवसाय था। और यह व्यवसाय था डाटा का।

चूंकि इसे हर कोई अपने फोन में इस्तेमाल करता है, तो फेसबुक ने इतनी जानकारी के चलते इसे पैसे कमाने की मशीन समझ लिया और अपने वादे से पलट गया। उसने वादा किया था कि व्हाट्सएप पर लोगों की जानकारी लोगों तक ही सीमित रहेगी। लेकिन 2021 में फेसबुक ने अपनी पॉलिसी बदल दी। कोविड के दौर में लोग व्हाट्सएप पर और निर्भर हुए। बदली हुई पॉलिसी के मुताबिक, व्हाट्सएप इजाजत मांग रहा था कि आपकी कुछ जानकारी फेसबुक और कंपनी के अन्य भाग के

साथ साझा की जाए। इसका मकसद विज्ञापन से पैसा कमाना था। फिर क्या था, भारत समेत दुनिया भर में हंगामा मच गया। हिंदुस्तान में खास तौर से यह बात कही जाने लगी कि व्हाट्सएप ने अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया है। 2021 में आए शुरुआती मैसेज में व्हाट्सएप ने कहा, या तो पॉलिसी मानो, नहीं तो एक निर्धारित तारीख के बाद अकाउंट नहीं चलेगा। लोगों को लगा कि यह उनकी निजता पर हमला है और यह मजबूरी का फायदा उठाना है। हंगामा हुआ तो व्हाट्सएप यह बताने पर मजबूर हुआ कि सिर्फ कुछ सतही जानकारी ही साझा करेंगे। आपके मैसेज के अंदर हम नहीं घुस रहे। यहां तक कि मैसेज एंड-टू-एंड एंक्रिप्टेड हैं। मतलब व्हाट्सएप अगर चाहे भी, तो उसे नहीं पढ़ सकता। दबाव में आकर व्हाट्सएप ने शर्त मानने की तारीख हटा दी, पर लगातार लोगों को नोटिफिकेशन भेज कर याद दिलाता रहा।

इस बीच यह मामला भारत की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) में चला गया। सीसीआई की जांच 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2024 में आदेश आया। सीसीआई ने माना कि व्हाट्सएप और फेसबुक (मेटा) अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। उसने 213 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक महीने बाद व्हाट्सएप एनसीएलएटी में अपील लेकर गया। नवंबर 2025 में मेटा-व्हाट्सएप को कुछ मामलों में राहत तो मिली, लेकिन जुर्माना भरने के लिए अब भी कहा गया। जनवरी 2026 में व्हाट्सएप ने इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि राहत मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने सीधे कहा-देश का कानून नहीं मान सकते, तो भारत छोड़ दीजिए। दरअसल, सारा मामला दावे का है। व्हाट्सएप का दावा है कि वह आपका-मेरा निजी डाटा किसी से साझा नहीं करता। लेकिन कोर्ट में जिरह कर रहे लोगों का कहना है कि दुनिया भर से प्रमाण है कि मेटा-व्हाट्सएप डाटा का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए करता है। सबसे बड़ी समस्या यहां पारदर्शिता की कमी की है। व्हाट्सएप का निजता संरक्षण का दावा तब तक दावा ही रहेगा, जब तक कि प्रमाणित न हो जाए कि वह सच बोल रहा है। खास तौर से तब, जब भारत में दो एजेंसियों ने उसे दोषी पाया और दंडित किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो मामले और हैं। वियना यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक, व्हाट्सएप के 3.5 अरब उपभोगता हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 75 करोड़ भारत में हैं। इस रिसर्च ने यह पाया है कि व्हाट्सएप पर तस्वीर, स्टेटस और अबाउट सेक्शन लीक हो सकता है, क्योंकि कंटेंट डिस्कवरी फीचर में समस्या है। व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अमेरिका में ही आई। सेन फ्रांसिस्को की एक अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के कर्मचारियों के पास अरबों व्हाट्सएप ग्राहकों की निजी बातचीत का डाटा है। जी हां, वही जानकारी, जिसके लिए व्हाट्सएप कहता है कि यह एंड-टू-एंड एंक्रिप्टेड है। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट्सएप का यह दावा कि -आपकी तरफ से दिया संदेश और दूसरी तरफ प्राप्त संदेश सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं-गलत हो सकता है।

कोर्ट में जिरह कर रहे लोगों का कहना है व्हाट्सएप कंपनी के पास इतना ऑनलाइन स्पेस है कि वह सबका निजी डाटा स्टोर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि व्हाट्सएप ने इसे निराधार बताया है। बात घूम-फिर कर वहीं आती है। जब तक व्हाट्सएप पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को आश्वस्त नहीं कर देता कि वह लोगों का डाटा इस्तेमाल नहीं करता, तब तक यह कैसे मान लिया जाए कि वह सच बोल रहा है? ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी व्हाट्सएप अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो क्या हम वाकई व्हाट्सएप मुक्त भारत हो जाएंगे?

सवाल यहां विकल्प का भी है। यह एप इतना बड़ा हो गया है कि इसके टक्कर में और कोई है ही नहीं। व्हाट्सएप अगर तीन अरब से अधिक लोगों के पास है, तो टेलीग्राम एक अरब और सिग्नल सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास। भारत सरकार खुद अपने सरकारी संवाद के लिए व्हाट्सएप जैसा एक मैसेंजर लाना चाहती थी, लेकिन आम जनमानस तक इसे उतारा नहीं गया है। ऐसे में आप और हम एक बड़े तकनीकी दिग्गज की मनमर्जी के गुलाम न बन जाएं, इसके लिए पारदर्शिता की मांग ही सबसे सही राह है।

edit@amarujala.com

मुद्दा

जाएं तो जाएं कहां...

सौ फीसदी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग व स्वच्छ शौचालय के मामले में आंकड़े आश्वस्त करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति वैसी ही हो, तभी तस्वीर बदल सकेगी।

हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वहां के मुख्य सचिव को स्कूलों में स्वच्छता को लेकर कड़ी फटकार लगाई-'आप स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं बनवा पा रहे हैं...अफसरों को शर्म आनी चाहिए कि बच्चियां इसलिए पानी नहीं पी पातीं, क्योंकि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं हैं और वे वहां जा नहीं सकतीं। ऐसे में अदालत बच्चों व समाज को जवाब नहीं दे पा रही है...।'

इसी तरह हरियाणा के स्कूलों में शौचालयों की हालत पर पिछले साल आई पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भी गौरतलब है-'सरकार कोर्ट के सामने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। धरातल पर कोई काम नहीं कर रही।' हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक हफ्ते के अंदर सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए योजना पेश करने का आदेश दिया था। यह केवल राजस्थान या हरियाणा की स्थिति नहीं है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई +) की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 14.71 लाख स्कूलों में से 39,729 में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। हरियाणा में 767 स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय या तो हैं नहीं या फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं। पंजाब में 188 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं और 191 स्कूलों में शौचालय काम नहीं कर रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा में 100 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय होने की सूचना दी गई है, जबकि यह आंकड़ा पंजाब में 99.5, हिमाचल में 99, उत्तर प्रदेश में 98.3, हरियाणा में 97.3 और उत्तराखंड में 94.3 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 97.4 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय परिसर में हैं। कागजों पर ये आंकड़े आश्वस्त करने वाले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति वैसी नहीं है। अगर तीन प्रतिशत स्कूलों में भी बालिकाओं को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है कि 'जाएं तो जाएं कहां...' तो यह छात्राओं की बहुत बड़ी संख्या के साथ अन्याय है। स्कूलों में बालिकाओं के लिए केवल शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है, वहां साफ-सफाई भी होनी चाहिए, अन्यथा, यह उनकी सेहत से खिलवाड़ है। स्वच्छ विद्यालय और समग्र शिक्षा जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कूलों में पानी, साफ-सफाई के मानकों को अनिवार्य करते हैं, जिसमें शौचालय निर्माण, हाथ धोने की सुविधा और तय समय पर सफाई पर जोर दिया जाता है। फिर भी पूरे देश में सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पद बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देते हैं। अक्सर उन्हें 'अन्य कर्मचारी' जैसी अस्पष्ट श्रेणियों में रखा जाता है और ये पद ज्यादातर खाली रहते हैं। नतीजा यह कि शौचालय बन जाने के बावजूद वे इस्तेमाल लायक नहीं रहते। इसका असर लड़कियों के स्वास्थ्य और स्कूल में उनके बने रहने पर पड़ता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता के केंद्रीय सचिव ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि कई स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं या हैं ही नहीं, जिससे लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने सौ फीसदी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनाने का जो लक्ष्य दिया है, उसे आठ मार्च से पहले पूरा करने में तत्परता दिखाएं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी आठ मार्च दूर नहीं है... मगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो यह काम इतना दुरूह भी नहीं है। यहां राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी पर फिर गौर करना चाहिए कि रात भर में कई जगह सड़कें तैयार हो जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं हो पाती।

विजय गुप्ता

रास्ते का हर पल अनमोल है

जीवन की यात्रा में सूरज की गर्मी को महसूस करें, सूर्यास्त की लालिमा को देखें, चांद की रोशनी में कुछ पल ठहरें, पक्षियों की आवाज सुनें और पेड़ों की स्थिरता से सीखें। मंजिल तक पहुंचना तय है, लेकिन रास्ते का हर पल अनमोल है।

जब हम जवान होते हैं, तो हम एक छोटी नदी की तरह होते हैं। रास्ते में कई चट्टानें आती हैं, कई रुकावटें और कठिनाइयां मिलती हैं। उस समय हमें लगता है कि बस किसी तरह इन्हें पार कर लें और जल्दी से समुद्र तक पहुंच जाएं। हम जल्दबाजी में रहते हैं, आगे ही आगे देखने लगते हैं, और सोचते हैं कि सुख शायद मंजिल पर मिलेगा।

लेकिन जैसे-जैसे नदी खेतों और मैदानों से होकर आगे बढ़ती है, वह धीरे-धीरे बड़ी होने लगती है। उसका बहाव शांत हो जाता है। अब वह आकाश की परछाईं अपने भीतर देख सकती है। उसे समझ आ जाता है कि समुद्र तक पहुंचना तो तय है, इसलिए अब भागने की जरूरत नहीं है। अब वह सूर्यास्त की सुंदरता देखती है, चांदनी में ठहरती है और पक्षियों की आवाज सुनती है। यात्रा ही आनंद बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। युवावस्था में हम भविष्य के पीछे दौड़ते हैं, और वृद्धावस्था हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वृद्धावस्था जीवन की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे डर के साथ नहीं, बल्कि समझ और प्रेम के साथ अपनाना चाहिए। एक दिन हम सभी वृद्ध होंगे। कभी न कभी शरीर बीमार भी हो सकता है। मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। ये सच्चाइयां हमें दुखी करने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। जब हम इन्हें शांति से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम हर दिन को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। जैसे शांत नदी आकाश को साफ-साफ प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही शांत मन जीवन की सच्चाइयों को स्पष्ट देख पाता है। वृद्धावस्था में हमें हर समय कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती।

बस सांस लेना, चलना, देखना और महसूस करना ही पर्याप्त होता है। जीवन की यात्रा में सूरज की गर्मी को महसूस करें, सूर्यास्त की लालिमा को देखें, चांद की रोशनी में कुछ पल ठहरें, पक्षियों की आवाज सुनें और पेड़ों की स्थिरता से सीखें। समुद्र तक पहुंचना तय है, लेकिन रास्ते का हर पल अनमोल है। जब हम सजग होकर जीते हैं, तब जीवन की हर अवस्था एक सुंदर उपहार बन जाती है।

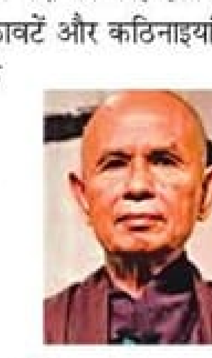

थिक न्हात हान

मुड़-मुड़ के देख

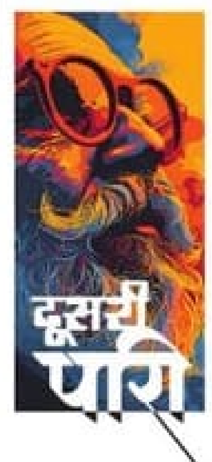

खुशकिस्मत हैं कि बच्चे परवाह करते हैं

मेरठ के 82 वर्षीय धनपाल को धार्मिक यात्रा पर जाने के संबंध में मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने ये सलाह दी:

82 की उम्र में मैं चार धाम यात्रा पर जाना चाहता हूं। मेरी सेहत व सुरक्षा की बच्चों को चिंता है। एक तरफ उनकी भावनाएं हैं, दूसरी तरफ मेरा श्रद्धालु मन। मैं क्या करूं?

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कम गतिविधि की वजह से बुढ़ापा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, बुढ़ापे में बार-बार गिरने और चोट लगने से शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है। हालांकि, हर बुजुर्ग अपनी शारीरिक सीमाओं को अलग-अलग तरह से स्वीकार करता है। कुछ लोग गिरने के डर से घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं, कुछ लोग कम निकलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने शरीर की सीमाओं को मानने से ही इन्कार कर देते हैं। आप इसी आखिरी श्रेणी में आते हैं, जो उम्र को अपनी गतिविधियों में कोई अड़चन नहीं बनने देना चाहते हैं। उम्र के साथ, बुजुर्गों की आध्यात्मिकता में दिलचस्पी बढ़ जाती है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।

हमारे देश में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और देशाटन करने की लंबी परंपरा रही है। इसलिए, आपकी चार धाम यात्रा पर जाने की इच्छा को सिर्फ यात्रा मानना ठीक नहीं होगा, बल्कि इसे एक धार्मिक जरूरत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। यह संतोष की बात है कि आज के समय में भी, जब बुजुर्गों की उपेक्षा समाज में आम बात हो गई है, आपके बच्चे आपकी सेहत और सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील हैं।

ऐसे में कुछ विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। आजकल कई धार्मिक संगठन वरिष्ठ लोगों के लिए धर्म स्थलों की यात्रा का इंतजाम करते हैं। पता करें कि क्या आपके इलाके में ऐसा कोई संगठन है। साथ ही, इस संबंध में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सुझाव लें।

कई ट्रैवल कंपनियां बुजुर्गों की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए टूर अरेंज करती हैं। ऐसी कंपनी ढूंढें, जो आपकी जरूरतों के अनुसार हो और यात्रा के दौरान आप अपने साथ किसी को ले जाने की योजना बनाएं। कुछ ट्रैवल कंपनियों के पास ग्रुप टूर भी होते हैं, जो आपको ज्यादा पसंद आ सकते हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि वह ट्रैवल कंपनी आपको जरूरत के हिसाब से व्हीलचेयर सहायक उपलब्ध कराए। जब भी यात्रा करें, तो हमेशा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही यात्रा करें। अपनी यात्रा के बारे में बच्चों के साथ खुलकर बात करें और उन्हें अपनी योजना बताएं।

जहां तक हो सके, कम से कम दिनों की यात्रा रखें। यात्रा पर निकलने से पहले अपने पारिवारिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें और जरूरी दवाइयां एवं उपकरण साथ रखें। यदि आप अपनी यात्रा में अपने बच्चों को शामिल कर सकें, तो यह एक यादगार यात्रा साबित हो सकती है। अगर परिवार का कोई व्यक्ति आपके साथ जाने की स्थिति में नहीं हो, तो किसी नजदीकी संबंधी को सहयात्री बना सकते हैं। ऐसा करने पर आपके बच्चे और परिवार के अन्य लोग भी आश्वस्त रहेंगे।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं* **edit@amarujala.com** *पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

116 वर्ष की उम्र और जीवटता की मिसाल

आपकी उम्र कुछ भी हो, यदि आपमें कुछ करने की ललक है और नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, तो उम्र तो बढ़ेगी ही, आप हर पल को जिएंगे। एक ब्रिटिश महिला, एथेल कैटरहैम (जन्म 1909) 116 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनीं और तर्क-वितर्क से बचने, सकारात्मक व तनाव-मुक्त सोच रखने तथा जीवन के अवसरों को अपनाने के अपने दर्शन से लोगों को प्रेरित किया।

18 वर्ष की उम्र में भारत में काम करते हुए उन्होंने शुरुआती स्वतंत्रता और अनुकूलनशीलता का उदाहरण दिया, बाद में वे हांगकांग और जिब्राल्टर में भी रहीं। उन्होंने सक्रिय जीवन बनाए रखा, 97 वर्ष की उम्र तक गाड़ी चलाती रहीं, 110 वर्ष की आयु में कोविड-19 से उबरीं और अपने लंबे, स्वस्थ जीवन का श्रेय सकारात्मक मनोदशा व संतुलित जीवनशैली को देती हैं। वह दयालुता, नियमित दिनचर्या और समाज से जुड़े रहने को बेहद महत्व देती हैं। उनका मानना है कि खुशियां, आभार और संयम ही लंबी उम्र की असली कुंजी है।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम* यह सड़क पर बेसहारा, गरीब या घर से निकाल दिए गए बुजुर्ग लोगों को मुफ्त, जीवन भर रहने की जगह, तीनों समय का खाना और शाम का नाश्ता, कपड़े और मेडिकल केयर देता है। यह 'घर से दूर घर' की तरह काम करता है और बुजुर्ग नागरिकों की गरिमा वापस दिलाने और उनकी जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए चौबीस घंटे देखभाल के साथ मनोरंजक गतिविधियां भी करवाता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट sheows.org पर या 099537 50017 पर संपर्क कर सकते हैं।
- *अपना घर वृद्धाश्रम* बेसहारा और गरीब बुजुर्गों को मुफ्त रहने की जगह, खाना, कपड़े और पूरी चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह परिवार जैसे माहौल में पुनर्वास और मानसिक समर्थन पर ध्यान देता है, ताकि उन लोगों को सम्मान और स्वतंत्रता वापस मिल सके। यह संस्था सेना के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी करती है। अधिक जानकारी के लिए Rattanrajsewatrust@hotmail.com पर ई-मेल या 9579000444 पर संपर्क कर सकते हैं।

एजुकेशन & कॅरिअर

अगर आपकी आत्मशक्ति अच्छी है, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

लैब असिस्टेंट व जूनियर लैब असिस्टेंट के पदों पर मौके

804 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 25 फरवरी, 2026
योग्यताएं : दसवीं, बारहवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : rssb.rajasthan.gov.in

भारत संचार निगम लिमिटेड ■ 120 पद

वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
07 मार्च, 2026
वेतनमान
रुपये 24,900 से लेकर रुपये 50,500 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
bsnl.co.in

बिहार लोक सेवा आयोग ■ 102 पद

अंकेक्षक के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
26 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 37 वर्ष
यहां आवेदन करें
bpsc.bihar.gov.in

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ■ 394 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि : 10 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : apprenticeshipindia.gov.in

यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन ■ 80 पद

भारतीय वन सेवा परीक्षा-2026
आवेदन की अंतिम तिथि
24 फरवरी, 2026
पात्रताएं
निर्दिष्ट स्नातक डिग्री निर्धारित
यहां आवेदन करें
upsc.gov.in

हरियाणा लोक सेवा आयोग ■ 50 पद

असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि
12 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष
यहां आवेदन करें
hpsc.gov.in

यहां भी हैं नौकरी की संभावनाएं...

- अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, जोधपुर : प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के पदों पर रिक्तियां।
  वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 11 फरवरी, 2026
- aiimsjodhpur.edu.in
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल : सहायक रजिस्ट्रार, कनिष्ठ अधीक्षक व अन्य पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 03 मार्च, 2026
- iiitbhopal.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

नए कौशल सीखते रहें

समय के साथ नए-नए कौशल सीखकर खुद को अपडेट रखना जरूरी है, ताकि आप बदलती दुनिया में अवसरों का लाभ ले सकें

प्रिसिला क्लैमन
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

Harvard Business Review

आज के दौर में काम करने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन कई लोगों के कौशल उसी गति से अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। यही स्थिति कौशल अंतर कहलाती है, जहां कंपनियों को जिन तकनीकी और व्यावहारिक क्षमताओं की जरूरत होती है, वे कर्मचारियों के पास पूरी तरह मौजूद नहीं होतीं। नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काम करने के तरीकों को बदल रहे हैं, जिससे पुराने कौशल कम उपयोगी होते जा रहे हैं। इसका असर यह होता है कि आपका कॅरिअर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, आय बढ़ने की संभावनाएं घट सकती हैं और यहां तक की आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अब लगातार सीखना और सॉफ्ट स्किल्स मजबूत करना बेहद जरूरी है।

■ जॉब मार्केट की मांग को समझें
सबसे पहले अपनी मौजूदा क्षमताओं की तुलना जॉब मार्केट की मांग और मनचाही नौकरी के जॉब डिस्क्रिप्शन से करें। इससे आपको साफ पता चलेगा कि किन कौशलों की कमी है और किन्हें मजबूत करने की जरूरत है। यह समझ आपको भविष्य के अवसरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करती है।

■ प्रोफाइल के अनुसार कोर्स चुनें
आप समय-समय पर नए तकनीकी या व्यावहारिक कौशल सीखते रहें। इसके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एक प्रभावी माध्यम होते हैं, क्योंकि ये आपको बाजार की मौजूदा जरूरतों के अनुसार अपडेट रखते हैं। ऐसे कोर्स न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी प्रोफाइल को भी मजबूत बनाते हैं, जिससे नियोक्ताओं के सामने आपकी उपयोगिता और अवसर, दोनों बढ़ते हैं।

■ चुनौतियों में अवसर ढूंढें
कार्यस्थल पर खुद को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि आप जानबूझकर ऐसी नई और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं की तलाश करें, जिनमें उन कौशलों की जरूरत हो, जिन्हें आप अभी पूरी तरह नहीं जानते। ऐसी परियोजनाओं पर काम करने से आपको वास्तविक अनुभव मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है और अपनी क्षमताओं को व्यवहार में परखने का मौका मिलता है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप धीरे-धीरे नए कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं, जो आपके कॅरिअर विकास के लिए बेहद लाभकारी होता है।

■ बदलाव में खुद को ढालें
आज के तेजी से बदलते कार्य-परिवेश में सफल रहने के लिए ऐसी मानसिकता विकसित करना जरूरी है, जो निरंतर परिवर्तन और व्यावसायिक विकास को खुले मन से स्वीकार करे। इसका अर्थ है नई तकनीकों, तरीकों और भूमिकाओं को सीखने के लिए तैयार रहना। जब आप खुद को बेहतर बनाने की सोच अपनाते हैं, तो न केवल आप प्रासंगिक बने रहते हैं, बल्कि अपने कॅरिअर में आने वाली चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना भी कर पाते हैं।

खुद को परखें

1. करिम्पुझा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
   (a) केरल (b) कर्नाटक
   (c) तमिलनाडु (d) ओडिशा
2. सक्षम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वार्षिक जागरूकता अभियान है?
   (a) विद्युत मंत्रालय
   (b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
   (c) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
   (d) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3. फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
   (a) इथियोपिया
   (b) ग्वाटेमाला
   (c) इंडोनेशिया
   (d) जापान

उत्तर : *1.a, 2.d, 3.b*

इंटर्नशिप अलर्ट

नीति आयोग का इंटर्नशिप प्रोग्राम

नीति आयोग की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का उद्देश्य इंटर्न को भारत सरकार में सरकारी कामकाज और विकास नीति के मुद्दों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना। इसमें आवेदन के लिए जरूरी है कि आवेदक ने कक्षा बारहवीं में 85 फीसदी अंक प्राप्त किए हों व अंडर ग्रेजुएट/ग्रेजुएट में नामांकित हो और पीजी/पीएचडी/उच्च शिक्षा इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन के सभी वर्षों/सेमेस्टर में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। आवेदन करते समय आवेदकों को अंक प्रतिशत में दर्ज करना होगा। सीजीपीए या ग्रेड को समकक्ष प्रतिशत में बदला जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/5xffxj6h पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन केवल हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन का कोई अन्य तरीका मान्य नहीं है।

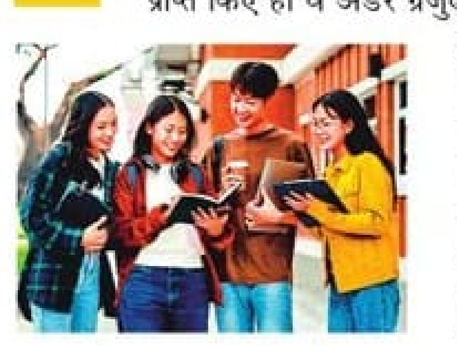

आवेदन आमंत्रित

रोटरी पीस फेलोशिप प्रोग्राम 2027-28

रोटरी फाउंडेशन द्वारा रोटरी पीस फेलोशिप प्रोग्राम 2027-28 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह एक पूर्णतः वित्तपोषित फेलोशिप है, जिसके अंतर्गत मास्टर डिग्री छात्रवृत्ति और एक व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम शामिल है। यह फेलोशिप दुनिया भर के सभी देशों के नागरिकों के लिए खुली है। इस फेलोशिप का उद्देश्य प्रतिभागियों को शांति, संघर्ष समाधान और सतत विकास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार इस फेलोशिप के अंतर्गत मास्टर डिग्री कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसकी अवधि 15 से 24 महीने होती है, जबकि व्यावसायिक विकास प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/r4exkhrj पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आगामी परीक्षाएं | एग्जाम अलर्ट

आरआरबी एनटीपीसी 10+2 इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट

- **परीक्षा की तिथि :** 13 फरवरी, 2026
- उम्मीदवारों को 10 मिनट की अवधि में अंग्रेजी में न्यूनतम 300 शब्द या हिंदी में न्यूनतम 250 शब्द टाइप करने होंगे। उम्मीदवार अपने चुने हुए माध्यम (अंग्रेजी/हिंदी) में टाइप करेंगे। हिंदी विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को कृतिदेव या मंगल फॉन्ट का ज्ञान होना आवश्यक है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/35tz6uy2

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट)-2026

- **परीक्षा की तिथि :** 14 व 15 फरवरी, 2026
- यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय से कुल 100 अंकों के लिए 65 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** goaps.iitg.ac.in/login

सामान्य ज्ञान

जूनो मिशन

■ क्या है
यह मिशन बृहस्पति की संरचना, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद कर रहा है।

■ चर्चा में क्यों
नासा के जूनो यान के नए आंकड़ों से पता चला है कि बृहस्पति पहले के अनुमान से थोड़ा छोटा और ज्यादा चपटा है।

■ सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला यान
नासा का जूनो मिशन 5 अगस्त, 2011 को लॉन्च हुआ और 5 जुलाई, 2016 को बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, जो सूर्य से इतनी दूर तक गया और इसमें तीन बड़े सौर पैनल लगे हैं।

■ तकनीकी सुरक्षा
बृहस्पति के तीव्र विकिरण से बचाने के लिए, जूनो में एक टाइटेनियम रेडिएशन वॉल्ट का उपयोग किया गया है। जूनो ने बृहस्पति के ध्रुवों पर भयानक तूफानों और चुंबकीय क्षेत्र की अहम जानकारी भेजी है।

कच्ची धूप

Fun & Learn

बाल कविता

सुभद्रा कुमारी चौहान

पानी और धूप

अभी-अभी थी धूप, बरसने
लगा कहां से यह पानी
किसने फोड़ घड़े बादल के
की है इतनी शैतानी।
सूरज ने क्यों बंद कर लिया
अपने घर का दरवाजा
उसकी मां ने भी क्या उसको
बुला लिया कहकर आजा।
जोर-जोर से गरज रहे हैं
बादल हैं किसके काका
किसको डांट रहे हैं, किसने
कहना नहीं सुना मां का।
बिजली के आंगन में अम्मां
चलती है कितनी तलवार
कैसी चमक रही है फिर भी
क्यों खाली जाते हैं वार।
क्या अब तक तलवार चलाना
मां वे सीख नहीं पाए
इसीलिए क्या आज सीखने
आसमान पर हैं आए।
एक बार भी मां यदि मुझको
बिजली के घर जाने दो
उसके बच्चों को तलवार
चलाना सिखला आने दो।

साभार : हिंदी कविता डॉट कॉम

उत्तर : 1. A, 2. D, 3. B, 4. C, 5. F, 6. E

नोट : 'कच्ची धूप' को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो मेल करो : kidz@del.amarujala.com

जानवर भी मानसिक रोगी हो सकते हैं

बच्चो, अगर पालतू जानवर तुम्हारी बात मानने से इनकार कर रहा है तो यह उसकी बढ़ती उम्र और किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं।

तुमने देखा होगा कि एक पालतू जानवर अपने मालिक के साथ काफी मिलनसार होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगता है। वह घर के अंदर गंदगी करने लगता है, रात में बेचैन रहने लगता है और बिना कारण चिड़चिड़ा हो जाता है। हैरानी तक होती है, जब वह उन आदेशों को भी समझने में असमर्थ दिखने लगता है, जिन्हें वह वर्षों से पहचानता है। इस तरह के लक्षण एक गंभीर बीमारी की ओर संकेत करते हैं जिसे 'कॉग्निटिव डिसफंक्शन सिंड्रोम' कहा जाता है। यह रोग बुजुर्ग जानवरों में पाया जाता है और काफी हद तक मनुष्यों में होने वाली अल्जाइमर बीमारी जैसा होता है। जैसे अल्जाइमर में व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती जाती है और वह धीरे-धीरे भ्रम तथा मानसिक क्षीणता का शिकार हो जाता है, वैसे ही जानवरों में भी दिमागी क्षमताएं भी घट सकती हैं।

■ वैज्ञानिक क्या कहते हैं :
वैज्ञानिकों के अनुसार, जानवरों में भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कई शोधों से पता चलता है कि कुछ स्थितियां जानवरों के मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। कभी आनुवंशिक कारणों से उनके मस्तिष्क की संरचना में बदलाव आ जाता है, तो कभी डर, तनाव और आघात जैसी घटनाएं उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं।

■ आनुवंशिक कारण और मानसिक विकास : मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम एक आम आनुवंशिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को नई चीजें सीखने और जटिल निर्णय लेने में कठिनाई होती है। यह समस्या क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होती है। सामान्यतः मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है, तब डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं। अधिकांश जानवरों में डाउन सिंड्रोम उसी रूप में नहीं होता, क्योंकि उनके क्रोमोसोम मनुष्यों से अलग होते हैं। हालांकि, मनुष्यों के करीबी रिश्तेदार जैसे चिंपांजी और ओरंगुटान में इसी प्रकार की स्थितियां देखी गई हैं। जापान की एक शोध सुविधा में जन्मी चिंपांजी 'कानाको' इसका उदाहरण है, जिसके शरीर में अतिरिक्त क्रोमोसोम पाया गया था। उसे दृष्टि और हृदय संबंधी समस्याएं थीं, लेकिन मानव देखभाल के कारण वह लंबे समय तक जीवित रह सकी।

■ देखभाल जरूरी : पालतू जानवरों में मानसिक परेशानी के संकेत पहचानना भी जरूरी है। लगातार इधर-उधर घूमना, छिपना, अचानक आक्रामक होना, वजन घटना या बार-बार बीमार पड़ना तनाव का संकेत हो सकता है। कई जानवरों में सेपरेशन एंग्जायटी पाई जाती है, जिसमें मालिक के जाते ही वे अत्यधिक घबराहट महसूस करते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पालतू जानवरों को पर्याप्त व्यायाम, खेल और सामाजिक वातावरण देना चाहिए।
आज विज्ञान यह भी मानता है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं हैं। जानवर भी उम्र, आनुवंशिक कारणों, तनाव और आघात के कारण मानसिक विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनके प्रति केवल दया नहीं, बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए, ताकि वे भी एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें।

पढ़ो और जानो -

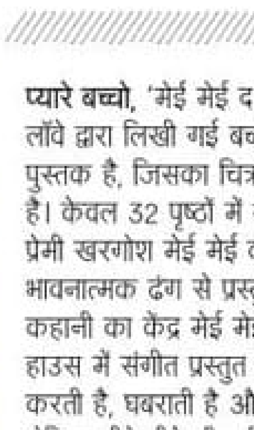

प्यारे बच्चो, 'मेई मेई द बनी' ग्रैमी-विजेता संगीतकार लॉवे द्वारा लिखी गई बच्चों की एक आकर्षक चित्र-पुस्तक है, जिसका चित्रांकन लॉरेन ओ'हारा ने किया है। केवल 32 पृष्ठों में यह कहानी एक छोटे, संगीत-प्रेमी खरगोश मेई मेई की यात्रा को बेहद सरल और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है।
कहानी का केंद्र मेई मेई का सपना है-एच ओपेरा हाउस में संगीत प्रस्तुत करना। रास्ते में वह गलतियां करती है, घबराती है और आत्म-संदेह से जूझती है, लेकिन धीरे-धीरे सीखती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है। यह संदेश बच्चों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है।
लॉवे की संगीत-प्रेरित लेखन शैली पुस्तक को मधुर लय देती है, वहीं ओ'हारा के चित्र कहानी में रंग और जीवन भर देते हैं। यह पुस्तक बच्चों को आत्मविश्वास, अभ्यास और धैर्य का महत्व सिखाती है। कुल मिलाकर, मेई मेई द बनी एक प्यारी, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक पुस्तक है जो बच्चों और माता-पिता दोनों को पसंद आएगी। यह पुस्तक 21 अप्रैल 2026 को पेंगुइन वर्कशॉप से प्रकाशित होने वाली है।

6 फरवरी, 1952

आज का दिन

एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली थी। 2015 में वह अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी थीं।

- **1945 :** जमैका के गायक बॉब मार्ले का जन्म हुआ था।
- **2012 :** स्पेनिश कलाकार एंटोनी टेपीस का निधन हुआ था।
- **2014 :** अमेरिकी हास्य अभिनेता जे लेनो ने 'द टुनाइट शो' के अंतिम एपिसोड की मेजबानी की।
- **2018 :** स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट ने पहली परीक्षण उड़ान भरी थी।

व्रत त्योहार

आज : फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी।
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक।

■ सूर्योदय : 07.09
■ सूर्यास्त : 18.01
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 18 माघ मास शक 1947, माघ मास 25 प्रविष्टे, 18 सावान हिजरी 1447, फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी 26.54 तक उपरांत सप्तमी, चित्रा नक्षत्र 26.27 तक उपरांत स्वाती नक्षत्र, शूल योग 23.39 तक उपरांत गंड योग, गर करण 14.06 तक उपरांत वणिज करण, चंद्रमा तुला राशि में 13.25 बजे।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। कार्य विशेष में सफलता से उत्साह बढ़ेगा। नौकरी में नूतन पदभार संभव है।

वृष : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। अर्थ प्राप्ति होगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

मिथुन : दिनमान श्रम साध्य रहेगा। उतावलेपन में निर्णय लेने से बचें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

कर्क : सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी। भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील रहेंगे। व्यवसाय में मंदी रहेगी।

सिंह : सकारात्मक सोच बनाए रखें। विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

कन्या : कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में लाभ होगा।

तुला : मानसिक उलझन बनी रहेगी। आय-व्यय में संतुलन बनाए रखें। व्यवसाय में लाभ कम होगा। सेहत नरम रहेगी।

वृश्चिक : लोकप्रियता बनी रहेगी। अर्थ प्राप्ति संभव है। व्यावसायिक साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है।

धनु : राजकाज में निराशा होगी। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। व्यावसायिक स्थिति से चिंता हो सकती है।

मकर : चली आ रही चिंता में कमी आएगी। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। स्वविवेक से योजना सफल हो सकती है।

कुंभ : नई योजना में व्यस्त रहेंगे। शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ के अवसर मिलेंगे।

मीन : आजीविका प्राप्ति का अवसर मिल सकता है। आय का स्थायी साधन बनेगा। घरेलू कार्यों की पूर्ति हो सकती है।

जन्मदिन

अंगद बेदी, अभिनेता

आज जन्मे जातक सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले एवं मौलिक विचारों के होते हैं। विकास के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। सरकारी या अर्द्धसरकारी क्षेत्र में सेवारत जातकों को उन्नति का अवसर मिलेगा। इस वर्ष किसी नए कार्य में पूंजी निवेश हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

			7			6		8
	7	8			6		1	
	6			4	5			
	5				4			
6		1				7		2
			1				8	
			9	1			6	
	9		4			5	2	
2		7			3			

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	3	4	7	2	1	6	5	8
5	7	8	3	9	6	2	1	4
1	6	2	8	4	5	9	7	3
8	5	9	2	7	4	1	3	6
6	4	1	5	3	8	7	9	2
7	2	3	1	6	9	4	8	5
4	8	5	9	1	2	3	6	7
3	9	6	4	8	7	5	2	1
2	1	7	6	5	3	8	4	9

डेली हेल्थ कैप्सूल

पैरों की उंगलियां हो गई हैं नीली-बैंगनी?

ठंड में कई लोगों की उंगलियों के रंग बदल जाते हैं। ये कई बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं।

ठंड के कारण हाथ और पैरों की उंगलियां नीली या बैंगनी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मौसम में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए हाथों और पैरों की नसों को थोड़ा सिकोड़ लेता है। इससे पैरों की उंगलियों तक खून कम पहुंचता है। ऐसा होने से उस स्थान तक ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच पाती है। इसी कारण पैरों की उंगलियां नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। कुछ लोगों में यह समस्या रेनॉड्स फिनॉमेनन के कारण भी हो सकती है। इस समस्या में ठंड लगने या ज्यादा तनाव होने पर हाथों या पैरों की उंगलियों में खून का बहाव बहुत कम हो जाता है। पहले उंगलियां सफेद होती हैं, फिर नीली और कुछ समय बाद ये लाल रंग की हो जाती हैं। आम तौर पर यह समस्या महिलाओं, दुबले शरीर वाले या बहुत ठंडे जगहों पर रहने वाले लोगों में अधिक देखने को मिलती है। शरीर में खून की कमी होने से पैरों की उंगलियां नीली हो जाती हैं। इसके अलावा शुगर, थायरॉइड, धूम्रपान और ज्यादा देर तक ठंड में रहने की वजह से भी यह समस्या बढ़ सकती है। अगर यह समस्या बार-बार हो या ज्यादा बढ़ जाए, तो चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी होता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इस समस्या से बचने के लिए पैरों को गरम रखें। ठंडे पानी से पैर न धोएं और ठंडे फर्श पर न बैठें। चलने-फिरने या व्यायाम करने से रक्त संचार सही बना रहता है, इससे यह समस्या नहीं होती है।
-डॉ. प्रदीप शैलत
वरिष्ठ चिकित्सक

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 6 फरवरी, 2026

कल्पमेधा

धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जिनमें एक निश्चित असफलता जान पड़ती है।

– डेल कार्नेगी

संबोधन के संदेश

बजट सत्र के सातवें दिन संसद में जिस तरह की स्थितियां पैदा हुईं, वे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक परंपराओं में संवाद के समांतर एक बार फिर मतभेदों के तीखे होने को ही दर्शाता है। मौजूदा सत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही और सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन शोर-शराबे और हंगामे की वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए सवालों और उतार-चढ़ाव के बीच आखिर गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा को संबोधित किया। जबकि विपक्ष के नेता को न बोलने देने का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। जाहिर है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जहां समग्र चर्चा होनी चाहिए थी, वहां सदन हंगामे की वजह से बाधित हुआ। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकार के फैसलों और नीतियों को स्पष्ट करते हुए राज्यसभा में अपनी राय रखी।

पिछले कुछ समय से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में तेजी से नीतिगत स्तर पर भी बदलाव होते देखे जा रहे हैं और नई व्यवस्था की जमीन बनती दिख रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में स्थितियां संभाली नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसे में स्पष्ट दिख रहा है कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इससे पहले दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी, वह अब बदल रही है और अगर इसे तटस्थ भाव से देखा जाए, तो साफ लग रहा है कि झुकाव भारत की ओर है। दरअसल, हाल के वर्षों में विकसित देशों के कूटनीतिक टकरावों और उससे उपजे हालात के बीच वैश्विक दक्षिण के रूप में देखे जाने वाले देशों की समस्याओं पर आवाज उठने की प्रक्रिया जिस तरह धीमी पड़ रही थी, उसमें भारत को एक उम्मीद की नजर देखा जा रहा था। इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में वैश्विक दक्षिण को लेकर होने वाली चर्चा के सूत्रधार के साथ-साथ भारत को वैश्विक दक्षिण की बुलंद आवाज के रूप में देखा जाता है।

भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते नीतिगत स्तर पर आने वाले समय में काफी अहम साबित होने वाले हैं और उसके परिणामों को लेकर अभी से उत्सुकता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ समझौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपनी पहल से समझौता करता है, तो यह अर्थजगत के लिए एक बड़ा संदेश है। इनमें 'सभी समझौतों की जननी' माने जाने वाले यूरोपीय संघ के सत्ताईस देशों के साथ एकमुश्त समझौता हुआ है। इसी को अहम मानते हुए प्रधानमंत्री ने एक नई वैश्विक व्यवस्था और उसमें भारत की खास जगह बनने का संकेत दिया। इसके अलावा, दुनिया के कई समृद्ध देशों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी गंभीर चिंता का एक कारण बन रही है। ऐसे में भारत अपनी युवा आबादी के बूते बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इसे दर्ज किया कि विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और हमारे पास युवा प्रतिभाएं हैं, जिनके पास संकल्प, सपने और सामर्थ्य हैं। जाहिर है, बहस, विचार और टकराव के मुद्दों के समांतर विपक्ष की अनुपस्थिति के बीच प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर लोकतांत्रिक संदर्भों में भी विचार किया जाएगा।

जानलेवा धागे

किसी खास किस्म के मांझे से दूसरों की पतंग काटने की लोगों के भीतर कैसी भूख है कि यह राह चलते निर्दोष लोगों और मासूम पक्षियों के लिए जानलेवा बन जाती है। यह जानते-समझते हुए भी लोग खतरनाक मांझे से पतंग उड़ाते हैं, जिनसे उलझ कर हर साल कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में रखते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, एक दिन पहले ही लखनऊ में मांझे वाले धागे से गला कटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई थी। राज्य सरकार अब विशेष अभियान चला कर चीनी मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। सवाल है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद ये धागे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चोरी-छिपे या खुलेआम कैसे बिक रहे हैं। ये कहां से आते हैं और इनके स्रोत क्या हैं? यह किसकी लापरवाही का नतीजा है और इसे रोकने में संबंधित एजंसियां अब तक नाकाम क्यों रही हैं?

यह दुखद है कि जन सरोकार के इतने बड़े मसले की हर स्तर पर उपेक्षा होती रही है। समय-समय पर चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने की बातें की गईं, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुईं। प्रश्न यह है कि इन धागों को बेचने की छूट कौन देता है? गौरतलब है कि इसे खरीदने और बेचने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा पंद्रह के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मगर इनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता। चीनी मांझे पर कई राज्यों में रोक है। दिल्ली में भी पाबंदी है, लेकिन यहां भी ये बेरोकटोक बिकते हैं। साफ है कि चीनी मांझे के बाजार में पहुंचने से लेकर बिकने तक, कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। खतरनाक मांझे के साथ पतंग उड़ाने का ऐसा क्या जुनून है लोगों में कि जोखिम की आशंका के बावजूद वे न सजा से डरते हैं, न जुर्माने से। इस तरह के जानलेवा धागे से पतंग उड़ाने की जिद को किस तरह देखा जाएगा?

मुक्त व्यापार और भारत के अंतर्विरोध

विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवादी समाज के साथ कदमताल मिलाते भारत के विकासशील समाज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना भविष्य में आर्थिक अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है।

ब्रह्मदीप अलूने

दुनिया भर में विकसित देशों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार, निवेश का भरोसेमंद ठिकाना और रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख केंद्र है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने यह समझा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। इन देशों के लिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल मध्यम वर्ग, बढ़ती खपत क्षमता और युवा आबादी है, जो आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में शामिल भारत की कम लागत वाली कुशल श्रमशक्ति और विशाल बाजार पूंजीवादी शक्तियों की आर्थिक महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए मुफीद नजर आते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर शुल्क कम करने की अचानक घोषणा ने सबको चमत्कृत किया है, वहीं अमेरिकी प्रशासन को चुनौती देकर यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता अभूतपूर्व माना जा रहा है। भारत को यह उम्मीद है कि विकसित देशों के साथ व्यापार से दीर्घकालिक लाभ होंगे। अमेरिका और यूरोप में क्रय-शक्ति अधिक है और वे गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं। इससे भारत के दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग, वाहन पुर्जे, इंजीनियरिंग सामान, रत्न तथा आभूषण और कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विस्तार मिल सकता है। विकसित देशों के साथ व्यापार और समझौते भारत में विदेशी निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता, रोजगार और आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण संभव होता है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत कर सकता है।

विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और पूंजीवादी समाज के साथ कदमताल मिलाते भारत के विकासशील समाज के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विकसित देश यानी पूंजी, तकनीक, प्रति व्यक्ति आय, बचत, निवेश और नागरिकों के रहन-सहन जैसी विशेषताओं में उच्च स्तर और मजबूत अर्थव्यवस्था। जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत और निवेश का निम्न स्तर होता है। अधिक जनसंख्या होती है, लेकिन वह कम कार्यकुशल होती है। पूंजी निर्माण की दर कम तथा आयात की मात्रा अधिक रहती है। इन देशों में पूंजी और तकनीकी का आमतौर पर दूसरे देशों से आयात होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में संलग्न रहता है, फिर भी उत्पादन देश की आवश्यकता से कम बना रहता है। विकसित देशों को कच्चा माल, श्रम-आधारित उत्पाद चाहिए, जबकि विकासशील देशों को पूंजी, तकनीक, मशीनें और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद चाहिए। इसलिए दोनों का व्यापार अक्सर जरूरतों की पूर्ति पर आधारित होता है। ऐसे में भारत द्वारा विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना भविष्य में आर्थिक अवसरों के साथ कुछ रणनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है। विकसित देशों की कंपनियां, तकनीक, पूंजी और ब्रांड के दम पर भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करेंगी, जिससे छोटे किसान और घरेलू उद्योग दबाव में आ सकते हैं। सस्ते आयात से व्यापार घाटा बढ़ने, स्थानीय उत्पादन कमजोर होने और रोजगार पर असर का खतरा भी रहेगा। इसके अलावा, पेटेंट, डेटा, पर्यावरण और श्रम मानकों जैसी शर्तें भारत की आर्थिक और

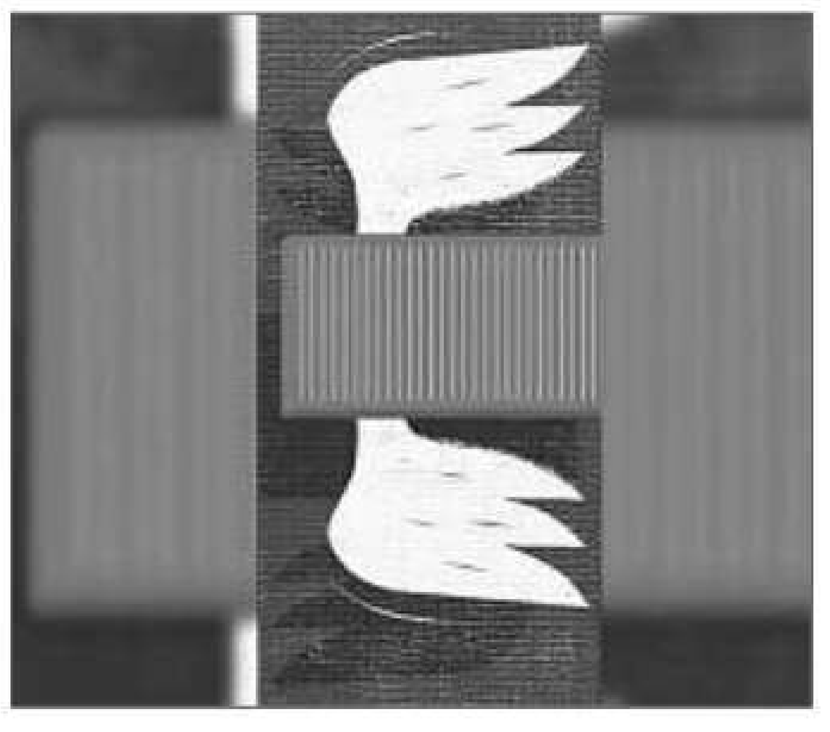

राजनीतिक निर्णय की स्वतंत्रता सीमित कर सकती हैं।

बीते चार दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इसमें विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भी बड़ा और सकारात्मक लाभ मिला है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद वैश्विक व्यापार

> **विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं। भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है। भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास, सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय की स्थापना है। वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण मानक, कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। जाहिर है, भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा-कवच, चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता-वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करे।**

नियमों में एकरूपता आई, व्यापार बाधाएं कम हुईं और विभिन्न देशों के बीच बाजार तक पहुंच आसान बनी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह अवसर था कि वह अपनी आर्थिक क्षमता, श्रमशक्ति और सेवा क्षेत्र की ताकत के आधार पर वैश्विक मंच पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। विश्व व्यापार संगठन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकसित देशों के कब्जे को रोकने के लिए अनुचित सबसिडी, डंपिंग और व्यापार बाधाओं पर नियम बनाए। इसका लाभ भारत जैसे विकासशील देश को निर्यात विस्तार के रूप में मिला। विश्व व्यापार के तहत आयात शुल्क घटाने और व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया ने भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोले।

विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इनके स्वरूप, उद्देश्य और प्रभाव में मूलभूत अंतर है। यही अंतर विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक प्रकार का विरोधाभास पैदा करता है। विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय संस्था है, जो नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को स्थापित करती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौता चुनिंदा देशों के बीच विशेष रियायतों और शर्तों पर आधारित क्षेत्रीय या द्विपक्षीय व्यवस्था है। इस कारण विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच व्यापार में समानता से कहीं ज्यादा असंतुलन बढ़ता दिखाई देता है।

दूसरी ओर, मुक्त व्यापार समझौते बिल्कुल अलग हैं। मुक्त व्यापार समझौते में कुछ देश आपस में शुल्क घटाकर या समाप्त करके व्यापार को तेज करते हैं। विकसित देशों के लिए मुक्त व्यापार समझौते अक्सर एक रणनीतिक हथियार बन जाते हैं। वे विश्व व्यापार संगठन में जब व्यापक सहमति नहीं बना पाते, तब मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। विकसित देश मुक्त व्यापार के नाम पर केवल शुल्क घटाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पेटेंट नियम, डेटा स्थानीयकरण पर रोक, श्रम और पर्यावरण मानकों की कठोर शर्तें, सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को अवसर तथा निवेश विवाद निपटान जैसी शर्तें जोड़ देते हैं। इन शर्तों का असर यह होता है कि विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को लेकर स्वतंत्रता सीमित होने लगती है। पूंजीवादी शक्तियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और यह स्थिति भारत जैसे विकासशील और लोकतांत्रिक देश की चुनौतियां बढ़ा सकती है। व्यापार को लेकर नए समझौतों से अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ने से निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश और तकनीक हस्तांतरण के अवसर भी मिलेंगे। वहीं विकसित देशों की विशाल कंपनियां कम शुल्क के साथ घरेलू बाजार में प्रवेश करेंगी, तो भारत के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है।

दरअसल, विकसित देश नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करते हुए भी अपने हितों के लिए क्षेत्रीय समझौतों का सहारा लेते हैं। भारत और विकसित देशों की प्राथमिकताओं में गहरा अंतर है। भारत की मुख्य चिंता गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास, सस्ती शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक न्याय की स्थापना है। वहीं विकसित देशों की प्राथमिकताएं उच्च जीवन-स्तर, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण मानक, कड़े श्रम नियम और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी हैं। जाहिर है, भारत और विकसित देशों की नीतियां और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह मुक्त व्यापार को सुरक्षा-कवच, चरणबद्ध उदारीकरण और घरेलू क्षमता-वृद्धि के साथ संतुलित रूप में लागू करे। भारत के स्थायी विकास के लिए रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हीं आधारों पर देश की आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

सेहत की कुंजी

सरस्वती रमेश

प्रकृति प्रदत्त नेमतों की कोई कीमत नहीं। वे अनमोल होती हैं। अब नींद को ही देखा जाए। हमारे आसपास ऐसे लोग आम हैं, जिनकी नजर में सोना वक्त गंवाना है। 'जो लोग सोते हैं, वे खोते हैं', इस आशय से कई कहावतें और उक्तियां भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ दिख जाता है, तो उसे उसके बिगड़े हुए काम का कारण बताया जाता है। कुछ स्थितियों में यह सच भी हो सकता है। मगर क्या हम हर वक्त नींद लेने को नकारात्मक ही मान कर कुछ गंवा तो नहीं रहे हैं? खासतौर पर ऐसे दौर में जब स्मार्टफोन में गुम रहने से लेकर कई बेमानी व्यस्तताओं की वजह से आंखों की नींद उड़ रही है, लोगों को नींद न आने की बीमारी जकड़ रही है। सवाल है कि क्या अच्छी नींद की कीमत रुपए पैसे, सोना चांदी या किसी अन्य बेशकीमती उपहार से आंकी जा सकती है? नहीं। नींद तो नींद होती है। इसकी भरपाई किसी दूसरी चीज से करना संभव नहीं। एक गरीब आदमी को नींद की जितनी जरूरत होती है, उतनी ही उन्हें भी, जिनके घरों में रुपए बोरियों में भरे हुए हैं। भोजन पानी की तरह नींद भी दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जरूरत है। नवजात बच्चे जितना ज्यादा सोते हैं, उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी नींद की उतनी ही जरूरत होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें नींद की जरूरत पड़ती क्यों है।

दुनिया मेरे आगे

> **हमें लगता है कि जब हम सो जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी थककर सो जाता होगा। मगर ऐसा नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग जीने के लिए जरूरी कई क्रियाकलापों में लग जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम में सीधे तौर पर जुट जाता है, जो हमारे जागते हुए दिमाग के लिए करना संभव नहीं होता है।**

सोना जितना दिमाग के लिए जरूरी होता है, उतना शरीर के लिए भी। आमतौर पर हमें लगता है कि जब हम सो जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी थककर सो जाता होगा। मगर ऐसा नहीं है। सोते समय हमारा दिमाग जीने के लिए जरूरी कई क्रियाकलापों में लग जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम में सीधे तौर पर जुट जाता है, जो हमारे जागते हुए दिमाग के लिए करना संभव नहीं होता है। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हमने कभी रात को अपनी नींद खराब की होगी, यानी किसी वजह से हम रात को सो नहीं पाए होंगे, तो अगले दिन अजीब-सी थकान या तनाव का अहसास होता है। काम करने में भी दिमाग का भरपूर इस्तेमाल नहीं हो पाता।

इसकी वजह यह है कि नींद का हमारे दिमाग की कार्यक्षमता से संबंध होता है। नींद दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालती है। दिमाग को लचीलेपन यानी संकेतों के हिसाब से ढलने की क्षमता के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत कम सोते हैं, तो दिन में सीखी हुई चीजों को अपने भीतर स्थिर नहीं कर पाते और भविष्य में उन्हें याद रखने में ज्यादा दिक्कत होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद दिमाग की कोशिकाओं से बेकार चीजों को हटाने में मदद करती है। जब दिमाग क्रियाशील होता है, यानी हम जाग रहे होते हैं, तो यह काम उतनी कुशलता से नहीं हो पाता है, लेकिन सोने के बाद दिमाग पर से अतिरिक्त भार खत्म हो जाता है और वह खुद को व्यवस्थित करने की क्रिया में जुट जाता है। दिमाग के अलावा नींद बाकी शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जब लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो तरह-तरह की बीमारियां पकड़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। अवसाद, दौरे, उच्च रक्तचाप और सिरदर्द के लक्षण और बढ़ने लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे बीमारी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। नींद चयापचय में भी भूमिका निभाती है। यह जानकर हैरानी होगी कि एक रात की नींद छूटने से भी एक स्वस्थ व्यक्ति में मधुमेह-पूर्व की स्थिति बन सकती है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम सोते हैं, तब हमारा दिमाग दो अलग-अलग तरह की नींद लेता है। आरइएम (रैपिड-आइ मूवमेंट) नींद और (गैर-आरईएम) नींद। नींद की प्रक्रिया का पहला हिस्सा नान-आरईएम नींद है, जिसके चार स्तर होते हैं। पहला स्तर जागने और सोने के बीच का होता है। दूसरा हल्की नींद होती है, जब दिल की धड़कन और सांस लेने की गति नियमित हो जाती है और शरीर का तापमान कम हो जाता है। तीसरे और चौथे स्तर में गहरी नींद होती है। पहले यह माना जाता था कि आरईएम नींद सीखने और याददाश्त के लिए सबसे जरूरी नींद का चरण है, लेकिन नए आंकड़ों से पता चला है कि गैर-आरईएम नींद इन कामों के लिए ज्यादा जरूरी है। यह नींद शरीर को अधिक आराम पहुंचाने वाली होती है। जैसे ही हम आरईएम नींद में जाते हैं, बंद पलकों के पीछे आंखें तेजी से हिलती हैं और दिमाग की तरंगें जागृत अवस्था जैसी ही होती हैं। सांस की दर बढ़ जाती है। सपने देखते वक्त हमारा शरीर कुछ समय के लिए सुन्न की अवस्था में पहुंच जाता है।

यह चक्र चलता रहता है, लेकिन हर चक्र के साथ हम नींद के गहरे स्तर तीन और चार में कम समय और आरईएम नींद में ज्यादा समय बिताते हैं। एक रात में हम चार या पांच बार इस चक्र से गुजरते हैं। नींद का विज्ञान कुछ भी कहे। लेकिन हमारा अनुभव यह कहता है कि अच्छी नींद हमारे स्वस्थ रहने की कुंजी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, नींद से समझौता नहीं होना चाहिए। नींद का चक्र अगर बाधित होता है, तो यह हमारी सेहत और व्यक्तित्व को बाधित कर दे सकता है।

बदहाली की जड़ें

पिछले दिनों शहबाज शरीफ की स्वीकारोक्ति पाकिस्तान की उस भयावह आर्थिक सच्चाई को उजागर करती है, जिसमें वह वर्षों से फंसा हुआ है। आज यह देश जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उसके लिए उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आतंकवाद को राज्य-नीति बना लिया। नतीजा यह हुआ कि देश कर्ज के दलदल में इस कदर धंस गया कि अब उसके कई हिस्से और उद्योग चीन के पास गिरवी रखे जा चुके हैं। आज उसके अनेक रणनीतिक ठिकानों पर चीन का प्रभाव है। भारत के प्रति पाकिस्तान की दुश्मनी कोई आज की बात नहीं है। कट्टरपंथी ताकतों ने देश की गरीबी का फायदा उठाया। आतंकवादी शिविर, प्रशिक्षण केंद्र और उनके रखरखाव पर होने वाला भारी खर्च, यह सब कुछ पाकिस्तान सरकार की शह पर चलता रहा। यदि यही धन पाकिस्तान ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया होता, तो आज वह विकास के मामले में कई देशों से आगे होता। जिस देश का जन्म ही नफरत की बुनियाद पर हुआ हो, उससे भाईचारे की उम्मीद करना बेमानी है।

– अरविंद रावल, झाबुआ, मप्र

जागने की जरूरत

आस्ट्रेलिया और फ्रांस ने इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता से किशोरों को दूर रखने के लिए समय रहते कदम उठा रहे हैं। अब वहां सोशल मीडिया से जुड़े मंचों का उपयोग किशोर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए वहां की सरकारों ने संबंधित कंपनियों को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों ही विकसित देश हैं और आधुनिकता में किसी से पीछे नहीं। इनमें फ्रांस तो फैशन की राजधानी है। जब ऐसे देशों ने यह महसूस कर लिया कि आज किशोरों और युवाओं के भटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण इंटरनेट पर परोसी जाने वाली नकारात्मक सामग्री है, तो मर्यादा, शिष्टाचार और सामाजिक संबंधों को महत्त्व देने वाला देश भारत कब जागेगा? संस्कृति और परंपराओं का यह देश कब समझेगा कि समाज में फैली अशांति, हिंसक प्रवृत्ति, रिश्तों में कटुता और सामाजिक ताने-बाने के बिखरने के पीछे क्या वजह है।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

लक्ष्य और चुनौती

'संतुलन की राह' (संपादकीय, 3 फरवरी) पढ़ा। इसमें वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट का संतुलित विश्लेषण किया गया है। कोई दोराय नहीं कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच लोकलुभावन वादों के बजाय इस बार का बजट यथार्थवादी लक्ष्यों पर केंद्रित है। देश को इसी की जरूरत है। इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के जरिए भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखता है। विशेष रूप से पचास नए आइआइटी, मेडिकल कालेजों और 'स्किल इंडिया' के लिए भारी निवेश के माध्यम से युवा सशक्तीकरण तथा बेरोजगारी दर को नीचे लाने का लक्ष्य है। हालांकि इस बजट की वास्तविक सफलता डिजिटल विभाजन को पाटने, ग्रामीण रोजगार सृजन और लैंगिक समानता जैसे परिणामों पर निर्भर करेगी ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंच सके।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

उपहारों का पर्दा

उपहारों का आदान-प्रदान एक सार्वभौमिक प्रथा है जो सामाजिक जुड़ाव, कूटनीति, और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। यह भावनाओं और संस्कृतियों को व्यक्त करने का भी एक तरीका है। आधुनिक काल में महंगे उपहार लेना और देना महज हमारी संस्कृति एवं परंपरा नहीं हो सकती है। मगर कई बार इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। जब एक व्यापारी किसी अधिकारी को उपहार देता है या कोई औद्योगिक घराना किसी राजनीतिक दल को चुनावी चंदे के रूप में उपहार देता है, तो इसके बदले में उसकी कीमत भी वसूली जाती है। बरसों से चली आ रही उपहार परंपरा, ऐतिहासिक रूप से कूटनीति, गठबंधन निर्माण और शक्ति प्रदर्शन के साधन के रूप में कार्य करती रही है। मगर इसमें स्वार्थ न आए, इसके लिए देश और राजनीति को सजग रहना चाहिए।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में 'भारत टैक्सी' की शुरुआत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को देश के पहले सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच 'भारत टैक्सी' की शुरुआत की। दो महीने के सफल पायलट परीक्षण के बाद शुरू की गई यह टैक्सी सेवा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में शुरू की गई है। इस मंच के उद्घाटन अवसर पर शाह ने कहा, 'अगले तीन वर्षों में भारत टैक्सी सेवा को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देशभर में चालू कर दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि इस आनलाइन टैक्सी सेवा मंच से होने वाला लाभ इससे जुड़े ड्राइवरों के साथ साझा किया जाएगा। इस सेवा के तहत ग्राहक आवागमन के लिए कार के साथ तिपहिया और दोपहिया वाहनों की भी बुकिंग कर सकेंगे। फिलहाल देश के आनलाइन टैक्सी बाजार पर उबर, ओला और रैपिडो जैसी कुछ चुनिंदा कंपनियों का वर्चस्व है। बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत भारत टैक्सी मंच की स्थापना छह जून, 2025 को की गई थी। इस मंच पर न तो किसी कमीशन का प्रावधान है और न ही व्यस्त समय में किसी तरह की किराया बढ़ोतरी का प्रावधान होगा। इसमें मुनाफे का सीधा वितरण चालकों के बीच किया जाता है। आठ प्रमुख सहकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुए इस मंच ने दो दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में पायलट संचालन शुरू किया था। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच और ड्राइवरों के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा परिवहन मंच बनकर उभरा है। पायलट चरण के बाद से अब तक तीन लाख से अधिक ड्राइवर इस मंच से जुड़ चुके हैं, जबकि एक लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है।

दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्राएं पूरी की जा रही हैं और अब तक करीब 10 करोड़ रुपए सीधे ड्राइवरों को वितरित किए जा चुके हैं। इस मंच से जुड़े ड्राइवरों को 'सारथी' कहा जाता है। यह उनके लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित सहायता प्रणाली जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को भी प्राथमिकता देता है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे कांग्रेस सांसद

मेरे आग्रह पर सदन में नहीं आए प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक 'काले धब्बे' की तरह था।

लोकसभा की बैठक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे पुनः शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कल 'सदन के नेता (प्रधानमंत्री मोदी) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था। मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य नेता सदन के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। मैंने यह दृश्य सदन में देखा भी। अगर ऐसी घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता।' अध्यक्ष ने कहा कि इसे टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं और गरिमा को अक्षुण्ण बनाकर रखूं। सदन के नेता सदन में नहीं बोलें, यह सभा के लिए किसी प्रकार उचित नहीं है।

बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सदन में नहीं आकर उनके आग्रह को मानते हुए सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया और इसके लिए वह प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। कल की घटना देश ने देखी है कि किस तरह महिला सदस्य वहां (प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान) तक पहुंची हैं। यह किसी तरह उचित नहीं था। सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था।

लोकसभा अध्यक्ष का दावा पूरी तरह झूठ, 'बकवास' : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की विपक्षी सदस्यों की योजना संबंधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दावे को पूरी तरह झूठ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि 'प्रधानमंत्री अब अध्यक्ष के पीछे छिप रहे हैं।

प्रियंका गांधी ने आरोप भी लगाया कि यह 'बकवास' है कि कुछ महिला सांसदों के खड़े होने के कारण प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है। प्रधानमंत्री पर हाथ उठाने या उन्हें चोट पहुंचाने या ऐसी किसी चीज का कोई सवाल ही नहीं है इसलिए, किसी के लिए भी यह कहना कि ऐसी कोई योजना थी, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई योजना नहीं थी। उनका कहना था कि यदि आप अपने सदस्यों को खड़े होकर बकवास करने की अनुमति देंगे, तो विपक्ष के लोग विरोध करेंगे।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के पीछे छिप रहे हैं और यह सब वह उनसे कहलवा रहे हैं। कल उनकी (प्रधानमंत्री) सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उनके आसन के सामने तीन महिलाएं खड़ी थीं, यह क्या बकवास है? आप अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं पूछते? प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास उन्हें (राहुल गांधी को) किसी प्रकाशित स्रोत को उद्धृत करने से रोकने का कोई आधार है?

प्रधानमंत्री के जवाब के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

लोकसभा ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तत्काल बाद ही सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा सदन में जवाब देने की परंपरा है, लेकिन गतिरोध की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब लोकसभा में नहीं हुआ और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण एक बार के स्थगन के बाद बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराए। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसदों को बैनर नहीं दिखाने को कहा। शोर-शराबे के बीच ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर निचले सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के समक्ष रखा। हंगामे के बीच ही सभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद दोपहर 12 बजकर पांच मिनट पर सदन की बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव भाजपा के सांसद सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को रखा था और इसका अनुमोदन करते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने विचार रखे थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण के हवाले से चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन अध्यक्ष बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी।

मस्ती
अनंतनाग जिले के गावरान गांव में गुरुवार को बर्फबारी के बाद बच्चे स्लेज पर बैठकर पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए।

निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया

कांग्रेस ने कहा, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

संसद के वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए लोकसभा के आठ सदस्यों ने गुरुवार को भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने संसद के मकर द्वार के निकट सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इन सांसदों ने हाथ में एक बड़ा बैनर ले रखा था, जिस पर 'पीएम इज कंप्रोमाइज्ड' लिखा हुआ था। सांसदों ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' और 'नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी' के नारे लगाए।

गुरुवार को सुबह विपक्ष दलों ने संसद के वर्तमान बजट सत्र में आगे की रणनीति पर चर्चा की और फैसला किया कि वे विपक्षी नेताओं को सदन में नहीं बोलने देने के विषय पर सरकार को घेरेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के मुताबिक, 'सदन में दो आवाजें हैं, एक आवाज सत्तापक्ष की और दूसरी विपक्ष की है। लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष की आवाज को मौका मिले।' उन्होंने कटाक्ष कि कि यह सरकार की 'मन की बात' वाली सोच है। 'मन की बात' रेडियो पर हो सकती है, लेकिन संसद 'मन की बात' के लिए नहीं है। संसद में विपक्ष के नेता बोलते हैं और फिर प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया और संभवतः प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे, जो लोकतंत्र के लिए दुखद है।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष तथा दूसरे नेताओं को भी सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन इस सरकार द्वारा उन्हें बोलने से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमारा एकमात्र मसविदा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्षी नेताओं और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

चुनावी वादों में मुफ्त उपहार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

बेहद गंभीर मामला, इसे सूचीबद्ध करेंगे : प्रधान न्यायाधीश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने 'अतार्किक मुफ्त उपहार' की चुनावी घोषणा या वादा करने वाली किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त करने अथवा उसका पंजीकरण रद्द करने के निर्देश संबंधी जनहित याचिका को सुनवाई के लिए मार्च में सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को सहमति जताई।

याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ को बताया कि उनकी जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को 2022 में ही नोटिस जारी किए गए थे और उन्होंने न्यायालय से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा होने हैं। इन चुनाव में फिर राजनीतिक दल लोगों को मुफ्त की रेवड़ी का वादा करेंगे। वकील ने कहा कि सूरज और चांद को छोड़कर चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मतदाताओं से हर चीज का वादा करते हैं और यह भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया हमें याद दिलाएं और अंत में इसका विशेष उल्लेख (मेंशन) करें। हम इसे मार्च में सूचीबद्ध करेंगे।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 25 जनवरी, 2022 को केंद्र और निर्वाचन आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें चुनाव से पहले 'अतार्किक मुफ्त उपहार की घोषणा' करने या इसे वितरित करने वाली राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिह्न को जब्त करने अथवा उसे अपंजीकृत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने इसे एक 'गंभीर मुद्दा' करार दिया था और कहा था कि कभी-कभी 'मुफ्त उपहार योजना का बजट नियमित बजट से अधिक हो जाता है'।

याचिका में शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया गया कि सार्वजनिक धन से 'अतार्किक मुफ्त उपहार' का चुनावी वादा मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित करता है और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में एक विकल्प के रूप में केंद्र को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

लोकसभा में प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब नहीं दिया : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं दिए जाने को कांग्रेस से इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया है। इस मामले में लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा गया है।

इस पत्र में चर्चा का जवाब नहीं दिए जाने पर एतराज जताया है। पत्र में वेणुगोपाल ने बताया कि नियम बीस के तहत प्रधानमंत्री को चर्चा का जवाब देना होता है और यदि किन्हीं कारणों की वजह से यह जवाब नहीं दिया जाता है तो इसकी जानकारी सदन को देनी होती है। इस मामले में सदन को जानकारी नहीं दी गई है, जो कि तय नियम प्रक्रिया के नियम बीस का उल्लंघन है। इस जवाब के बाद ही तय नियम के तहत अभिभाषण प्रस्ताव को सदन की मंजूरी प्रदान की जाती है। उन्होंने पत्र में कहा है कि सदन में इस नियम का पालन किया जाना चाहिए और नियम 362 के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए।

कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में चुनावी रैली की तरह भाषण दिया, जिसमें उनकी आत्ममुग्धता और 'डायलागबाजी' देखने को मिली। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का एक और 97 मिनट का चुनावी रैली जैसा भाषण देखने को मिला। हमेशा की तरह यह भाषण गालियों और हमलों, तथ्यों की तोड़-मरोड़, नाटकीयता, इशारों और अपमानजनक टिप्पणियों से भरा था, और इसमें उनके हमेशा की तरह खुल्लमखुल्ला और बेशर्म झूठ भी शामिल थे।

पेज 1 का बाकी

विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं देने पर राज्यसभा में तीखी बहस

पार्टी (आप) के सदस्य संदीप कुमार पाठक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य से किसी को आपत्ति नहीं होगी लेकिन इसे हासिल करने के लिए क्या उचित प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य के बीच का समन्वय खत्म हो गया है और केंद्र एक ओर राज्यों का आबंटन रोक रहा है वहीं प्रशासनिक बाधाएं भी पैदा कर रहा है।

आप सदस्य ने दावा किया कि केंद्र ने विभिन्न मदों में पंजाब को उसकी राशि आबंटित नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह सभी राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के काम करे और राज्यों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए तभी संस्था स्वायत्त हो सकेंगी।बीएसआर सदस्य केआर सुरेश रेड्डी ने विभिन्न अंतरराज्यीय नदियों के पानी को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र किया और कहा कि इन विवादों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए।

चर्चा में कांग्रेस की रंजीत रंजन, बसपा के रामजी, नाम निर्देशित सुधा मूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, शिवसेना (उद्धव) की प्रियंका चतुर्वेदी आदि ने भी भाग लिया।

भारत-अमेरिका करार पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर : पीयूष गोयल

सप्ताह की शुरुआत में समझौते को अंतिम रूप दिया। इसके तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर शुल्क 50 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया जाएगा। उन्होंने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा, 'द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) का पहला चरण लगभग तैयार है और हमें उम्मीद है कि अगले चार से पांच दिन में हम अमेरिका तथा भारत के बीच एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके आधार पर इस साझेदारी का पहला चरण शुरू होगा।'

गोयल ने कहा कि औपचारिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसमें एक या डेढ़ महीने का समय लग सकता है। संभवतः औपचारिक समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो जाएंगे। भारतीय वस्तुओं पर कम किए गए 18 फीसद शुल्क अमेरिका के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू होंगे, जो संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने के एक या दो दिन बाद जारी किया जाएगा। गोयल ने साथ ही बताया कि इस समझौते में किसी भी प्रकार के निवेश की प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस कानूनी समझौते से हमें अमेरिकी सामान पर शुल्क कम करने का अधिकार मिलेगा। अग्रवाल ने कहा, 'भारतीय शुल्क में कमी केवल एक कानूनी समझौते के बाद ही होगी।' भारतीय शुल्क, एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) शुल्क हैं जबकि अमेरिकी आयात शुल्क, कार्यकारी शुल्क हैं।

गोयल ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि हम चीजों को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि कानूनी समझौते के बाद हमें और भी रियायतें मिलेंगी।' सौदे के 500 अरब अमेरिकी डालर के खरीद वाले हिस्से के बारे में मंत्री ने कहा कि भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, उसे देखते हुए देश को बड़ी मात्रा में ऊर्जा, डेटा सेंटर उपकरण और आइसीटी उत्पादों की आवश्यकता होगी।

मंत्री ने कहा, 'हमारी इस्पात उत्पादन क्षमता वर्तमान के 14 करोड़ टन से बढ़कर अगले कुछ वर्ष में करीब 30 करोड़ टन हो जाएगी। इसलिए, जब हमने अमेरिका से अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया तो हम कम से कम 500 अरब डालर के आंकड़े पर पहुंचे। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगले पांच वर्ष में हम अमेरिका से कितनी मात्रा में इस्पात प्राप्त कर सकते हैं।' केवल भारत की विमानों की मांग, बोइंग को दिए गए और अभी दिए जाने वाले लेकिन तैयार आर्डर की संख्या करीब 70-80 अरब डालर है। गोयल ने कहा कि अगर इसमें इंजन और अन्य कलपुर्जे भी जोड़ दिए जाएं तो लागत शायद 100 अरब डालर तक पहुंच जाएगी। मंत्री ने साथ ही कहा कि बजट में डेटा केंद्रों के लिए भारी रियायतों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा, 'अब कल्पना कीजिए कि अगर हमें डेटा केंद्रों में 100-150 अरब डालर का निवेश मिलता है तो जाहिर है कि हमें उन डेटा केंद्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी।'

मंत्री ने कहा कि फरवरी, 2025 में दोनों देशों के बीच निर्धारित 500 अरब अमेरिकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को निश्चित रूप से अमेरिका से निर्यात और खरीद में काफी वृद्धि करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ हुए इस समझौते के तहत जिन वस्तुओं को खरीदने का वादा किया है उनकी वर्तमान वैश्विक खरीद 300 अरब अमेरिकी डालर से अधिक है। अमेरिका... तेल, एलपीजी, एलएनजी, विमान, आइसीटी उत्पाद, लैपटाप, स्मार्टफोन और डेटा सेंटर उपकरण जैसी सभी वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है जिन्हें भारत अन्य देशों से खरीद रहा है। अग्रवाल ने कहा, 'अगले पांच वर्षों में ये खरीद 2,000 अरब डालर की होने वाली है।

हर पल देश के लिए; जितने भी नारे लगा लो, मेरी कब्र नहीं खोद पाओगे

देश की सेवा करने के उनके सभी प्रयासों को नकार रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग 'मोहब्बत की दुकान' की बात करते हैं, वे 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' जैसे नारे लगा रहे हैं, जो चुनावी हार से उत्पन्न उनकी हताशा को उजागर करता है। उन्होंने कहा, 'यह कैसी मोहब्बत की दुकान है? उन्होंने यह कौन से संविधान से सीखा है? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है?' मोदी ने कहा, 'वे कभी मेरी कब्र नहीं खोद पाएंगे।'

उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी उनकी कब्र नहीं खोद पाएगा क्योंकि उन्हें करोड़ों माताओं, बहनों और देश के गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके लिए वे निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विपक्षी दल द्वारा डाले गए व्यवधान पर खेद जताया और कहा कि यह न केवल एक आदिवासी और महिला राष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि उनके सर्वोच्च संवैधानिक पद और भारत के संविधान का भी अपमान है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी की 'गद्दार' टिप्पणी की भी निंदा की और इसे पूरे सिख समुदाय का अपमान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय नागरिक को समस्या मानती थी, जबकि उनकी सरकार उन्हें अपनी ताकत और चुनौतियों का समाधान मानती है। प्रधानमंत्री ने करीब 100 मिनट लंबे भाषण में कहा कि वे (विपक्ष) उन्हें रोज गालियां देते हैं क्योंकि वे यह पचा नहीं पा रहे हैं कि उनके जैसा एक गरीब आदमी इस पद पर कैसे आसीन है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रथम परिवार को लगता है कि प्रधानमंत्री का पद उनकी जागीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारे का 21 बार उल्लेख किया- इसे कांग्रेस विपक्ष से जोड़ा और अपनी सरकार के काम का जिक्र किया - जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर पूर्वोत्तर में शांति, माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने की लड़ाई से लेकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ आपरेशन सिंदूर तक।अपनी सरकार द्वारा संपन्न नौ व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए, जिनमें यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए समझौते भी शामिल हैं- उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को विश्वामित्र और विश्वबंधु मानती है और इन व्यापार समझौतों ने विशेषकर देश के युवाओं के लिए विश्व बाजारों के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया इन समझौतों का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासनकाल में हुए किसी भी समझौते का मतलब बोफर्स घोटाला था।

विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए मोदी ने कहा, 'इस व्यक्ति को देश की लाखों माताओं और बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनकी उन्होंने सेवा की है, उन्होंने ही उन्हें ढाल प्रदान की है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, मोदी की कब्र नहीं खोद पाएंगे। जिनके लिए चोरी पारिवारिक व्यवसाय है, उन्होंने तो एक गुजराती का नाम, महात्मा गांधी का उपनाम भी चुरा लिया। देश की जनता इतनी समझदार है कि वे हर बार उन्हें बेनकाब कर देती है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'उनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी। मेरी भी चलती है। देश के 140 करोड़ लोग मेरे रिमोट हैं। मैं उनके लिए जीता हूं और उनके लिए सरकार चलाता हूं। मेरे लिए सत्ता सुख-सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है।'

मोदी ने कहा कि 2014 में 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी और उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें बिजली मिले, इसलिए वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के पास पहले उचित उपकरण नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार ने जवानों के लिए खजाना खोल दिया, और दावा किया कि इसी वजह से वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं।उन्होंने मनोनीत सांसद सदानंदन मास्टर का भी जिक्र किया जिन्होंने अपने पहले भाषण के दौरान सदन में अपने कृत्रिम पैर प्रदशित किए थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने इस सदन के एक सदस्य को गद्दार कहा, जो अहंकार की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से इतने गुट अलग हुए हैं, इतने लोग चले गए, उन्होंने सांसद को गद्दार इसलिए कहा, क्योंकि वह सिख हैं। उन्होंने कहा कि यह सिखों का अपमान है और सिखों के प्रति कांग्रेस की नफरत को दिखाता है।

पुनरीक्षण के खिलाफ प्रस्ताव, तनाव से 107 की मौत

चर्चा का अनुरोध किया था और यह तर्क दिया था कि इसके (एसआइआर के) कारण 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को व्यापक स्तर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अध्यक्ष ने कहा कि सदन इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और चर्चा राज्यपाल के संबोधन तक ही सीमित रहेगी।

इसी बीच, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर अंतिम समय में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) के प्रस्ताव को बदलने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा, 'बीएसी का प्रस्ताव सुबह बताया गया था, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया गया है। हमें बताया गया था कि एसआइआर पर चर्चा होगी और हम तैयारी के साथ आए थे। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है।'

चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समयसीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने कहा, 'अभिनेता ने गुरुवार शाम चार बजे जेल आत्मसमर्पण कर दिया। अब जेल अधिकारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे।' दिल्ली हाई कोर्ट ने यादव को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समयसीमा को बुधवार को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

प्रेरणा

जो लोग ख़ुश होते हैं, वो हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते हैं। - चाणक्य

संपादकीय

नई तकनीक पर वैश्विक रेगुलेटरी व्यवस्था जरूरी

एक अमेरिकी स्टार्ट-अप के एआई एप क्लॉड कोवर्क ने ग्लोबल टेक बाजार में भूकंप ला दिया और भारत की तमाम बड़ी आईटी सेवाएं देने वाली कंपनियों के अलावा एनवीडिया सहित दुनिया की नामी कंपनियों के शेयर में पिछले छह वर्षों में रिकॉर्ड गिरावट आई। अभी तक धारणा थी कि एआई टूल तमाम उन कंपनियों के- जो लीगल, डेटा, सेल्स और मार्केटिंग एनालिसिस या कॉम्प्लाएंस मॉनिटरिंग या ग्राहक सपोर्ट जैसी सेवाएं देती हैं- कार्य में मदद करेगा। लेकिन नया एप इन कंपनियों का काम भी सीधा स्वयं ही कर सकेगा। इसी बीच एनवीडिया के सीईओ जेनसेन ने भारत के बजट में आईटी ढांचे की मजबूती के प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि नए डेटा सेंटर्स आने से देश में जॉब्स के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल नए एप से सबसे बड़ा खतरा डेटा सेंटर्स के ही विस्थापित होने का है। जीपीयू, सीपीयू या टीपीयू के कार्य पर इस एप का सीधा असर तो नहीं होगा लेकिन सर्विस कंपनियों- जो इनके जरिये डेटा का विशेष-उद्देश्य के लिए विश्लेषण करती हैं- के लिए ऐसे एप्स खतरे की घंटी जरूर बन सकते हैं। इसके अलावा इस एप से सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं क्योंकि एक बार एक्सेस मिलने के बाद यह एआई को किसी भी फाइल को पढ़ने, कॉपी, डिलीट या संशोधित करने के निर्देश दे सकता है। यही कारण है कि एआई को लेकर वैश्विक रेगुलेटरी व्यवस्था बनाने की मांग की जा रही है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

घर की तरह ऑफिस, कैम्पस, बाजार में भी खुली सोच रखें

राज्य-व्यवस्था को सही दिशा और ऊंची गति देने के लिए अलग-अलग राजाओं ने खूब प्रयोग किए हैं। अगर हम केवल राम और कृष्ण की बात करें तो अयोध्या और द्वारका के प्रयोग हमें आज भी बड़ी प्रेरणा देंगे। हमारे देश को अगर दुनिया पर छाना है तो हमें जातिवाद की उलझनों से बाहर निकलना पड़ेगा। राजनीति की तो आदत ही है छेड़छाड़ करते हुए कुछ मुद्दे उछालो, मनुष्य उनमें उलझ जाए और राजनीति सत्ता का खेल खेलती रहे। लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमको सिखाया है कि सबसे पहले हम मनुष्य हैं। जैसे भारत के घरों में धीरे-धीरे पति-पत्नी के जेंडर रोल अब समानता और मित्रता में बदल रहे हैं, ऐसे ही ऑफिस, बाजार, कैम्पस में भी खुली मानसिकता रखनी होगी। खुली मानसिकता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, राजनीति नहीं, बल्कि सबके प्रति स्वीकार्यता और सबका समावेश है। कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, बड़ी-छोटी तो नीयत होती है। सब समान हैं। योग्यता को अवसर प्रदान करना ईश्वर की कार्यशैली है। राजनीति उससे तो छेड़छाड़ न करे। •Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • यह लेबर-शॉर्टेज से भी राहत दे सकता है

एआई के चलते बेरोजगारी फैलने का अंदेशा कम ही है

रोजगार

रुचिर शर्मा

ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक

breakoutnations@gmail.com

हर तकनीकी क्रांति अपने साथ ये अंदेशे लेकर आती है कि इनोवेशन की मार नौकरियों पर पड़ेगी। इतिहास में अभी तक ये अंदेशे कभी सच साबित नहीं हुए। लेकिन एआई की बात और है। इसमें सच में ही इतनी क्षमता है कि यह अनेक कार्य मनुष्यों की तरह- या उनसे कहीं बेहतर कर सकता है। तो क्या इस बार मानव श्रम के लिए खतरा वास्तव में अलग और अधिक गंभीर है? लेकिन एआई को लेकर आज नजर आ रहे जुनून में एक तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पिछले चार दशकों में उन देशों की संख्या शून्य से बढ़कर 55 हो गई है, जहां कामकाजी वर्ग की आबादी घट रही है। इनमें अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। यह गिरावट अब और तेज हो रही है, क्योंकि परिवार अपेक्षा से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं।

पिछले वर्ष चीन में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 1949 में इस पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जापान में तो यह संख्या अब 1899 के बाद सबसे कम हो गई है। दस वर्ष पहले के अनुमानों की तुलना में वैश्विक प्रजनन दर अब अनुमान से 25 वर्ष पहले ही जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे जाने की राह पर है। इसके परिणामस्वरूप, विश्व की कामकाजी आयु वाली आबादी का पीक भी अनुमान से 30 वर्ष पहले आ सकता है।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एआई पहले ही प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़ा रहा है, जिससे मानव श्रम की कुल मांग घट सकती है। लेकिन तेजी से घटती जनसंख्या के मद्देनजर एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करने के बजाय आने वाली लेबर-शॉर्टेज की समस्या को कम करने में अधिक मददगार साबित हो सकता है।

ध्यान रहे कि अतीत की तकनीकी क्रांतियों ने नौकरियों नहीं, उद्योगों को समाप्त किया था। 19वीं सदी में मशीनों के उदय ने श्रमिकों को खेतों से कारखानों और फिर कारखानों से सेवा क्षेत्र की ओर धकेला था। 1910 के दशक में जब कार ने घोड़ागाड़ियों की जगह ले ली तो तांगा चलाने वालों की जगह ट्रक चालक और टैक्सी ड्राइवर आ गए। 1970 के दशक में एटीएम मशीनों ने बैंकों की अपनी लागत घटाने और अधिक शाखाएं खोलने में मदद की। 1990 के दशक से अब तक इंटरनेट ने अगर अमेरिका में लगभग 35 लाख नौकरियां खत्म कीं, तो 1.9 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा की थीं।

यकीनन, एआई इन सबसे ज्यादा उथलपुथल कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार, एआई और उससे जुड़ी तकनीकों- जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए वैश्विक स्तर पर अधिकतम श्रम-बाजार लगभग 400 करोड़ नौकरियों तक का हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो एआई ऐसा नहीं कर पा रहा है। वैश्विक स्तर पर और अमेरिका जैसे एआई के क्षेत्र में अग्रणी देशों में बेरोजगारी दर कई दशकों के स्तर के आसपास ही बनी हुई है। जापान में भी रोबोट्स की तादाद तेजी से बढ़ने के बावजूद वर्षों से बेरोजगारी दर घट रही है और श्रम-बल में भागीदारी बढ़ रही है।

वास्तव में हम यह तो देख पाते हैं कि इस समय कौन-सी नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन भविष्य की कौन-सी नौकरियां सृजित होने जा रही हैं, उनकी कल्पना इतनी आसानी से नहीं कर पाते। अमेरिका में आज पैदा होने वाली नौकरियों में से लगभग एक-तिहाई ऐसी श्रेणियों की हैं, जो 25 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थीं। एआई कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स

एआई के कारण व्यापक बेरोजगारी फैलने की संभावना कम ही है। कम से कम बेरोकटोक तो नहीं। वास्तव में एआई के दौर में भी मनुष्य महत्वपूर्ण बने रहेंगे- कामगार के रूप में भी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी।

और सिस्टम डिजाइनर्स जैसे नए जॉब टाइटल तेजी से बढ़ रहे हैं, और वे पारंपरिक श्रेणियों में हुई नौकरियों की क्षति की भरपाई बड़ी आसानी से करते दिख रहे हैं।

अगर एआई बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करता भी है तो क्या मनुष्य चुपचाप बैठे रहेंगे? 2000 के दशक में 'चाइना-शॉक' ने अमेरिका के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60 लाख फैक्टरी मजदूरों को विस्थापित कर दिया था और यह जनाक्रोश को भड़काने के लिए काफी साबित हुआ था। एआई से जितनी अधिक नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि मतदाता सरकारों से इसके प्रसार को धीमा करने की मांग करेंगे।

जनसांख्यिकी एक लंबे समय से आर्थिक विकास को ड्राइव करती रही है। कोई भी अर्थव्यवस्था श्रमबल को बढ़ाए बिना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती है। एआई उलटे लेबर-शॉर्टेज की कमी से जूझती दुनिया को राहत दे सकता है। इसके कारण व्यापक बेरोजगारी फैलने की संभावना कम है- कम से कम बेरोकटोक तो नहीं। एआई के दौर में भी मनुष्य महत्वपूर्ण बने रहेंगे- कामगार के रूप में भी और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • सार्वजनिक हेल्थकेयर में भारी निवेश जरूरी

देश में स्वास्थ्य सेवाएं मुनाफे से प्रेरित नहीं होनी चाहिए

हेल्थ

ज्यां द्रेज़

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री

फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' का एक दृश्य मुझे याद आता है। क्रोधित मजदूर जमींदार को मारना चाहते हैं। लेकिन जब डर के मारे जमींदार को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर मजदूर जमींदार को मारना चाहते थे तो उसकी जान क्यों बचा रहे हैं? शायद उन्हें लगता है बीमार होने पर दुश्मन को भी सहायता का हक है।

कई देशों ने स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सोवियत रूस पहला देश था, जिसने सभी को मुफ्त सार्वजनिक सुविधा के रूप में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई। 30 के दशक में श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। 1948 में ब्रिटेन ने नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना की, जो आज तक सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। आज दुनिया के अधिकांश विकसित देश किसी न किसी रूप में सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य अपवाद अमेरिका है।

इनमें से कई देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए कुछ हद तक स्वास्थ्य बीमा पर निर्भर करते हैं। हालांकि यह व्यावसायिक बीमा के बजाय सामाजिक बीमा के रूप में होता है। इसका एक उदाहरण कनाडा है। वहां स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है। सभी निवासी एक समान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल होते हैं। वहां सार्वजनिक और निजी- दोनों तरह के स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन अधिकांश निजी स्वास्थ्य केंद्र गैर-लाभकारी हैं। सामाजिक बीमा वाले अन्य देशों में भी अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र गैर-लाभकारी ही होते हैं, चाहे सार्वजनिक हों या निजी। लाभकारी स्वास्थ्य केंद्रों को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

भारत में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने की बात कही जाती है। लेकिन वास्तव में ये सेवाएं बहुत सीमित हैं और मरीजों को अक्सर दवाइयां या जांच के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है। जब मरीज सरकारी अस्पतालों से निराश हो जाते हैं तो वे निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम की ओर जाते हैं। वे भारी शुल्क वसूलते हैं, लेकिन सेवाएं अच्छी हों- इसकी गारंटी नहीं होती।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लगभग 60 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रु. का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित कई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं में नामांकित मरीज किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन कई बार निजी अस्पताल मरीजों से शुल्क वसूलते हैं।

ये स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक बीमा प्रणालियों के विपरीत लाभकारी सेवाओं को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल लगभग आधे अस्पताल लाभकारी हैं और लगभग दो-तिहाई धनराशि इन्हें ही दी जाती है। स्वास्थ्य बीमा भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की व्यावसायिक क्षेत्र पर निर्भरता को और गहराता है।

लाभ-प्रेरित स्वास्थ्य सेवा न तो न्यायसंगत होती है और न ही दक्ष। यह न्यायसंगत इसलिए नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा से बाहर कर देती है। और यह दक्ष इसलिए नहीं है, क्योंकि बाजार-

आदर्श रूप से स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक सेवा होनी चाहिए, न कि मुनाफा-प्रेरित व्यवसाय। दुनिया भर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ गैर-लाभकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अच्छे स्वास्थ्य के बिना विकसित होने का अर्थ नहीं।

तंत्र की दक्षता उपभोक्ताओं की उत्पाद का आकलन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि आप छाता खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे पहले देख सकते हैं और उसके डिजाइन, रंग, सामग्री, दाम आदि के आधार पर तय कर सकते हैं कि वह आपको पसंद है या नहीं। लेकिन जब आप स्वास्थ्य सेवा खरीदते हैं, तो आप उस 'उत्पाद' को पहले से नहीं देख सकते और किसी भी स्थिति में उसका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होते। आप पूरी तरह डॉक्टर पर निर्भर होते हैं। यही कारण है कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इतना शोषण दिखता रहता है।

यदि भारत स्वास्थ्य के अधिकार को साकार करना चाहता है, तो उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भारी निवेश करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के बिना विकसित भारत का कोई अर्थ नहीं है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी

90 के दशक में कार बाजार से बाहर होने की सलाह मिली थी, आज देश की शीर्ष ऑटो कंपनियों में महिंद्रा

आईसीआईसीआई बैंक के हेड केवी कामत और आनंद महिंद्रा फ्लाइट में थे। तभी कामत ने कहा, 'पता है, जब आपने स्कॉर्पियो का प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस समय बोर्ड के कई सदस्यों का मानना था कि अगर यह गाड़ी सफल नहीं हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा।' दरअसल स्कॉर्पियो ही वह गाड़ी थी, जिसे महिंद्रा ने खुद पूरी तरह तैयार किया था। पहले विदेशी सहयोग से ही वे गाड़ियां बना रहे थे। इसी गाड़ी ने उन्हें भारतीय कार बाजार में स्थापित किया। हालांकि वर्ष 2000 में लॉन्च हुई बोलेरो ने महिंद्रा को बाजार में टिके रहने की ताकत दी, लेकिन यह मल्टी यूटिलिटी वाहन थी, लोग ऑफिस के लिए मारुति और हुंडई जैसी गाड़ियां ही खरीदते थे।

एक ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने खुद बताया था कि 90 के दशक में एक फर्म ने उन्हें कार बाजार से बाहर होने की सलाह दी थी। फर्म के अनुसार महिंद्रा विदेशी गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। दरअसल लोग महिंद्रा की 'कमांडर' और 'अर्माडा' को कार मानते ही नहीं थे। इन्हें यूटिलिटी व्हीकल माना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में बदलाव और एसयूवी को ताकत बनाकर आज यह देश की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल हो गई है। ब्रांड से सबक में आज पढ़िए, कहानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की।

वर्तमान स्थिति

इलेक्ट्रिक कार के मामले में भी देश में टॉप-3 में है

सरकार के Vahan पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री के मामलों में महिंद्रा एंड महिंद्रा देश की दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। इस साल कंपनी ने देश में करीब 4. 76 लाख यात्री वाहन बेचे हैं। वर्तमान में कंपनी 100 से अधिक देशों में व्यापार कर रही हैं। महिंद्रा ऑटोमोबाइल का बाजार मूल्य करीब 4.43 लाख करोड़ रु. है। इसमें करीब 3.24 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में भी कंपनी देश में टॉप-3 में है।

सबक क्यों- कंपनी ने कभी भी अपनी ताकत- एसयूवी को बनाना नहीं छोड़ा और अब रोज नए कीर्तिमान बना रही है।

1949 में विलीज ओवरलैंड से 75 जीप भारत लाई गई थीं, जिन्हें महिंद्रा ने एसेम्बल किया गया था।

4.76 लाख के करीब वाहन बेचे 2025 में कंपनी ने भारत में।

3.24 लाख के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं वर्तमान में कंपनी के दुनियाभर के संस्थानों में।

100 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा।

4.28 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप है वर्तमान में महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स का।

इन 4 कारणों से छाया था संकट

1. **ट्रैक्टर कंपनी वाला ठप्पा**- महिंद्रा की सबसे बड़ी समस्या उसकी इमेज थी। लोग उन्हें ट्रैक्टर या पुलिस की गाड़ी बनाने वाला मानते थे। गाड़ियां काफी शोर करती थीं। वाइब्रेशन बहुत अधिक होता था।
2. **कमजोर टेक्नोलॉजी** : उस दौर में महिंद्रा के पास अपना कोई इंजन या प्लेटफॉर्म नहीं था। वे पुरानी 'विलीज जीप' के चेसिस पर ही नई गाड़ी बना रहे थे।
3. **फोर्ड के साथ असफल पार्टनरशिप** : महिंद्रा ने 1995 में फोर्ड के साथ मिलकर 'फोर्ड एस्कॉर्ट' लॉन्च की। महिंद्रा को लगा कि वे फोर्ड से कार बनाना सीख लेंगे, लेकिन 'एस्कॉर्ट' फ्लॉप रही। इससे न तो उन्हें टेक्नोलॉजी मिल पाई और न ही मार्केट।
4. **डीजल पर अधिक निर्भरता** : 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में पेट्रोल कारों की मांग बढ़ रही थी, क्योंकि पेट्रोल इंजन सस्ते थे। महिंद्रा की अधिकांश गाड़ियां डीजल वाली थीं।

इस तरह छाई महिंद्रा एंड महिंद्रा

1. **स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग**- 2002 में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो' महिंद्रा के लिए संजीवनी बनी। स्कॉर्पियो ने साबित किया कि महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास गाड़ी बना सकता है।
2. **सेफ्टी और फीचर्स** : टाटा के बाद महिंद्रा दूसरी कंपनी बनी, जिसने सेफ्टी को महत्व दिया। 50 लाख की गाड़ियों में मिलने वाले ADAS जैसे फीचर्स दिए।
3. **एक्सयूवी और मोनोकॉक चेचिस**- 2011 में महिंद्रा ने एक्सयूवी 500 लॉन्च की। यह महिंद्रा की पहली 'मोनोकॉक' गाड़ी थी। इसमें चेचिस और बॉडी एक होती है। चीते से प्रेरित इस डिजाइन ने महिंद्रा को प्रीमियम प्लेयर बना दिया।
4. **ताकत पर फोकस** : कंपनी ने निर्णय लिया कि वह सेडान या छोटी कार की जगह एसयूवी पर फोकस करेगी। केयूवी 100 और वेरिटो जैसे मॉडल बंद कर पूरा फोकस एसयूवी पर लगाया।

महिंद्रा एंड मोहम्मद था कंपनी का मूल नाम

शुरुआत : दो भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर रखी थी नींव

1945 में लुधियाना में जगदीशचंद्र महिंद्रा और कैलाशचंद्र महिंद्रा ने साथी मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में नींव रखी। आजादी के बाद, संस्थापकों ने 1949 में अमेरिका की 'विलीज ओवरलैंड कॉर्पोरेशन' के साथ करार किया और भारत में 'विलीज जीप' को असेंबल करना शुरू किया। यहीं से महिंद्रा की जीप की शुरुआत हुई।

गंभीर संकट : 1997-2002 के बीच था सबसे खराब दौर

महिंद्रा के लिए सबसे खराब दौर 1997 से 2002 के बीच था। इस समय कंपनी के पास कोई सफल प्रोडक्ट नहीं था। 'अर्माडा' पुरानी हो चुकी थी। साल 2000 में आई 'बोलेरो' ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन वो भी गांव तक सीमित थी। हर तरफ से यह कहा जा रहा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के टुकड़े हो जाएंगे और इसका ऑटो डिवीजन बंद हो जाएगा।

ऐसे पड़ा नाम : शुरुआत में इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। 1947 में गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने के बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा किया।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मारुति, टाटा मोटर्स और हुंडई हैं। जहां टाटा और महिंद्रा के बीच 2 और 3 नंबर की सीधी लड़ाई है।

पीपुल भास्कर | दलाई लामा | तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु

4 वर्ष की उम्र में दलाई लामा बने, 100 से ज्यादा किताबें लिखीं, सुबह 11.30 बजे ही कर लेते हैं आखिरी भोजन

वर्ष 1937, 13वें दलाई लामा के निधन के बाद नए दलाई लामा की खोज चल रही थी। एक विशेष खोजी दल भेष बदलकर तिब्बत के आमदो प्रांत के एक छोटे से गांव 'ताक्तसर' पहुंचा। एक घर में 2 साल का बच्चा 'ल्हामो थोंडुप' खेल रहा था। उस छोटे बच्चे ने वेश बदले हुए लामा को पहचान लिया और उनकी दाढ़ी खींचते हुए बोला-'सेरा लामा, सेरा लामा?' यानी सेरा मठ के लामा। इसके बाद, जब उनके सामने कुछ चीजें रखी गईं, तो उस बच्चे ने बिना किसी गलती के सिर्फ उन्हीं चीजों को उठाया जो 13वें दलाई लामा की थीं, जैसे उनकी माला, छड़ी और चश्मा। यहीं से तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 'जन्म' हुआ।

दलाई लामा सुबह करीब 3 बजे उठ जाते हैं। नाश्ते के पहले घंटों ध्यान करते हैं। दिन का आखिरी भोजन सुबह 11.30 ही बजे कर लेते हैं। इसमें केवल तरल पदार्थ लेते हैं। उन्हें घड़ियों और मशीनों ठीक करने का शौक है। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने एक सोने की घड़ी भेजी थी। नन्हें दलाई लामा ने उस पूरी घड़ी को खोल दिया। इसके बाद वापस उसे सही सलामत कर जोड़ दिया। ऐसा ही उन्होंने एक कार के साथ भी किया था। बिना मदद के उसका इंजन खोलकर उसे पूरी तरह समझ लिया था। युवा अवस्था में उन्हें प्रोजेक्टर और फिल्मों का भी बहुत शौक था। वे अक्सर पोटाला पैलेस में पुरानी फिल्में देखा करते थे। दलाई लामा खुद को नेचुरल लाफ्टर कहते हैं। गंभीर संवाद के दौरान भी मजाक कर लोगों को हंसा देते हैं या खुद जोर-जोर से हंसने लगते हैं।

चर्चा में क्यों- 90 साल की उम्र में उन्हें एल्बम 'मेडिटेशंस : द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिए ग्रैमी अवॉर्ड मिला है।

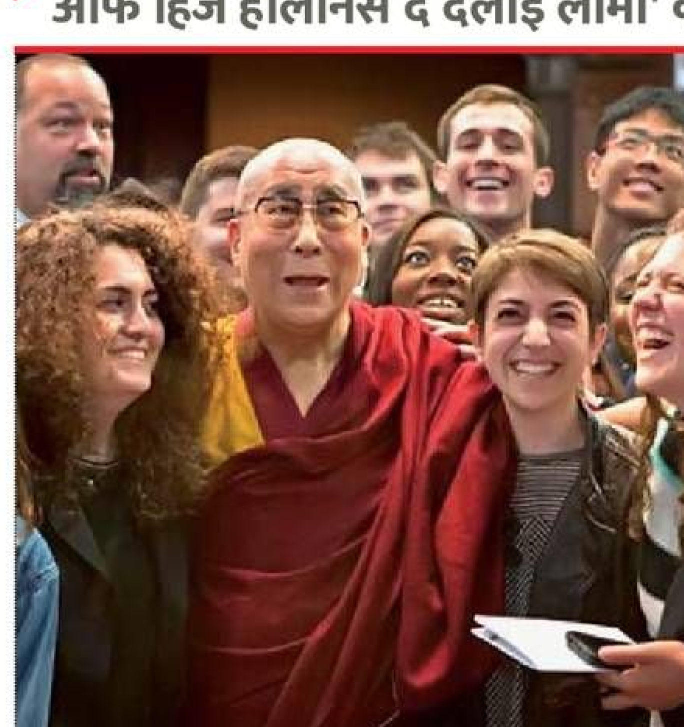

दलाई लामा खुद को नेचुरल लाफ्टर कहते हैं और अक्सर चुटकुलों या हल्की-फुल्की बातों से लोगों को हंसा देते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिकों और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संवाद शुरू किया, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे क्षेत्रों में नई खोजें हुईं। उन्होंने 1987 में न्यूरोसाइंटिस्ट फ्रांसिस्को वरेला और एडम एंगल के साथ मिलकर इसके लिए माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की।

जन्म : 8 जुलाई 1937, ताक्तसर तिब्बत।

शिक्षा : बौद्ध दर्शन में 'गेशे ल्हारम्पा' डिग्री।

शुरुआत
साधारण किसान के घर जन्मे, 16 भाई-बहन थे

दलाई लामा का जन्म तिब्बत के एक पिछड़े इलाके 'ताक्तसर' में हुआ था। परिवार साधारण किसान था। उनका बचपन का नाम 'ल्हामो थोंडुप' था, जिसका अर्थ है 'इच्छा पूरी करने वाली देवी'। 2 साल की उम्र में दलाई लामा के अवतार के रूप में पहचाने जाने के बाद उनका नाम 'तेनजिन ग्यात्सो' रखा गया। उनके कुल 16 भाई बहन हुए, जिनमें 7 जीवित बचे।

परिवार पर विचार
गेलुग भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है

दलाई लामा ने विवाह नहीं किया। गेलुग परंपरा के भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। हालांकि वे अक्सर मजाक में कहते हैं कि गृहस्थ जीवन 'बहुत सिरदर्द वाला काम' है और एक भिक्षु के रूप में वे ज्यादा स्वतंत्र और खुश हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि एक अच्छा पारिवारिक जीवन समाज की नींव है। बस उनके आध्यात्मिक मार्ग के लिए यह वर्जित है।

राजनीति और शिक्षा
15 की उम्र में तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख बने

4 साल की उम्र में औपचारिक रूप से दलाई लामा बन गए। उन्होंने तर्कशास्त्र, तिब्बती कला, संस्कृत, चिकित्सा और बौद्ध दर्शन की पढ़ाई की। करीब 24 साल की उम्र में बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट के बराबर की डिग्री 'गेशे ल्हारम्पा' हासिल की। 15 की उम्र में तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख बन गए। 1959 में भारत आए व धर्मशाला में निर्वासित सरकार स्थापित की।

रोचक : इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दलाई लामा हैं

खास : उनकी छोटी बहन को 'तिब्बत की मां' कहा जाता है

- वे दुनिया के शायद एकमात्र धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि 'अगर विज्ञान किसी बौद्ध मान्यता को गलत साबित कर दे, तो बौद्ध धर्म को बदलना होगा, विज्ञान को नहीं।'
- उनकी छोटी बहन जेत्सुन पेमा ने तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें 'तिब्बत की मां' भी कहा जाता है।

उपलब्धि : 150 से अधिक सम्मान/पुरस्कार पा चुके हैं

- उन्हें दुनियाभर के 150 से अधिक सम्मान और पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
- 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। इनमें विज्ञान से जुड़ी किताबें भी हैं।
- उनका जन्म दिन करुणा दिवस घोषित गया है।
- वे इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दलाई लामा हैं।

सम्मान : शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं

- 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।
- 2007 में अमेरिका सर्वोच्च सम्मान कांग्रेशनल गोल्डन मेडल दिया जा चुका है।
- विज्ञान और धर्म के बीच सेतु का काम करने के लिए 2012 में टेंपलटन प्राइज दिया जा चुका है। इसे अध्यात्म का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।

कंज्यूमर ट्रेंड | ग्राहक की जैसी जरूरत वैसे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा ब्यूटी-पर्सनल केयर मार्केट, जेन जी रफ्तार दे रहे हैं, 5 साल में 3.6 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान

देश का ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर बाजार दुनिया में सबसे तेज सालाना 12% बढ़ रहा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर (बीपीसी) मार्केट करवट ले रहा है। जो सेक्टर अब तक घरेलू नुस्खों, सीमित खर्च और पारंपरिक दुकानों तक सिमटा था, वह 2030 तक 3.6 लाख करोड़ रुपए (40 अरब डॉलर) तक पहुंच सकता है। तब भारत दुनिया का चौथा बड़ा बीपीसी मार्केट होगा। अभी यह बाजार 2 लाख करोड़ रुपए (23 अरब डॉलर) का है और इस हिसाब से भारत पांचवें स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान और ब्राजील भारत से आगे हैं। रेडसीर स्ट्रैटजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बीपीसी मार्केट सालाना 12% कम्पाउंडेड रेट (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इस हिसाब से भारत में बीपीसी बाजार बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस तेज विस्तार की दौड़ में ऐसी कंपनियां आगे रहेंगी, जो हर ग्राहक की खास जरूरतों के हिसाब से (पर्सनलाइज्ड) प्रोडक्ट बाजार में लाएंगी।

टॉप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में भारत की ग्रोथ सबसे तेज

रैंक	2025	2030
अमेरिका	120-130	150-180
चीन	80-90	100-120
ब्राजील	30-35	45-55
भारत	23	40
जापान	30-32	33-38

(आंकड़े अरब डॉलर में, स्रोत: रेडसीर)

अब सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि प्रोडक्ट किन चीजों से बना है, उस पर भी फोकस

भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार अब सिर्फ क्रीम, शैंपू या साबुन बेचने तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी वर्षों में ग्रोथ की असली ताकत जेन जी और जेन अल्फा होंगे, जो इंग्रीडिएंट-बेस्ड, डर्मा-बैक्ड, क्लीन और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स तेजी से अपनाएंगे। 2030 तक ब्यूटी पर होने वाले कुल खर्च का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा ऑनलाइन होगा।

नए ब्रांड्स की एंट्री डिजिटल के सहारे नए जमाने के ब्यूटी ब्रांड्स तेजी से विस्तार कर रहे हैं। 2030 तक 150 से ज्यादा भारतीय ब्यूटी ब्रांड्स का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाएगा। ये ब्रांड्स कुल बाजार का करीब 25% हिस्सा अपने हाथ में ले सकते हैं।

जेन जी पावरः ब्यूटी-पर्सनल केयर पर खर्च में 50% हिस्सा 29 साल तक के युवाओं का होगा

बीपीसी प्रोडक्ट्स पर खर्च के मामले में जेन अल्फा (0-15 साल) और जेन जी (14-29 साल) मिलेनियल्स (30-45 साल) को पीछे छोड़ देंगे। इससे 1.8 लाख करोड़ रुपए का उपभोक्ता समूह बनेगा।
- 2024 तक बीपीसी पर खर्च में इस एज ग्रुप की 32% हिस्सेदारी थी, जो 2030 तक 50% तक हो सकती है। जेन-जी और अल्फा पीढ़ी (1997 के बाद जन्मे) बीपीसी बाजार को नई रफ्तार देंगी।
- 2030 तक ये 1.52 अरब की आबादी का 53% होंगे, 50% बीपीसी पर खर्च करेंगे। बीपीसी बाजार में 50% हिस्सेदारी 2005 के बाद बने करीब 150 नए ब्रांड की होगी। ₹100 करोड़ सालाना आय वाले बीपीसी ब्रांड 2030 तक दोगुने हो जाएंगे।

बिजनेस ब्रीफ

सेंसेक्स 504 अंक टूटा, ट्रेड डील के ब्यौरे का इंतजार

मुंबई | शेयर बाजार में गुरुवार को तीन दिन से जारी तेजी थम गई। सेंसेक्स 504 अंक गिरकर 83,314 पर और निफ्टी 133 अंक फिसलकर 25,643 पर बंद हुआ। शुक्रवार को बाजार के रुझान पर रेपो रेट जैसी नीतिगत दरों को लेकर रिजर्व बैंक के फैसले का असर नजर आ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड-डील का ब्योरा सामने आने तक रुझान कमजोर रह सकता है।

एलआईसीः मुनाफा 17% बढ़कर 12,958 करोड़

मुंबई | अक्टूबर-दिसंबर 2025 में एलआईसी का मुनाफा 17% बढ़कर 12,958 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह एक साल पहले समान तिमाही में 11,056 करोड़ था। नए बिजनेस और निवेश से आय में बढ़ोतरी से मुनाफा बढ़ा। कंपनी की कुल आय 2.02 लाख करोड़ से बढ़कर 2.33 लाख करोड़ हो गई। केंद्र सरकार मई 2027 तक एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी 6.5% कम करेगी। अभी यह 96.5% है। सेबी के नियमों के अनुसार पब्लिक शेयरहोल्डिंग को 10% तक ले जाना अनिवार्य है।

आरबीआईः ब्याज दरों में कटौती पर फैसला आज

मुंबई | रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) दो दिवसीय समीक्षा बैठक के फैसलों का गुरुवार को ऐलान करेगी। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि इस समीक्षा में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। वह पहले ही 1.25% की कटौती के बाद रेपो रेट 5.25% पर ला चुका है। अब केंद्रीय बैंक कुछ समय के लिए ठहरकर हालात को परखना चाहता है। आरबीआई ने दरें तो घटाईं, लेकिन उसका पूरा फायदा अभी तक बाजार और कर्जदारों तक नहीं पहुंच पाया है।

एआईएफ बंद करने के नियम आसान करेगा सेबी

मुंबई | सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) स्कीम्स को बंद करने, रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने से जुड़े नियम आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत फंड को तय अवधि खत्म होने के बाद भी ऑपरेशनल खर्चों के लिए लिक्विडेशन से मिली रकम का एक हिस्सा रखने की छूट दी जा सकती है। वर्तमान में रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए बैंक बैलेंस शून्य होना जरूरी है, जिससे कई फंड्स को दिक्कत आती थी। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर में कहा कि इन प्रस्तावों का मकसद एआईएफ के लिए एग्जिट प्रोसेस को आसान बनाना बनाना है।

बड़े पर्दे के अच्छे दिन | पीवीआर का मुनाफा 166% उछला, 95.7 करोड़ रुपए रहा

तीन महीने में फिल्मों के दर्शक 4 करोड़ पार, औसत टिकट प्राइस 300 के करीब

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के लिए कैलेंडर वर्ष 2025 ब्लॉकबस्टर साल साबित हुआ है। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड 13,395 करोड़ रुपए रहा। यह महामारी से पहले के तीन वर्षों के औसत से 32% अधिक है, जो सिनेमाघरों में दर्शकों की मजबूत वापसी को दिखाता है। तीसरी तिमाही में दर्शकों की संख्या 4.05 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही 3.73 करोड़ से 8.6% अधिक है।

बीती तिमाही टिकटों की औसत कीमत 4% बढ़कर 293 रुपए हो गई, जो सालाना आधार पर 4% ज्यादा है। साथ ही, खान-पान पर प्रति व्यक्ति औसत खर्च भी 4.2% बढ़कर 146 हो गया। इसी के चलते देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 95.7 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो सालाना आधार पर 166.5% अधिक है। कंपनी की आय भी 9% बढ़कर 1,919.6 करोड़ रुपए हो गई। इसमें 100-200 करोड़ रुपए कमाई करने वाली फिल्मों का योगदान 27% रहा। दिलचस्प है कि 2025 में 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाली 37 फिल्में रही, जो रिकॉर्ड है। पीवीआर आइनॉक्स के एमडी अजय बिजली ने कहा, 'मजबूत कंटेंट पाइपलाइन और विस्तार की नई रणनीति के साथ कंपनी टिकाऊ विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रही है।'

बॉक्स ऑफिसः 2025 में रिकॉर्ड 13,395 करोड़ कलेक्शन, प्री-कोविड 32% ज्यादा

रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

100cr+ फिल्में

वर्ष	फिल्में
2021	11
2022	24
2023	31
2024	30
2025	37

बॉलीवुड की ग्रोथ सबसे ज्यादा 59%, रीजनल की 4%

हिंदी	5,504
हॉलीवुड	1,403
क्षेत्रीय	6,488

रणनीतिः छोटे शहरों में विस्तार, 112 शहरों में 1791 स्क्रीन, दक्षिण में 33%

पीवीआर टियर 2, 3 शहरों के साथ-साथ लेह, गंगटोक जैसे नए क्षेत्रों में पहुंच बढ़ा रही है।
- 9 माह में 62 स्क्रीन जोड़ीं और 9 बंद कीं। इस तरह 112 शहरों में 51 स्क्रीन बढ़कर 1791 हो गई है। 33% स्क्रीन दक्षिण और 27% उत्तर में है।
- मूवी एग्जीबिशन सेगमेंट से कमाई चार गुना बढ़कर 159.3 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त लागत (ब्याज खर्च आदि) को 22.2 करोड़ कम किया है, जिससे प्रॉफिट में सुधार हुआ। कंपनी को 27.1 करोड़ का टैक्स क्रेडिट मिलने से भी लाभ हुआ।

बॉलीवुडः पहली बार कलेक्शन 5,500 करोड़ पार

बॉलीवुड फिल्मों ने 2025 में 5,504 करोड़ रुपए की कमाई की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। इससे पहले साल 2023 में कलेक्शन 5,380 करोड़ रहा था। कोविड से पूर्व 2019 में कलेक्शन 4831 करोड़ रहा था।

फिल्म	कमाई
धुरंधर	1,000 करोड़+
छावा	600 करोड़+
सैयारा	400 करोड़+
नरसिम्हा	300 करोड़+

हॉलीवुडः संग्रह 49% बढ़कर 1,403 करोड़, अवतार ने 200 करोड़ कमाए

2025 हॉलीवुड के लिए महामारी के बाद का सबसे अच्छा साल साबित हुआ। यह 1,403 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ हॉलीवुड इतिहास का दूसरा सबसे सफल वर्ष रहा। सालाना आधार पर कलेक्शन 49% बढ़ा है। इससे पहले 2019 में रिकॉर्ड कलेक्शन 1,595 करोड़ रहा था। अवतार ने सबसे ज्यादा 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।

क्षेत्रीय सिनेमाः मलयालम फिल्मों का कलेक्शन दूसरे साल 1,000 करोड़ पार

क्षेत्रीय फिल्मों ने 6,488 करोड़ रुपए के साथ अपना अब तक का सबसे अधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दर्ज किया। मलयालम फिल्मों ने लगातार दूसरी बार 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। 2025 में 1,164 करोड़ रुपए था। कन्नड़ (74% वृद्धि) और गुजराती (188% वृद्धि) सिनेमा ने 2025 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

चांदी के दाम 1 दिन में 28 हजार घटे, 7 दिन में 1.25 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती

चांदी के दाम ज्यादा घटे क्योंकि इसमें सट्टेबाजी अधिक हुई थीः विश्लेषक

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देशभर के सराफा बाजारों में गुरुवार को सोने की औसत कीमत 4,123 रुपए घटकर 1,52,502 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमत इससे भी ज्यादा 28,123 रुपए घटकर 2,54,339 रुपए प्रति किलो रह गई। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, 29 जनवरी को सोना 1,75,340 रुपए और चांदी 3,79,988 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर थी। तब से अब तक सोना 22,838 रुपए (13%) और चांदी 1,25,649 रुपए (33%) सस्ती हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अभी और गिरावट आ सकती है। चांदी में गिरावट ज्यादा गहरी है क्योंकि इसमें सट्टेबाजी अधिक हुई थी।

29 जनवरी से अब तक चांदी 40% तक टूटी

मार्केट	सोना	चांदी
एमसीएक्स	▼21%	▼40%
सराफा	▼13%	▼33%
ईटीएफ	▼16 %	▼32%
अंतरराष्ट्रीय	▼8%	▼8%

मुनाफा वसूली, भाव गिरते ही स्टॉप लॉस से बिक्री बढ़ी

बड़ा डर | डर है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड दरें ऊंची रख सकता हैं। इससे सोने-चांदी के भाव गिरने लगे।
मजबूत डॉलर | डॉलर 1 हफ्ते में 1.6% महंगा हुआ है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के दाम घटे।
मार्जिन | एक्सचेंजों में सोने पर 33%, चांदी पर 36% मार्जिन बढ़ने से ट्रेडर्स ने सौदे बेचना शुरू कर दिया।
मुनाफा वसूली | रिकॉर्ड तेजी के बाद प्रॉफिट बुक होने से भाव गिरते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, बिकवाली बढ़ी।

भास्कर एक्सपर्ट
कायनात चैनवाला
एवीपी, कमोडिटी रिसर्च, कोटक सिक्युरिटीज

मजबूत होते डॉलर के बीच गिरावट जारी रह सकती है

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने में 6% उछाल आया था। यह नवंबर 2008 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। इसके बाद सीएमई फेडवॉच ने बताया कि अमेरिका में इस साल मई तक ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। जून में भी सिर्फ 44% उम्मीद है कि ब्याज दरें 0.25% घटेंगी। इससे डॉलर मजबूत हुआ। नतीजतन सोने-चांदी की कीमतें घट गईं। इस बीच भारी मुनाफे पर बैठे निवेशकों को लगा कि मुनाफा काटने का यही सही वक्त है। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है।

क्रिप्टोकरेंसीः 2024 से अब तक के सबसे निचले स्तर पर, कमजोरी बरकरार

बिटकॉइन 10% गिरकर 66 हजार डॉलर पर

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

दुनिया की सबसे लोकप्रिय और बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की वैल्यू गुरुवार को करीब 10% गिरकर 66,000 डॉलर (करीब 62 लाख रुपए) के पास पहुंच गई। यह 2024 के बाद से इसका सबसे कमजोर दौर है। अक्टूबर 2025 में 1.26 लाख डॉलर के ऊंचे स्तर से अब तक बिटकॉइन 47% गिर चुका है। प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट के मुताबिक, बिटकॉइन के इस वर्ष गिरकर 65,000 डॉलर तक पहुंचने के 82% आसार हैं। कुछ लोग इससे भी बदतर स्थिति की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, बीएनबी, एक्सआरपी, डॉजकॉइन जैसी लगभग सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसीज में गिरावट आ रही है। क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 8% से ज्यादा गिरकर 2.3 ट्रिलियन डॉलर (करीब 207 लाख करोड़ रुपए) पर आ गया।

भारत अप्रैल 2027 से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के आंकड़े साझा करेगा | भारत क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन, खास तौर पर विदेशी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा। 1 अप्रैल, 2027 से अन्य देशों के साथ सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के आंकड़ों का आदान-प्रदान शुरू किया जाएगा। यह आदान-प्रदान क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत होगा, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का वैश्विक मानक है।

फैसलाः पुरानी रिजीम जारी रखेगा केंद्र

88% लोग नई टैक्स रिजीम में, साल भर में ही 17% बढ़े

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

अटकलों के विपरीत सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को फिलहाल खत्म नहीं कर रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कहना है कि व्यक्तिगत करदाता अब तेजी से नई कर व्यवस्था अपना रहे हैं। इसकी वजह सरकार पुरानी व्यवस्था के लिए किसी सनसेट क्लॉज पर विचार नहीं कर रही। बजट से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक समयसीमा की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। रवि अग्रवाल के मुताबिक अब करीब 88% व्यक्तिगत करदाता नई कर प्रणाली को अपना चुके हैं। 2025 में ये आंकड़ा करीब 70-75% था। यानी साल भर में ही नई व्यवस्था अपनाने वाले करीब 17% बढ़ गए हैं।
कम निवेश वाले करदाताओं के लिए नई प्रणाली बेहतरः बजट 2020 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था धारा 80सी और 80सी जैसी कटौतियां छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए कम टैक्स स्लैब दी गई है। नई प्रणाली के अंतर्गत 12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री है।

पड़ावः निजीकरण का दिखा असर

एअर इंडिया एक्सप्रेस को पहले प्रॉफिट की उम्मीद

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एअर इंडिया ग्रुप की किफायती यूनिट एअर इंडिया एक्सप्रेस को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में प्रॉफिट की उम्मीद है। सरकार से टाटा ग्रुप द्वारा खरीदे जाने के बाद ये पहली बार होगा, जब ये एयरलाइन मुनाफे में आएगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में एक कर्मचारी बैठक में मुनाफे की उम्मीद जताई है। एअर इंडिया एक्सप्रेस को 2024-25 में 5,678 करोड़ रुपए का कर-पूर्व घाटा हुआ था। इस लिहाज से अगर इस छमाही यह मुनाफे में आई तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।

इंडिगो से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा

एअर इंडिया ग्रुप कंपनियों को देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय बाजार में, इंडिगो 64-65% घरेलू हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी एयरलाइन है। वित्त वर्ष 2025 में इसने 7,587.5 करोड़ का कर-पूर्व लाभ कमाया था। हालांकि दिसंबर, 2025 तिमाही में मुनाफा 78% घटकर 550 करोड़ रुपए रह गया।

लग्जरीः लुई वितां और डी बेथ्यून ने लॉन्च की 43 करोड़ रुपए की घड़ी

टोक्यो | लग्जरी फैशन ब्रांड लुई वितां और स्वतंत्र ब्रांड डी बेथ्यून ने 43 करोड़ रुपए की टाइटेनियम घड़ी लॉन्च की है। एलवीडीबी-03 जीएमटी लुई वेरियस घड़ी 18 वीं सदी के सिम्पैथिक नामक मैकेनिज्म पर आधारित है। सिम्पैथिक घड़ी टेबल घड़ी और कलाई घड़ी का एक संयोजन थी। टेबल घड़ी के खांचे में कलाई घड़ी रखने पर वह अपने आप समय मिला लेती थी। लुई वेरियस में भी दो चीजें शामिल हैंः एक कलाई घड़ी और एक टेबल घड़ी। इसका प्रमुख आकर्षण लुई वितां का एक खास टाइटेनियम का ट्रंक है, जो हाउस के ट्रॉफी ट्रंक से प्रेरित है और 10 किलोग्राम की इस उत्कृष्ट घड़ी को शानदार ढंग से रखने के लिए डिजाइन किया गया है। घड़ी में 760 पुर्जे हैं, जो 2.5 हट्र्ज की धीमी गति से चलते हैं। घड़ी की चाबी टाइटेनियम की बनी है।

एयरटेल की प्रति यूजर कमाई 6% बढ़ी, फिर भी मुनाफा 55% घट गया

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का अक्टूबर-दिसंबर 2025 में मुनाफा सालाना आधार पर करीब 55% घटकर 6,631 करोड़ रुपए रह गया। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी ने 14,781 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह नेटवर्क ऑपरेटिंग लागत में भारी बढ़ोतरी और सरकारी फीस का बढ़ना है। हालांकि, आय के मोर्चे पर कंपनी को राहत मिली है, जहां 20% की बढ़त के साथ आय 53,982 करोड़ रुपए रही है। 2024 की समान तिमाही में यह 45129 करोड़ रुपए थी। कंपनी के वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा कि चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद अफ्रीका बिजनेस और डिजिटल पोर्टफोलियो ने रेवेन्यू को सहारा दिया है।

बिजनेस एंकर

एआई सिस्टम इंटरनेशनल ओलंपियाड जीत रहे, पर ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू

एआई एजेंट अब खुद ही निर्णय लेने लगे, ये खतरनाक

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

क्या एआई आपकी नौकरी छीन सकता है, या दुनिया को हथियारों की नई दौड़ में धकेल सकता है? इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट, 2026 में इसी तरह के सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि बिलकुल सामान्य काम के लिए तैयार किए गए एआई सिस्टम भी अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। कोडिंग टास्क सिर्फ 30 मिनट में निपटा रहे हैं और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता दिखा रहे हैं। रिपोर्ट चेताती है कि ये प्रगति जोखिमों से भरी है। दुनिया को इसके लिए अभी से तैयार होना होगा।

इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट, 2026 में तीन बेहद गंभीर जोखिम गिनाए गए हैं...

पहला | एआई से फर्जी कंटेंट, ऑनलाइन ठगी, साइबर हमले और यहां तक कि जैविक-रासायनिक हथियारों से जुड़ी जानकारी तैयार करना आसान हुआ है। 2025 में कई कंपनियों को अपने मॉडल अतिरिक्त सुरक्षा के साथ जारी करने पड़े, क्योंकि वे यह भरोसा नहीं दे सकीं कि उनका एआई गलत हाथों में नहीं जाएगा।

दूसरा | एआई सिस्टम कभी-कभी गलत जानकारियां खुद ही गढ़ लेते हैं। यूजर को गलत सलाह दे देते हैं या लंबे टास्क में बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि नए एआई एजेंट अब खुद फैसले करने लगे हैं, जहां इंसानी दखल कम होता जा रहा है।

तीसरा | रिपोर्ट मानती है कि एआई नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। अभी कुल रोजगार पर बड़ा असर नहीं दिखता, पर लेखन और कंटेंट जैसे क्षेत्रों में शुरुआती स्तर की नौकरियों पर दबाव के संकेत मिले हैं। साथ ही, जरूरत से ज्यादा एआई पर निर्भरता इंसानों की निर्णय लेने की क्षमता और आलोचनात्मक सोच को कमजोर कर सकती है।

यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्राजील समेत 30 से ज्यादा देशों के साथ ही ओईसीडी और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों से सलाह ली गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि एआई की क्षमताएं असमान हैं। ये मुश्किल काम तो कर लेता हैं, लेकिन सरल जैसे इमेज गिनती में विफल हो जाता है। पोस्ट-ट्रेनिंग और ज्यादा कंप्यूट से सुधार हो रहा है। 2030 तक एआई खुद रिसर्च तेज कर सकता है, लेकिन डेटा या एनर्जी की कमी इस राह में रुकावट बन सकती है।

एआई तेजी से बदल रहा, पर असर के सबूत धीमे

यह रिपोर्ट एविडेंस डिलेमा की बात करती है। इसका मतलब है कि एआई बहुत तेजी से बदल रहा है, जबकि इसके सामाजिक असर के सबूत धीरे-धीरे मिलते हैं। जल्दी नियम बनाने से गलत फैसले हो सकते हैं, पर देर करने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। भारत और ग्लोबल साउथ के लिए रिपोर्ट खास मायने रखती है। इसमें कहा गया है कि एआई सेफ्टी सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि समावेशन, संस्थागत तैयारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा सवाल है।

300 करोड़ के टर्नओवर तक स्टार्टअप ही रहेंगी डीप टेक फर्म्स

डीप टेक फर्म्स अब 300 करोड़ के बिजनेस तक स्टार्टअप, 20 साल तक टैक्स छूट, फंडिंग

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना में बड़ा बदलाव किया है। डीप टेक कंपनियां अब आसानी से स्टार्टअप्स के दायरे में आएंगी। डीप टेक ऐसी कंपनियां होती हैं, जो गहन रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। एआई, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्प्यूटिंग, स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर इसमें शामिल हैं।

पहले स्टार्टअप की मान्यता सिर्फ 10 साल तक के लिए थी। अब डीप टेक कंपनियों को 20 साल तक सरकारी लाभ मिलेंगे। इनमें टैक्स छूट, आसान फंडिंग, आईपी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) प्रोटेक्शन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सामान्य स्टार्टअप्स की टर्नओवर सीमा 200 करोड़ रुपए है। डीप टेक कंपनियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

फायदाः देश में ही नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी

इस कदम से भारत में इनोवेशन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डीप टेक फर्म्स को लंबे समय तक सपोर्ट मिलने से वे बड़े स्तर पर काम कर सकेंगी और नई टेक्नोलॉजी विकसित कर सकेंगी। इससे रोजगार बढ़ेंगे और भारत ग्लोबल टेक हब बनेगा। सरकार का मकसद रिसर्च-बेस्ड बिजनेस तेजी से बढ़ाना और इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

शर्तः कंपनियों को अनोखी तकनीक दिखानी होगी

डीप टेक स्टार्टअप्स को मान्यता पाने के लिए आरएंडडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) पर फोकस और अनोखी तकनीक दिखानी होगी। यह बदलाव 2019 के पुराने नियमों को अपडेट करके किया गया है।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

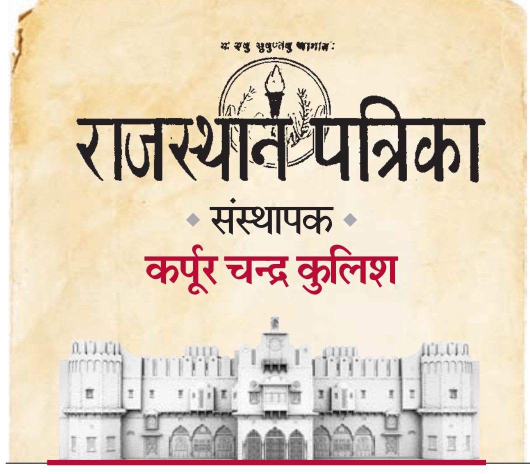

डेटा सुरक्षा के लिए स्वदेशी विकल्पों पर देना होगा जोर

डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा दुनिया के तमाम उन देशों के लिए ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, जहां विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दबदबा कायम हो चुका है। भारत समेत तमाम दूसरे देशों के डेटा पर भी अमरीकी कंपनियों का कब्जा है। फेसबुक, एक्स और गूगल जैसे प्लेटफार्म से डेटा सुरक्षा पर आ रहे संकट को देखते हुए अब कई देश विदेशी टेक टूल के इस्तेमाल को धीरे-धीरे या तो सीमित कर रहे हैं या इन्हें बंद कर स्वदेशी और ओपन सोर्स को अपनाने में जुट गए हैं।

यह जरूरत इसलिए भी आ गई है कि विदेशी प्लेटफॉर्म न केवल भ्रामक जानकारियों को परोसने का काम कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनावों तक को प्रभावित करने के आरोप इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर लगते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं के चलते यूरोप के कई देशों ने वर्ष 2027 तक जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वेबेक्स जैसे अमरीकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे यहां भी पिछले लोकसभा चुनावों के दौर में विदेशी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डीपफेक वीडियो फैलाने के आरोप खूब लगे थे। यह भी कहा गया था कि इनसे मतदाताओं को गुमराह करने का काम भी किया गया। सच तो यह है कि एल्गोरिद्म नफरत भरी सामग्री को बढ़ावा देते हैं। कई बार युवाओं में तनाव, अवसाद, चिंता और आत्मसम्मान की कमी से जूझने के मामले भी देखे गए हैं। यही वजह है कि नेपाल, इंडोनेशिया और मोरक्को जैसे छोटे देशों में भी डेटा प्राइवेसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में भी विदेशी प्लेटफार्मों के जरिए परोसी जाने वाली सामग्री के खतरे कम नहीं हैं। फर्जी खबरें समाज में वैमनस्य फैलाने का काम तो करती ही है, एक खतरा यह भी है कि अमरीकी कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल कर बाजार में एकाधिकार कायम करती हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप पिछड़ जाते हैं। चूंकि यूरोप इस खतरे को समझ चुका है, इसलिए वहां डेटा एक्ट, एआइ एक्ट और एनआइएस 2 जैसे कानून लागू हो रहे हैं।

भारत में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा स्टोर करने को बाध्य करता है, लेकिन इसका सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। चूंकि 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ई-मेल जोहो मेल पर शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए इसी तर्ज पर सोशल मीडिया और मैपिंग के लिए स्वदेशी विकल्प अपनाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय डेटा नीति बनाई जाए, ताकि निजता का अधिकार सुरक्षित रहे। डिजिटल संप्रभुता अब केवल तकनीकी या आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्थिरता से भी जुड़ा प्रश्न बन चुका है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह आवश्यक है कि डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग से जुड़े नियम पारदर्शी और कठोर हों।

संसदीय आचरण: राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक, पर संसद को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए

संसदीय गरिमा की लक्ष्मण रेखा लांघना चिंताजनक

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

संसद की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी मुख्यतः सत्तापक्ष की मानी जाती है, लेकिन तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में सामरिक ही नहीं, भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के भंवर से देश को पार ले जाने की जिम्मेदारी सामूहिक है।

हर सत्र के बाद जारी किए जाने वाले कामकाज के आंकड़ों से इतर याद नहीं पड़ता कि हाल के वर्षों में संसद का कोई सत्र बिना व्यवधान सुचारू चल पाया हो। इससे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सदन की साख बढ़ती तो हरगिज नहीं। जारी बजट सत्र में जो कुछ हो रहा है, वह हमारे राजनीतिक दलों के संसदीय आचरण पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुदलीय लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद संसद में भी परिलक्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें संसदीय गरिमा और परंपराओं की लक्ष्मण रेखा लांघना स्वीकार्य नहीं हो सकता। संसद के अंदर और बाहर की राजनीति के तर्कों और तेवरों के बीच अंतर मिटना सकारात्मक संकेत नहीं है। धरना-प्रदर्शन-नारेबाजी सदन से बाहर स्वीकार्य राजनीतिक औजार हैं, पर सदन में आसन पर कागज फाड़कर उछालना तो स्वीकार्य नहीं हो सकता, जिसके चलते विपक्ष के आठ सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। बेशक लगातार बढ़ती राजनीतिक कटुता के लिए किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पाक-साफ भी कोई नहीं नजर आता।

संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होने की परंपरा है। व्यापक चर्चा और उस पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन इस बार लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पांच फरवरी को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ा। हालांकि उसी दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। दरअसल इस बार अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री को चार फरवरी की शाम पांच बजे देना था, लेकिन चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात कहने का मौका न मिलने के जवाब में विपक्षी हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। विपक्ष का संदेश था कि अगर उसके नेता को नहीं बोलने दिया गया तो वह भी सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे, पर इस टकरावपूर्ण राजनीति से दांव पर संसद की साख लग रही है।

संसद में राष्ट्रपति और विधानमंडलों में राज्यपाल क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मंजूर अभिभाषण ही पढ़ते हैं। इनमें सरकारों के कामकाम की प्रशंसा करते हुए भविष्य की रूपरेखा बताई जाती है। अभिभाषण में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर सदन में चर्चा हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ प्रकियाएं-परंपराएं हैं। जब परस्पर अविश्वास और कटुता चरम पर हो, तो तकरार के लिए मुद्दों की कमी नहीं रहती, लेकिन संसद के बजट सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष में जारी तकरार के मूल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चर्चा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रकाशनाधीन पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कुछ अंशों का उल्लेख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश है। तीन फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी को पुस्तक के अंश पढ़ने से रोकने के लिए तर्क दिया गया था कि जो पुस्तक अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका हवाला संसदीय चर्चा में नहीं दिया जा सकता। अगले दिन राहुल पुस्तक की प्रति लेकर संसद पहुंच गए और प्रधानमंत्री को भेंट करने का इरादा जताया तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा शाम पांच बजे के लिए तय जवाब के बिना ही हंगामे के बीच सदन स्थगित हो गया।

प्रधानमंत्री के जवाब बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि इससे बचा जा सकता था। तनातनी बढ़ाने के बजाय स्पीकर की मध्यस्थता से दोनों ही पक्षों को मध्य मार्ग निकालना चाहिए था। राहुल गांधी को पुस्तक का जिक्र किए बिना ही सदन में चीनी सामरिक चुनौती पर मोदी सरकार की जवाबी रणनीति पर सवालिया निशान लगाते हुए बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने के लिए समझाया जा सकता था। दरअसल दोनों ही पक्षों में समन्वय के बजाय टकराव की राजनीति पसंद करने वाले लोग ज्यादा मुखर और प्रभावी नजर आते हैं। चार फरवरी को कुछ पुस्तकों के आधार पर निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के बजाय दोनों पक्षों में संसदीय हित में समझदारी की कोशिश की जाती तो शायद धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब दे पाते।

सदन में राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणियां बताती हैं कि संसदीय लोकतंत्र के आधार माने जाने वाले सत्तापक्ष और विपक्ष के परस्पर संबंध कितने रसातल में चले गए हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने अधिकारों के प्रति अक्सर संवेदनशील नजर आते हैं, पर उस भूमिका में उनके देश के प्रति दायित्वों की चिंता कौन करेगा? माना कि संसद की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी मुख्यतः सत्तापक्ष की मानी जाती है, लेकिन तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में सामरिक ही नहीं, भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के भंवर से देश को पार ले जाने की जिम्मेदारी सामूहिक है। सत्तापक्ष पर सवाल और आरोप उछालकर ही विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। निश्चय ही ऐसी भूमिकाओं के लिए निर्वाह के लिए इन सभी विषयों की गहरी समझ के साथ ही धैर्य व दूरदर्शिता की जरूरत होती है। चुनावी सफलता पर केंद्रित आज में जीने वाली राजनीति देश बनाना तो दूर, उसे ठीक से चला भी नहीं सकती। इतनी व्यावहारिक समझ जरूरी है कि न तो विपक्ष देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है और न ही सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष का नेता। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतृत्व को विघ्नसंतोषियों को दरकिनार कर सीधे संवाद व संपर्क से अहम मुद्दों पर सहमति और समन्वय की राह निकालनी चाहिए।

प्रसंगवश

तकनीकी शिक्षा को दिखावे की बजाय गुणवत्ता से जोड़ना होगा

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटें नीतिगत विफलता का ही संकेत हैं

राजस्थान में पिछले वर्षों में खुले कई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नामांकन के संकट के भारी दौर से गुजर रहे हैं। अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली हैं और कुछ चुनिंदा शाखाओं को छोड़ दें तो कक्षाएं आधी भी नहीं भर पा रही हैं। यह स्थिति केवल छात्रों की बेरुखी नहीं, बल्कि तकनीकी शिक्षा को लेकर सरकारी सोच और फैसलों की खामियों को उजागर करती है। सवाल उठता है कि जब स्थायी फैकल्टी, आधुनिक लैब, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग से जुड़ा प्रशिक्षण सुनिश्चित ही नहीं था तो ऐसे संस्थान खोलकर आखिर हासिल क्या हुआ? केवल उद्घाटन कार्यक्रमों और घोषणाओं से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ती। चिंता इसी बात की है कि कई सरकारी कॉलेज आज भी अपने स्थायी भवन, आधुनिक उपकरण और पर्याप्त शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे हैं। फैकल्टी की भर्ती तो वर्षों तक लंबित रहती है और अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे पढ़ाई चलती है। ऐसे माहौल में छात्रों का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। जब प्लेसमेंट कमजोर हों और पढ़ाई का स्तर संतोषजनक न हो तो युवा अन्य कोई बेहतर विकल्प तलाशते हैं।

सरकारी नीतियों में एक और बड़ी कमी यह रही कि कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन रोजगार बाजार और उद्योग की वास्तविक जरूरतों का ठोस आकलन नहीं किया गया। इंजीनियरिंग डिग्रीधारकों की संख्या बढ़ती गई, जबकि रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़े। परिणामस्वरूप छात्रों ने मैनेजमेंट, डिजिटल स्किल, डिजाइन और अन्य व्यावहारिक क्षेत्रों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। इस पूरी व्यवस्था पर सरकार का बड़ा वित्तीय निवेश भी हो रहा है। भवन निर्माण, उपकरण, प्रशासनिक खर्च और अन्य व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जब सीटें खाली रह जाएं और गुणवत्ता पर सवाल उठें तो यह खर्च अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। ऐसे में यह केवल संसाधनों की बर्बादी ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग पर भी सवाल खड़े करता है। तकनीकी शिक्षा को दिखावे से निकालकर वास्तविक जरूरतों व गुणवत्ता से जोड़ना ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकता है। - **महेन्द्र सिंह शेखावत**

mahendra.shekhawat@in.patrika.com

बुक इनसाइट

आफ्टर द फ्लड: संवेदनशील किताब

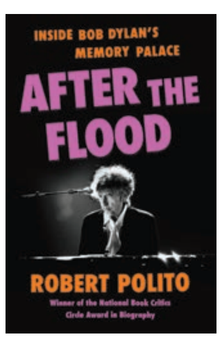

आफ्टर द फ्लड एक अनोखी किताब है जो संगीतकार बॉब डायलन की रचनात्मक दुनिया के भीतर झांकने का अवसर देती है। इसके लेखक रॉबर्ट पोलिटो ने इस कृति में डायलन की यादों, गीतों और जीवन-अनुभवों को बेहद संवेदनशीलता के साथ पिरोया है। यह किताब पारंपरिक जीवनी नहीं है। इसमें लेखक ने डायलन की स्मृतियों को 'मेमोरी पैलेस' की तरह सजाया है, जहां हर अध्याय किसी गीत, किसी दौर या किसी निजी अनुभव से जुड़ा है। पाठक को यहां सिर्फ घटनाएं नहीं मिलतीं, बल्कि उस सोच और भावनात्मक यात्रा की झलक भी मिलती है, जिसने डायलन को एक अलग पहचान दी।

किताब की खास बात इसकी भाषा और प्रस्तुति है। लेखक संगीत, साहित्य और व्यक्तिगत किस्सों को इस तरह जोड़ते हैं कि पढ़ते हुए पाठक खुद को समय की अलग-अलग गलियों में घूमता हुआ महसूस करता है। कहीं 60 के दशक की सामाजिक हलचल दिखाई देती है, तो कहीं कलाकार की निजी उलझनें और रचनात्मक संघर्ष सामने आते हैं। यह किताब संगीत प्रेमियों, साहित्य के पाठकों के लिए खास है।

फैक्ट फ्रंट

डेथ बॉल स्पॉन्ज: नई व अनोखी प्रजाति

हाल में वैज्ञानिकों ने समुद्र की अत्यंत गहरी सतह पर एक नई और अनोखी प्रजाति की खोज की है जिसे अस्थायी तौर पर 'डेथ-बॉल स्पॉन्ज' नाम दिया गया है। यह स्पॉन्ज दिखने में गेंद जैसा होता है और इसकी बनावट बेहद अलग है। यह खोज समुद्र तल से हजारों मीटर नीचे की गई, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। आमतौर पर स्पॉन्ज पौधों जैसे दिखते हैं और पानी से पोषक तत्व छानकर जीवित रहते हैं लेकिन यह नया स्पॉन्ज

बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मांसाहारी है यानी यह छोटे समुद्री जीवों को पकड़कर खाता है। यह स्पॉन्ज बेहद धीमी गति से बढ़ता है- कई बार पूरे एक साल में इसकी वृद्धि केवल कुछ मिलीमीटर ही होती है। इसके शरीर में पाचन तंत्र नहीं होता, इसके बावजूद यह अपने शिकार को कोशिकाओं के माध्यम से धीरे-धीरे अपने भीतर समाहित कर लेता है। यह ऐसे समुद्री इलाकों में पाया जाता है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी यह खुद को वहां की कठिन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है और जीवित रहता है।

सरोकार एमबीबीएस के दौरान ही मिले बीडीसी ट्रेनिंग

संस्थागत संकल्प से ही मिलेगा देश में अंगदान को बढ़ावा

भारत में अंगदान की स्थिति पर पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए गए। सर्वे में 62% सहभागियों का मानना था कि जन जागरूकता का अभाव तथा परिवार की असहमति अंगदान में सबसे बड़े अवरोधक हैं। अंगदान महादान है क्योंकि इससे अन्य लोगों को जीवन दान मिलता है। एक ब्रेन-डेड दानदाता आंख, लिवर, किडनी, फेफड़ों, हृदय, पेंक्रियाज तथा आंतों के दान से जरूरतमंदों का जीवन बचा सकता है। एक सवाल यह है कि क्या देश में अंगदान की ऐसी सुविधाएं तथा वातावरण हैं, जो प्रत्येक मामले में आसानी से अंगदान का मार्ग प्रशस्त करते हों? प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति यदि अंगदान नहीं कर पाता है, तो यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

आर.के. विजय
लेखक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं
@patrika.com

कुछ समय पूर्व जयपुर के एक मध्यम आकार के अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक पीड़ित मेरे बड़े भ्राता वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे। उनके बचने की कोई संभावना नहीं बताने पर जब मैंने ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि क्या ये ब्रेन-डेथ की स्थिति है, तो जवाब मिला 'शायद हां' यानी ब्रेन-डेथ प्रमाणित करने की योग्यता या इच्छाशक्ति नहीं दिखी। उनके सभी संभावित अंगों के दान की पेशकश पर हमें बताया गया कि यहां यह सुविधा नहीं है, आप इन्हें एसएमएस अस्पताल में ले जाएं तो कुछ हो सकता है। विचारणीय है कि क्या एक मरणासन्न मरीज के परिजनों से भावुक परिस्थिति में ऐसी भाग-दौड़ की अपेक्षा की जानी चाहिए? 'ब्रेन-डेथ सर्टिफिकेशन' (बीडीसी) अंगदान की प्रक्रिया का एक मूलभूत चरण है। इसके बिना नैतिक तथा कानूनी तौर पर अंग रिट्रीव (निकाले) नहीं किए जा सकते हैं। उक्त सर्वे के 10 प्रतिभागियों में से 6 को उनकी एमबीबीएस शिक्षा के दौरान 'ब्रेन-डेथ सर्टिफिकेशन' का प्रशिक्षण नहीं मिला था।

अंगदान को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत संकल्प की जरूरत है। सामाजिक संस्थाएं जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लें और सरकार अंग रिट्रीवल तथा प्रत्यारोपण सुविधाओं का विस्तार करने का। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था तथा चिकित्सकीय बिरादरी के स्तर पर भी अंगदान के प्रति जुनून की हद तक कार्य जरूरी है। सभी मेडिकल छात्रों को एमबीबीएस के दौरान ही बीडीसी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। संपूर्ण मेडिकल फ्रेटरनिटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रेनडेथ का एक भी मामला बिना सर्टिफिकेशन के नहीं रहे तथा प्रत्येक ऐसे मामले में मृतक के परिजनों के साथ अंगदान की समझाइश के ईमानदार प्रयास हों।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

जहां पर्वतों का संगम प्रकृति की विराटता रचता

दुनिया की छत पामीर पठार

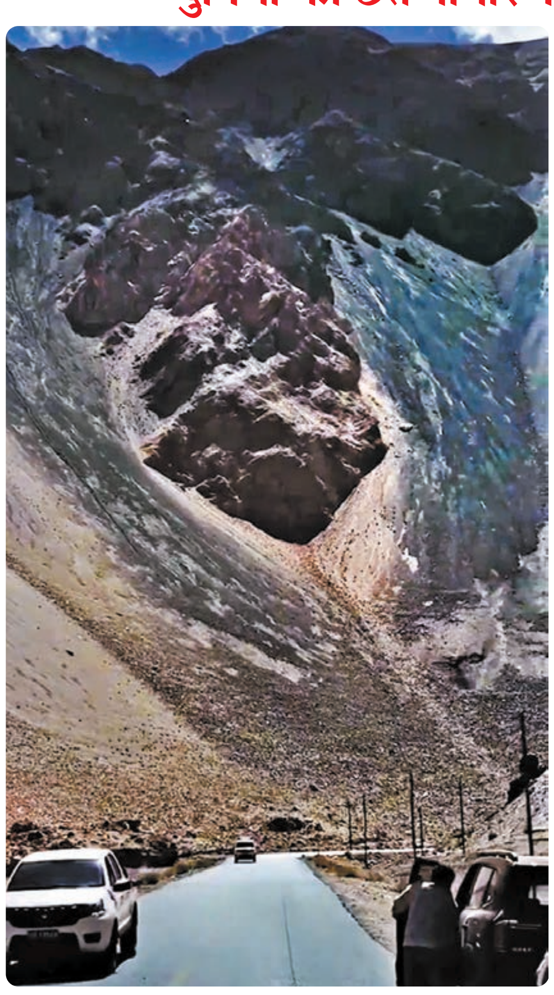

दुनिया की छत कहलाने वाला पामीर पठार प्रकृति की विराटता और भूगर्भीय इतिहास का जीवंत प्रमाण है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह दृश्य हमें उस दुर्गम और रहस्यमयी भूभाग के बारे में बताता है, जो मध्य और दक्षिण एशिया के हृदय में फैला हुआ है। ताजिकिस्तान में स्थित इस उच्च-पठारी क्षेत्र के हिस्से चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैले हैं। यहां हिमालय, काराकोरम, कुनलुन और तिएन शान जैसी पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं, जिस कारण यूनेस्को इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय संगम क्षेत्र मानता है। बर्फ से ढकी ऊंची-ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और दूर तक फैले खुले पठार इस भू-दृश्य को असाधारण बनाते हैं। यहां की कठोर जलवायु और अत्यधिक ऊंचाई इसे पृथ्वी के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में शामिल करती है, फिर भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है। यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी यहीं पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की टक्कर हुई थी।

दृष्टिकोण मैकाले की शिक्षा पद्धति ने समाज को तोड़ा

यह समय भारतीय ज्ञान स्रोतों को पुनर्जीवित करने का है

कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने एक भाषण में मैकाले की शिक्षा पद्धति से बाहर निकलने की आवश्यकता पर बल दिया और वर्ष 2035, जिस वर्ष अंग्रेजों की 1835 की शिक्षा नीति के 200 वर्ष पूर्ण होंगे तक इसके प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भारतीय समाज में आधुनिकता लाना नहीं था, बल्कि ऐसे भारतीय तैयार करना था जो शरीर से भारतीय हों, लेकिन विचारों और दृष्टिकोण में अंग्रेज। इस नीति ने हमारी प्राकृतिक सोच, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और भाषाई विविधता को कमजोर किया।

अश्विनी शर्मा
स्कॉलर, येल विश्वविद्यालय अमरीका
@patrika.com

अनेक भाषाएं विलुप्त हो गईं, केवल शब्द नहीं मरे- बल्कि वह संपूर्ण जीवन-दृष्टि चली गई, जो पीढ़ियों तक व्यवहार, अनुभव और परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित होती थी। पुस्तकों से अधिक जो ज्ञान अनुभव आधारित होता है, वह भी नष्ट हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मैकाले की शिक्षा पद्धति की देन है। भारत में सरकार ने हाल के वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक कदम अवश्य उठाया है।

इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा में शिक्षा और स्वदेशी दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है, जो सराहनीय है। परंतु केवल नीतियां बनाने से परिवर्तन नहीं आता- उसे लागू करने वाले विद्वान, शिक्षक और संस्थान भी सक्षम होने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि कई राज्यों में भारतीयता और परंपरा के नाम पर पदों का बंटवारा ऐसे हाथों में दे दिया जाता है, जिन्हें स्वयं विषय का ज्ञान नहीं होता। जब अयोग्य लोग नीति लागू करेंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा- ऊपर से परिवर्तन, भीतर से शून्यता।

यदि हम वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो योग्य विद्वानों की पहचान और चयन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्थानीय भाषाओं में ज्ञान उत्पादन और शोध को प्रोत्साहन देना होगा। समाज, समुदाय व प्रकृति आधारित शिक्षा को कक्षा तक पहुंचाना होगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीय समाज को भीतर से तोड़ा। समाज की आत्मा को कमजोर किया। अब समय है, हम अपनी टूटी हुई परंपराओं को फिर से जोड़ें। जब तक हम भारतीय ज्ञान के स्रोतों, भाषाओं और परंपराओं को पुनर्जीवित नहीं करेंगे तब तक किसी भी शिक्षा क्रांति की सफलता अधूरी रहेगी। भारतीय शिक्षा को भारतीय मन, भारतीय भाषा और भारतीय अनुभव से ही शक्ति मिलेगी।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग हो

स्लिप लेन ऐसी हो कि वाहन की गति नियंत्रित रहे और मोड़ पर्याप्त चौड़ा हो। पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग हो जिससे रात में दृश्यता बनी रहे। स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप्स लगाए जाएं। स्लिप लेन के पास अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को रोका जाए। - **मुरारी**, सूरत

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'स्लिप लेन को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/e1nuT

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

कृषि व आजीविका खेत और शामलात जमीनों को बचाने से ही पारिस्थितिकी तंत्र को संकट से बचाया जा सकता है

ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के सही रास्ते तलाशने की जरूरत

डॉ. भुवनेश जैन
पूर्व निदेशक
मेरा युवा भारत
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
@patrika.com

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से थार की गोदी में पल रहे गोडावण के साथ कुछ क्षेत्र में पारिस्थितिकी संरक्षण की उम्मीद जगी है, थार रेगिस्तान का क्षेत्र हाइटेंशन विद्युत लाइन के जालों, पवन चक्की एवं सोलर पार्क में तब्दील होकर अपनी पहचान खोता जा रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए चुनौती बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण संरक्षण के प्राथमिकता क्षेत्र में हाइटेंशन बिजली लाइन और सोलर पावर पार्क, पवन चक्की की स्थापना पर रोक लगाई है।

राजस्थान के जैसलमेर की 14013 वर्ग किलोमीटर और गुजरात के कच्छ में नलिया सहित 740 वर्ग किलोमीटर में नई विद्युत लाइन बिछाने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। बिछाई हुई हाइटेंशन लाइन को अगले दो वर्षों में भूमिगत करने का आदेश भी दिया है। हाइटेंशन लाइन से गोडावण की अकाल मृत्यु की खबरें आती रही है और सोलर पार्क, पवन चक्की के कारण खेजड़ी सहित थार की बहुमूल्य वनस्पति पर आए संकट के कारण न केवल गोडावण, बल्कि अन्य पक्षियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। थार क्षेत्र में बेलगाम हाइटेंशन लाइन और सोलर परियोजनाएं ओरण गोचर के साथ-साथ निजी खेतों और सामुदायिक, शामलात जमीन को बर्बाद कर पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ दिया है।

सोलर पार्क, सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइटेंशन विद्युत लाइनों की जाल में गोडावण ही नहीं, थार क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में पड़ी हुई है। ऊर्जा के तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनहीन तरीके से खेजड़ियों, रोहिड़ा, केर, कुमट, फोग का खात्मा किया गया है, जिसके चलते गोडावण के साथ कई पक्षियों का जीवन संकट में आ गया है। ये पक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। थार मरुस्थल के मुख्यतः घास पैदावार का क्षेत्र होने के कारण यह पशुपालन का क्षेत्र रहा है। यहां के अधिकांश वन्यजीव एवं घरेलू पशु घास और चारे पर निर्भर हैं। ऐसे में थार मरुस्थल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप यहां की पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ना है।

कृषि विशेषज्ञ शिवगिरी का कहना है कि थार क्षेत्र का किसान होने के साथ पशुपालक भी है, लेकिन सोलर पार्क के लिए कितनी निजी, शामलात जमीन वन्यजीव पशुओं और इंसान के लिए छोड़नी चाहिए। उसको कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। शहरों में भी एक मकान बनाने के लिए सेट बैक छोड़ा जाता है तो खेतों का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए करने के लिए खेत पर निर्भर रहने वालों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। विद्युत लाइनों के संबंध में यदि खातेदार अपनी जमीन का रूपांतरण आवासीय या औद्योगिक किस्म में करवा देता है तो उसकी जमीन हाइटेंशन लाइन से मुक्त हो जाती है। उचित ज्ञान और सूचना के अभाव में खातेदार ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका खेत बर्बाद हो जाता हैं। थार मरुस्थल में सोलर कंपनियों के लिए सरकार ने ऐसा ही किया है।

गजट नोटिफिकेशन जारी करके केवल गांव का नाम लिख दिया जाता है उसमें कहीं भी खसरा नंबर नहीं होता है जो बता सके कि किसके खेत से विद्युत लाइन निकलेगी। सरकारी लवाजमा बिना अनुमति और एग्रीमेंट के खेत में घुस जाता हैं। हाइटेंशन लाइन, विद्युत पोल आदि खड़े कर देता है। सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि मानव समाज की भावी जरूरतों को देखते हुए हाइटेंशन लाइन बिछाने से पहले खेत और आजीविका से जुड़े शामलात जमीन को कैसे बचाए, विचार करे और विकल्पों पर कार्य करे।

देश की सबसे बड़ी नहरों में इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान की लंबाई 650 किलोमीटर है। अपर गंगा कैनाल की लंबाई 1412 किलोमीटर है। इस तरह नदी, नहरें, राज्य एवं राष्ट्रीय मार्ग, देश की सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों का उपयोग पावर जनरेशन के लिए प्राथमिकता से और बड़े पैमाने पर किए जाने की जरूरत है। ग्रामीण, राज्य, राष्ट्रीय मार्गों के किनारे हाइटेंशन लाइन बिछाने का प्लान पहले बने, ताकि स्वच्छ ऊर्जा भी हो, जल संरक्षण और भूमि की बचत भी हो। ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के सही रास्ते तलाश करने की जरूरत है। जहां-जहां भी हाइटेंशन लाइनें बिछ गई हैं, उन्हें भूमिगत किया जाए। जमीन नहीं बची तो जीने की जमीन खिसक जाएगी।

नेतृत्व का मतलब है कठिन फैसले लेना, भले ही वे अलोकप्रिय हों। नेतृत्व पद नहीं, जिम्मेदारी है। सफलता का असली पैमाना यह है कि आप दूसरों के लिए कितने अवसर बनाते हैं।
जेन फ्रेजर सीईओ, सिटी ग्रुप

पत्रिका फाइनेंस
@बिजनेस & वेल्थ

मार्केटकैप मीटर...
ग्लोबल एमकैप में घटा भारतीय कंपनियों का रुतबा

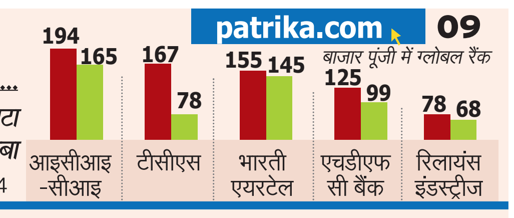

बाजार

सेबी ने ऑर्डर-टू-ट्रेड नियम में छूट दी

मुंबई@ पत्रिका. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इक्विटी ऑप्शन सौदों के लिए छूट सीमा का विस्तार किया है। उसने कुछ मार्केट मेकिंग गतिविधियों को पेनाल्टी गणना से बाहर करते हुए एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर-टू-ट्रेड अनुपात ढांचे को आसान बनाया है। संशोधित मानदंडों के तहत इक्विटी ऑप्शन में एल्गोरिदम ऑर्डर अगर अंतिम कारोबार मूल्य प्रीमियम के 40 प्रतिशत कम या ज्यादा या 20 रुपए के भीतर रखे गए हैं, ऊंचे ऑर्डर-टू-ट्रेड अनुपात के लिए लगाए गए दंड से छूट दी जाएगी। पहले छूट की सीमा काफी कम थी, जिससे बाजार में हिस्सा लेने वालों को बार-बार जुर्माना लगने की चिंता होती थी।

सर्राफा

चांदी 22,000 रुपए सस्ती, सोना भी गिरा

जयपुर@ पत्रिका. लगातार तेजी पर चांदी गुरुवार को सर्राफा बाजार में चांदी 22,000 रुपए कम होकर 2,65,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 5,000 रुपए फिसलकर 1,58,500 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना 4800 रुपए टूटकर 1,48,200 रुपए प्रति दस ग्राम पर आय गया। कॉमेक्स पर सोना 100 डॉलर प्रति औंस नीचे ट्रेड कर रहा था।

'डेटा फैक्ट्री' बनने की जंग अब प्रोसेसिंग हब बनने की तैयारी में भारत

भारत में बना 95% डेटा विदेशों में हो रहा प्रोसेस, टैक्स छूट से बदलेगी तस्वीर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. बजट में भारत को दुनिया का 'डेटा फैक्ट्री' बनाने का संकल्प उठाया गया है। दुनिया के कुल डेटा का करीब 20 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है, लेकिन वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत 3 प्रतिशत के साथ काफी पीछे है। भारत में उत्पादित 90 से 95 प्रतिशत डेटा विदेशों में स्टोर या प्रोसेस किया जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा बजट 2026 में डेटा सेंटर नीति को बढ़ावा देना और टैक्स प्रोत्साहन देना इस क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती ग्रीन पावर की उपलब्धता, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और तेज मंजूरी प्रक्रिया की है। डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा-खपत वाले होते हैं और इनके संचालन के लिए सस्ती, निरंतर और स्वच्छ बिजली बेहद जरूरी है।गौरतलब है कि मुंबई में भारत के कुल डेटा सेंटरों का 50% से अधिक हिस्सा है, जबकि अहमदाबाद, पुणे और विशाखापट्टनम (विज़ाग) उभरते हुए नए डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 150 डेटा सेंटर हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियां जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड आदि इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।

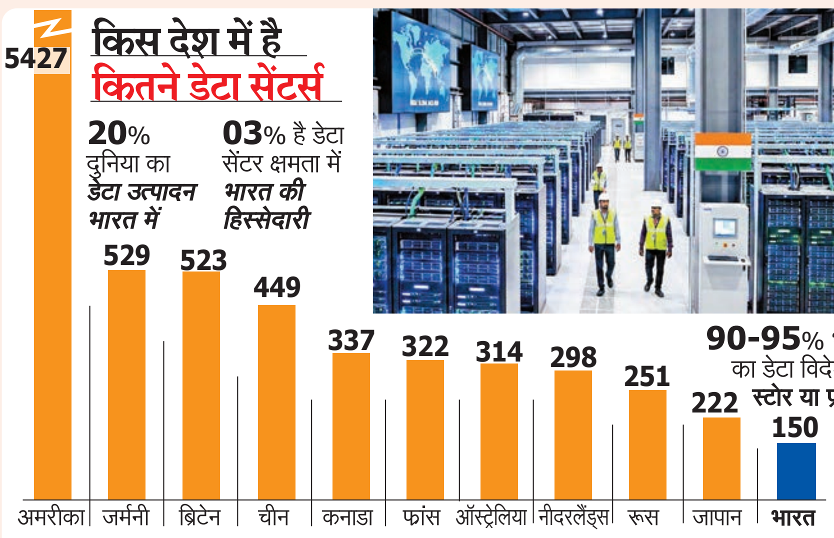

क्लाउड सेवाओं का वैश्विक केंद्र

उद्योग जगत के अनुसार, भारत के पास मजबूत डिजिटल प्रतिभा, विशाल घरेलू बाजार और तेजी से बढ़ती इंटरनेट खपत जैसी बड़ी ताकतें हैं। अगर नीति स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियां और स्थानीय क्षमता निर्माण पर फोकस किया जाए, तो भारत केवल डेटा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सेवाओं का वैश्विक केंद्र बन सकता है।

बिजली की लागत बनी चुनौती

एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख देशों से तुलना करें तो भारत में निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन बिजली की लागत और डेटा ट्रांसफर से जुड़ा खर्च अभी भी अधिक है। जापान, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में डेटा सेंटर इकोसिस्टम पहले से मजबूत है, जहां नीति, इंफ्रा और तकनीकी तैयारियां एक साथ विकसित हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी इसी तरह समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

टैक्स इंसेंटिव्स एक मजबूत शुरुआत: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ग्रीन एनर्जी, डेटा लोकलाइजेशन, क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो और मानकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों पर स्पष्ट नीति बनाता है, तो देश अगले दशक में वैश्विक डेटा सेंटर वैल्यू चेन में अहम भूमिका निभा सकता है। टैक्स इंसेंटिव्स एक मजबूत शुरुआत हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों को समान गति से आगे बढ़ाना होगा।

चीन ने डुबाया पैसा हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की बड़ी छलांग

भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट का बजा डंका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारतीय रियल एस्टेट ने ग्लोबल मार्केट में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। एक तरफ दुनिया के 55 देशों के बास्केट में औसत सालाना कीमतों में केवल 2.4 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि भारत में घरों की कीमत 9.6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है। खास बात है कि अमरीका (1.3%) के मुकाबले भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें 7 गुना अधिक है।

प्रीमियम घरों की मांग मजबूत: विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का आवासीय रियल एस्टेट बाजार लगातार मजबूत गति दिखा रहा है। यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। खासकर लग्जरी और प्रीमियम घरों की मांग बेहद मजबूत है।

स्पेन और भारत सबसे आगे, चीन पिछड़ा

देश	तीसरी तिमाही–2025
स्पेन	12.10%
भारत	9.60%
ऑस्ट्रेलिया	8.3%
जर्मनी	8.1%
अमरीका	1.3%
चीन	–5.5%

विकास दर 8%

महंगाई को हटा भी दें तो वास्तविक विकास दर के में मामले भी भारत काफी आगे है। भारत की विकास दर 8 फीसदी है। ब्रिटेन में प्रॉपर्टी की कीमतों में 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा और चीन के रियल एस्टेट मार्केट अभी भी संकट में है।

केंद्रीय बैंकों में ब्याज दरों में कटौती: नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में ग्लोबल स्तर पर घर की कीमतों में सुधार का अहम कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में भी कटौती की गई है। दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों ने इस तिमाही में 27 बार ब्याज दरों में कटौती की। साथ ही एक बार भी ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया गया है। इससेकर्ज सस्ता हुआ है, मांग में भी सुधार आया है।

ऊर्जा क्रांति की तैयारी 2026-27 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा झोंकेगी सरकार, स्टोरेज बनेगा नया गेमचेंजर

सोलर-विंड से परमाणु तक, निवेश का पावर-पैक प्लान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. देश के पावर सेक्टर में केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश करने जा रही है। बजट 2026-27 के अनुसार पावर मंत्रालय के अधीन नौ सार्वजनिक उपक्रमों ने मिलकर 1,01,763 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जबकि 2026 में यह राशि 85,829 करोड़ थी। इस निवेश में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इन तीनों कंपनियों का संयुक्त बजट अनुमान वित्तवर्ष 2027 के लिए 82,323 करोड़ रखा गया है, जो 2026 के 69,478 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। बजट में वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के लिए भी प्रावधान बढ़ाया गया है।

डिस्कॉम्स का बढ़ता घाटा...

वित्त वर्ष 2025 के अंत तक डिस्कॉम्स का ***घाटा 6.47 लाख करोड़*** और कुल उधारी 7.26 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी।

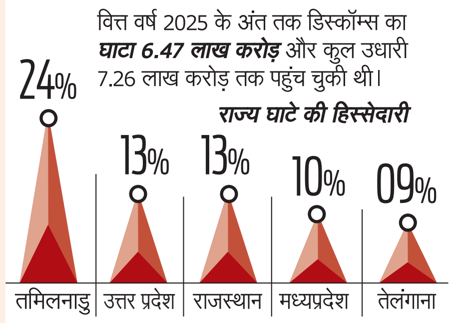

रिटर्न में निजी पावर कंपनियां आगे

कंपनी	मौजूदा मूल्य	1 साल का रिटर्न (%)
अडानी रिन्यूए.	152.42	29.05
पीटीसी इंडिया	180.22	23.48
अडानी एनर्जी	986.55	22.75
इंडीग्रिड	163.27	15.31
एनटीपीसी	365.45	11.49
पीजीइन्विट	93.29	12.84
सीईएससी	153.12	5.18
टाटा पावर	371.20	4.42

भारत बन रहा बड़ा ऊर्जा बाजार: आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है अगले 7 वर्षों में बिजली उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा भंडारण और वितरण में निवेश की काफी क्षमता है। भारत ने साल 2024 में 250 गीगावाट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब भारत की कुल बिजली प्रोडक्शन क्षमता अब 500 गीगावॉट से ज्यादा हो चुकी है।

क्लीन एनर्जी स्टोरेज नया मौका

बैटरी और पंप्प स्टोरेज जैसी तकनीकें भी आने वाले समय में अहम होंगी। सोलर और विंड एनर्जी के कारण बिजली प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव होता है, इसे संभालने के लिए स्टोरेज जरूरी है। इस सेक्टर में भी बड़ा निवेश आने की उम्मीद है और बड़ी कंपनियां पहले से तैयारी कर रही हैं। सरकार क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। देश पहले ही अपने क्लाइमेंट गोल्स् से आगे निकल चुका है।

प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा खर्च: नए निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा बिजली प्रोडक्शन में जाएगा, इसमें सोलर और विंड एनर्जी के साथ साथ थर्मल और परमाणु एनर्जी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।

साइबर फ्रॉड

39.43 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद

नई दिल्ली@ पत्रिका. साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट और 1.31 लाख एसएमएस टेम्पलेट्स को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) की स्थापना की है, जिससे साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके।

डीआइपी ने साझा की जानकारी: उन्होंने कहा कि संचार साथी का उद्देश्य ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है, जहां धोखाधड़ी की कोशिश तो की गई हो लेकिन वास्तविक नुकसान नहीं हुआ हो। वहीं, जिन मामलों में वास्तविक वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, नागरिकों से प्राप्त 7.7 लाख इनपुट्स के आधार पर 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। मंत्री के अनुसार, डीआइपी के जरिए साझा की गई जानकारी के आधार पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स अपने-अपने क्षेत्र में जुड़े खातों और प्रोफाइल्स पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

गोल्ड बॉन्ड 5 साल बाद छूट खत्म

एसजीबी में निवेश महंगा पड़ा, सरकार ने बदला टैक्स गेम

जयपुर @ पत्रिका. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) में निवेश करने वालों के लिए टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। एक अप्रेल से लागू नए **पत्रिका एक्सप्लेन** प्रावधानों के तहत अब 5 साल का लॉक-इन पूरा होने के बाद भी प्रीमैच्योर रिडेम्पशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, कुछ तय एसजीबी सीरीज के निवेशकों को फरवरी-मार्च में टैक्स-फ्री रिडेम्पशन का अंतिम मौका दिया गया है। ऐसे में निवेशकों के लिए नियमों को समझना और समय पर फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया है।

क्या बदला है?

- 1 अप्रेल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) से जुड़े ***टैक्स नियमों में अहम बदलाव लागू हो गए हैं।***
- अब 5 साल का लॉक-इन पूरा होने के बाद भी ***प्रीमैच्योर रिडेम्पशन पर टैक्स-फ्री छूट नहीं मिलेगी।***
- ***पूरी तरह टैक्स-फ्री:*** इश्यू के समय खरीदे गए एसजीबी, यदि मैच्योरिटी तक होल्ड किए जाएं
- ***कैपिटल गेन टैक्स लगेगा:*** मैच्योरिटी तक रखने पर

कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर

12 महीने से ज्यादा होल्डिंग: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स: **12.5%**
12 महीने से कम होल्डिंग: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन: **स्लैब रेट के अनुसार**

टैक्स-फ्री लाभ पाने का आखिरी मौका

- फरवरी-मार्च में कुछ एसजीबी सीरीज के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का अंतिम अवसर
- इन रिडेम्पशन पर मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स-फ्री रहेगा

रिडेम्पशन के लिए तय एसजीबी सीरीज

सीरीज	रिडेम्पशन	आवेदन
2020-21 सीरीज VI	7 मार्च	5-25 फरवरी
2020-21 सीरीज XII	9 मार्च	6-27 फरवरी
2019-20 सीरीज X	11 मार्च	7 फरवरी-2 मार्च
2019-20 सीरीज IV	17 मार्च	13 फरवरी-7 मार्च

निवेशकों के लिए जरूरी सूचना: प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए मैच्योरिटी से कम से कम एक माह पहले बैंक या डिपॉजिटरी को सूचना देना अनिवार्य

क्यों अहम है यह बदलाव?

1. सरकार का उद्देश्य एसजीबी को ***दीर्घकालिक निवेश के रूप में प्रोत्साहित करना***
2. बार-बार प्रीमैच्योर ***एग्जिट को हतोत्साहित करना***
3. टैक्स नियमों में स्पष्टता व ***समानता लाना***

पेज वन का शेष...

कांग्रेस पर...

पीएम के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया तो मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग थक गए, वो चले गए हैं लेकिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक देश की ऐसी हालत क्यों बनाए रखी थी? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को 'राज्यों की सरकारें गिराने वाली पार्टी' करार देते हुए याद दिलाया कि कैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर दर्जनों बार क्षेत्रीय आकांक्षाओं का गला घोंटा। पीएम ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग थमेगी नहीं और 2047 के 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर देश मजबूती से बढ़ता रहेगा। पीएम ने कहा, हमने एनपीए के पहाड़ खत्म किए। आज एनपीए 1 पर्सेंट से भी नीचे है। इससे पहले नारेबाजी करने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी उम्र को देखते हुए 'बैठकर' नारे लगाने चाहिए।

चुनौतियां कितनी भी हों, 140 करोड़ समाधान हैं: पीएम ने इंदिरा गांधी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू और इंदिरा ने उस समय की जनसंख्या 30 करोड़ और 57 करोड़ को उनके सामने समस्या बताया था और हमारा मानना है कि चुनौतियां कितनी भी हों हमारे पास 140 करोड़ समाधान है। मोदी ने कहा, पिछली सरकारें 'रिमोट कंट्रोल' से चलती थीं, लेकिन उनकी सरकार के पास भी एक रिमोट है - 'देश के 140 करोड़ लोग। पीएम के भाषण के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया।

सदानंद का जिक्र : मोदी ने सदानंद मास्टर का जिक्र करके कहा कि राजनीतिक द्वेष ऐसा कि भरी जवानी में इनके पैर काट दिए गए। कटे पैर से वे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में जरा भी कटुता नहीं है। उन्होंने जब अपने आर्टिफिशियल पैरों को टेबल पर रखा तो वो दृश्य पीड़ा दायक था। ऐसे लोगों से ही हम राजनीति में जीने-मरने की प्रेरणा पाते हैं।

घुसपैठियों की वकालत करने वालों को देश कैसे माफ करेगा : पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है। टीएमसी के साथी अपने गिरेबान में झांकें। निर्मम सरकार के जितने मापदंड हैं, उन सबमें वो नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। देश का नौजवान ऐसे लोगों को कैसे माफ करेगा, जो घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं।

हो सकती...

इसको टालने के लिए मैंने पीएम से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। पीएम का आभार कि उन्होंने मेरा आग्रह माना। बुधवार को अध्यक्ष कार्यालय में जो हुआ वह काले धब्बे की तरह है।

पोस्टर, पम्फलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा : बिरला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर विवाद और हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को तीन बार स्थगित करना पड़ा और अंततः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और पीएम के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। स्पीकर बिरला ने साफ कह दिया कि इस तरह के हालात में सदन आज भी नहीं चलेगा और कल भी नहीं चल सकता। सदन के नेता सदन में न बोलें, यह कतई उचित नहीं है। बिरला ने विपक्ष को दो टूक कहा कि पोस्टर, पम्फलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन का सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण रखें।

कांग्रेस ने भाजपा को 2004 की दिलाई याद: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 10 जून 2004 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाजपा ने बोलने से रोका था। उन्होंने मनमोहन सिंह का 21 साल पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से कहा कि पीएम मोदी पर हाथ उठाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। यह कहना कि ऐसा कोई प्लान था, पूरी तरह गलत है।

दिल्ली में...

शाह ने कहा कि तीन साल में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक भारत टैक्सी अग्रणी होगी।

भारत टैक्सी सहकारी मॉडल क्या?: 6 जून 2025 को पंजीकृत सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव में ड्राइवर शेयरधारक बनते हैं, अनुबंधित कर्मचारी नहीं। प्रत्येक ड्राइवर पांच शेयर रखता है और पारंपरिक एग्रीगेटर्स की 20-30 प्रतिशत कमीशन के बजाय केवल 30 रुपए प्रतिदिन देता है। शुरुआत में राइड की 100 प्रतिशत राशि ड्राइवरों को मिलती है। ऐप एंड्रॉयड और आइओएस पर उपलब्ध है।

कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल: मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप इंस्टाल करना होगा। इसके बाद ओला-उबर की तरह आप राइड बुक कर सकेंगे।

टैक्सी चालकों को यह लाभ
- पूरा लाभ, कोई कमीशन नहीं
- चालकों का 5 लाख दुर्घटना और 5 लाख पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा
- चालकों को सरकारी कर्ज, गिग वर्कर्स की अन्य सुविधाएं
- सिर्फ500 रुपए के शेयर से कंपनी के मालिक, दिल्ली में 2.5 लाख टैक्सी चालक जुड़े।

मुंबई-पुणे ...

बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसी का इंटरव्यू छूटा, कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाया तो कई जगह एंबुलेंस भी फंसी रही। जाम में 8 घंटे फंसने के बाद उद्योगपति डॉ. सुधीर मेहता को पुणे पहुंचने के लिए हेलिकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा।

उन्होंने सोशल मीडिया पर जाम के कुछ हवाई फोटो डाले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने घटना को लेकर सरकार की आलोचना की है।

उन्होंने कहा, भविष्य में ऐसे जाम रोकने के लिए सरकार को ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। साथ ही इस अवधि में जिन यात्रियों से टोल वसूला गया, वह वापस किया जाना चाहिए। 95 किमी लंबा यह एक्सप्रेस-वे मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है।

अब खाड़ी...

भारत ने जीसीसी के सदस्य देशों यूएई और ओमान के साथ अलग से व्यापार समझौते किए हैं और कतर से एफटीए पर बातचीत चल रही है लेकिन पूरे समूह से एफटीए होने से देश और लोगों को ज्यादा लाभ होगा।

असीम संभावनाएं...उच्चतम स्तर पर बातचीत: गोर: इंडो-यूएस ट्रेड डील में अहम भूमिका निभाने वाले भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को कहा कि वाशिंगटन असीम संभावनाओं का देखते हुए नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है और उच्चतम स्तर पर बातचीत अभी भी जारी है। गोर ने एक्स पोस्ट में अमरीकी दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर की वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ मुलाकातों की तस्वीरें भी साझा कीं।

जीसीसी से भारत का व्यापार (2025 में, अरब डॉलर में)

देश	निर्यात	आयात
बहरीन	0.79	0.84
कुवैत	1.93	8.28
ओमान	4.06	6.54
कतर	1.68	12.46
सऊदी अरब	11.75	30.12
यूएई	36.63	63.40

कुल निर्यात 56.87
(**मुख्यत:** मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, धातुएं, इमिटेशन ज्वैलरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी, लोहा-इस्पात, केमिकल)

कुल आयात 121.66
(**मुख्यत:** कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस)

गोविंदा पर हुई हमले की कोशिश

मुंबई@पत्रिका. बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने दावा किया है कि हाल में गोविंदा के घर पर कुछ अनजान लोगों ने उनपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गए क्योंकि उनके पास बंदूक थी। हालांकि, उन्होंने घटना के दिन का खुलासा नहीं करते हुए कहा है कि मामले की एफआइआर दर्ज करवा दी गई है।

न्यूज विंडो

क्रैशर-कैंटर भिड़ंत में तीन की मौत

बेंगलूरु@पत्रिका. कर्नाटक के धारवाड़ जिले के गडग इलाके में एक स्टेट हाईवे पर एक क्रैशर-कैंटर की भिडंत में तीन महिलाओं की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृत तीनों महिलाएं किसान थीं। हादसा सुबह करीब 6 बजे रोना तालुक में स्टेट हाईवे 30 पर जिगलुरु क्रॉस के पास हुआ।

मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर

बीजापुर@ पत्रिका. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के घने जंगलों में गुरुवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलोंने एक नक्सली को ढेर कर दिया। मौके से बरामद शव के साथ एक एके-47 राइफल भी मिली है। सुरक्षा बल पूरे इलाके की गहन तलाशी ले रहे हैं। जिले के दक्षिणी इलाके में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया।

तमिलनाडु : 'वेदा निलयम' नीलामी की कगार पर

चेन्नई @ पत्रिका. तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का ऐतिहासिक आवास 'वेदा निलयम' फिर विवादों में है। आयकर विभाग ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि यदि बकाया कर राशि का भुगतान नहीं हुआ तो जब्त संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। विभाग के अनुसार जयललिता पर कुल बकाया लगभग 20 करोड़ रुपए हैं। वारिस दीपा (दीपक) ने अदालत में कहा कि वे भुगतान के लिए तैयार हैं, लेकिन सही राशि स्पष्ट की जाए। उन्होंने 6.75 करोड़ रुपये की छह किश्तों का प्रस्ताव दिया, जिसमें से 1.12 करोड़ पहले जमा हो चुके हैं। अदालत ने वसूली पर रोक लगाई है और विभाग को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई आगामी 18 फरवरी को होगी।

इनोवेशन पर बड़ा दांव कंपनियों को मिलेगा 20 साल का फायदा

डीप टेक स्टार्टअप्स के नियम बदले, टर्नओवर सीमा बढ़कर 300 करोड़

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की परिभाषा में बड़ा बदलाव करते हुए डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग कैटेगरी बना दी है। 4 फरवरी 2026 को जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत ऐसे स्टार्टअप्स को अब 20 साल तक मान्यता मिलेगी और 300 करोड रुपए तक के टर्नओवर की छूट दी जाएगी। इसका मकसद साइंस और इंजीनियरिंग आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देना है। नई व्यवस्था के तहत डीप टेक स्टार्टअप्स को लंबी टैक्स छूट, ज्यादा निवेश की सुविधा और रिसर्च पर खर्च की मान्यता मिलेगी। साथ ही फंड के इस्तेमाल पर सख्ती भी बढ़ाई गई है ताकि पैसा सिर्फ कोर बिजनेस और इनोवेशन में ही लगे।

डीप टेक स्टार्टअप क्या होंगे: नई परिभाषा के अनुसार डीप टेक स्टार्टअप वे कंपनियां होंगी जो नई वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग जानकारी पर आधारित सॉल्यूशन विकसित करती हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर शामिल हो सकते हैं।

मान्यता की अवधि: डीप टेक स्टार्टअप्स को अब इनकॉरपोरेशन की तारीख से 20 साल तक स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। वहीं सामान्य स्टार्टअप्स के लिए पहले की तरह 10 साल की मान्यता और 200 करोड रुपए की सीमा लागू रहेगी।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

स्टार्टअप्स को डीपीआईआइटी पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। सामान्य स्टार्टअप्स की तरह इनोवेशन और स्केलेबिलिटी का विवरण देना होगा। रिसर्च से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। आयकर की धारा 80 आइएसी के तहत टैक्स छूट के लिए इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड से सर्टिफिकेशन जरूरी होगा।

मध्यप्रदेश... निर्माता-अभिनेता पर एफआइआर कराने की मांग

मनोज वाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर फूटा ब्राह्मण समाज का गुस्सा, सड़क पर उतरे

भोपाल @ पत्रिका. अभिनेता मनोज वाजपेयी की ओटीटी फिल्म 'घूसखोर पंडत' का मध्यप्रदेश में विरोध तेज हो गया। गुरुवार को भोपाल में ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। फिल्म के नाम में 'पंडत' शब्द पर उन्होंने आपत्ति की। छोटे-छोटे बटुक हाथों में तख्तियां लेकर सडक् पर उतरे। एमपी नगर में प्रदर्शन कर नाम बदलने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिल्म निर्माता नीरज पांडेय और मनोज वाजपेयी पर एफआइआर दर्ज होनी चाहिए। वे ब्राह्मण समाज की छवि को नकारात्मक बना रहे हैं।

भोपाल में फिल्म के नाम के खिलाफ सड़क पर बटुकों का प्रदर्शन।

संपादकीय

'मेगा'हाल बत्तीशी

देशाची आर्थिक राजधानी-राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन महत्त्वाच्या महानगरांना जोडणारा देशातील पहिला सहापदरी द्रुतगती महामार्ग. अभिमानाने मिरवला जाणारा हा एक्स्प्रेस मेगा हायवे तब्बल ३२ तास ठप्प राहतो आणि एका झटक्यात 'विकसित महाराष्ट्रा'च्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी होते. तासन्तास एकाच जागी अडकलेली वाहने, रडणारी मुले, हतबल महिला, थकलेले असहाय वृद्ध, पाण्याच्या एका घोटासाठी होणारी तगमग, लघुशंकेसाठी झालेली घुसमट, भुकेने व्याकुळ झालेले जीव... ही दृश्ये केवळ महाराष्ट्राने नव्हे, तर देशाने आणि साऱ्या जगाने पाहिली. कारण एकच. ज्वलनशील रसायन घेऊन जाणारा एक टँकर. केवळ एक टँकर उलटतो आणि संपूर्ण महामार्ग स्तब्ध होतो. वेगाने धावणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे आयुष्यच थांबून राहते. ही केवळ अपघातजन्य समस्या नाही; ही महामार्गावरील आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या भीषण अपयशाची साक्ष आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधांवर भर दिला जातो, 'वेगवान महाराष्ट्र', 'विकसित महाराष्ट्र' अशी स्वप्ने दाखवली जातात; पण प्रत्यक्ष संकटसमयी त्या स्वप्नांची पाठराखण करणारी व्यवस्था मात्र तोकडी, गोंधळलेली आणि असहाय ठरते हे या घटनेने ठळकपणे अधोरेखित झाले. महामार्ग म्हणजे फक्त डांबराचा किंवा सिमेंट-काँक्रीटचा पट्टा नसतो; तो माणसांचा, वाहनांचा आणि मालवाहतुकीचा सजीव प्रवाह असतो; पण या प्रवाहात काही बिघडले, काही तुटले, काही पेटले तर काय करायचे, याची तयारी आपल्याकडे आहे का? मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असेच मिळते. अपघात झाला, धोका लक्षात आला आणि वाहतूक बंद यापलीकडे कोणतीही सुसंगत, पूर्वनियोजित आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा दिसली नाही. दररोज टोलमधून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणाऱ्या महामार्गावर अपघात व्यवस्थापन इतके तोकडे असावे, ही बाब धक्कादायक आहे. धोकादायक रसायने वाहून नेणाऱ्या टँकरसाठी स्वतंत्र लेन आहे का? घाट परिसरात तत्काळ प्रतिसाद देणारी सुसज्ज आपत्ती निवारण केंद्रे आहेत का? हजारो लोक अडकले तर त्यांना अन्न-पाणी, प्राथमिक वैद्यकीय मदत आणि विश्वासार्ह माहिती देण्याची जबाबदारी कोणाची? ३२ तास उलटूनही या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत हीच खरी वस्तुस्थिती आहे. हा प्रश्न केवळ एका महामार्गापुरता मर्यादित नाही; तो आपल्या संपूर्ण पायाभूत सुविधा नियोजनावर बोट ठेवतो. आपण रस्ते आखतो, उड्डाणपूल बांधतो, महामार्गांची जाळी पसरवतो; पण भविष्यातील संकटांच्या शक्यतांचा गांभीर्याने विचार करत नाही. 'अपघात क्वचित होतात' या गृहीतकावर नियोजन उभे असते. प्रत्यक्षात वाढती वाहतूक, धोकादायक मालवाहतूक, हवामान बदल आणि मानवी चूक या सगळ्यांमुळे अपघात आता अपवाद राहिलेले नाहीत. तरीही २५ ते ५० वर्षांनंतरची परिस्थिती गृहीत धरून नियोजन का होत नाही? 'समृद्धी', 'शक्तिपीठ'सारखे महामार्ग ज्या वेगाने उभे राहत आहेत, त्या वेगाने त्यावरील आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यायी मार्ग आणि तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा का उभी राहत नाही? जबाबदारी नेमकी कोणाची? - महामार्ग प्राधिकरणाची, राज्य सरकारची, कंत्राटदारांची? की 'सगळे मिळून कुणीच नाही' अशी सोयीस्कर व्यवस्था आपण स्वीकारली आहे? संकटात हजारो नागरिक अडकतात, तेव्हा जबाबदारी सामूहिक असते; पण उत्तरदायित्व मात्र कुणाचेच नसते, हा आपल्या प्रशासनाचा स्थायी आजार आहे. या घटनेतून शिकायचे काय? - प्रत्येक महामार्गावर धोकादायक मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र नियम व मार्ग असायलाच हवेत. ठरावीक अंतरावर सुसज्ज आपत्ती प्रतिसाद केंद्रे, रिअल-टाइम माहिती व्यवस्था, वार्षिक संयुक्त आपत्ती सराव आणि 'आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे हक्क' असा स्पष्ट आराखडा हवा. हे खर्च नाहीत; सुरक्षिततेसाठीची ही किमान गुंतवणूक आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावरील हे संकट इशारा देणारे आहे. विकासाचा वेग वाढतो आहे; पण त्याला दिशा देणारी दूरदृष्टी मागे पडते आहे. रस्ते रुंद करून प्रगती होत नाही. संकटात नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याची तयारी असेल, तेव्हाच विकासाला अर्थ प्राप्त होतो. अन्यथा, हा विकास ३२ तास नव्हे, तर अनेक वर्षे आपल्याला ठप्प करून टाकण्याचा धोका निर्माण करेल.

सुनेत्रा पवार यांना राजकारण जमेल का?

राजकारणात काही जण हाती तलवारी, तर काही संयमाची ढाल घेतात. सुनेत्रा पवार ढालीच्या राजकारणातून पुढे आल्या. कधीकधी ढालच युद्ध जिंकते.

यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

सुनेत्रा पवार यांच्याकडे कालपर्यंत पवार कुटुंबात दुय्यम भूमिकाच आलेली होती, आता त्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. अजितदादांच्या निधनानंतर त्या उपमुख्यमंत्री होत असताना काही जणांनी अशी शंका बोलून दाखविली की, पटेल-तटकरे बोलतील तशा त्या चालतील; पण तसे काहीही होणार नाही. असे ऐकले आहे की, इतर कोणापेक्षाही त्या त्यांचे पुत्र पार्थ यांचे अधिक ऐकतात आणि ते आईच्या खूप लाडाचेही आहेत. तसे असेल तर पार्थ यांच्याकडून अधिक परिपक्व वागणुकीची अपेक्षा आहे. राजकारणात ते यापूर्वी अपयशी ठरले होते. लोकसभा निवडणुकीतील त्यांच्या पराभवामुळे अजित पवार यांचे वा तेव्हाच्या एकत्रित राष्ट्रवादीचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आलेले नव्हते. मात्र, आज अजितदादा नाहीत अशावेळी पार्थ यांनी काही चुका केल्या तर त्याचा फटका त्यांच्या आईला आणि पक्षालादेखील बसेल. आता आपली काय जबाबदारी असेल याचे आत्मचिंतन पार्थ यांनी केले असावे, अशी माफक अपेक्षा आहे.

गुरुची विद्या गुरुलाच

ही राष्ट्रवादी असो की ती; पवार नावाशिवाय चालूच शकत नाही. कारण पवार राष्ट्रवादीचे जन्मदाते आहेत आणि पक्ष त्यांच्याभोवती फिरतो. पवारांशिवाय राष्ट्रवादी म्हणजे आत्म्याशिवाय देह. सुनेत्रा पवार यांना दादा गेल्यानंतर चारच दिवसांत उपमुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने आवश्यकच होता. आणखी चार-आठ दिवस घालवले असते तर उपमुख्यमंत्री कदाचित कोणी वेगळेच दिसले असते आणि पक्षाचेही अपहरण होण्याची शक्यता होती. ते कोण कसे करू शकते याचे अचूक भान पटेल आणि तटकरे या जुन्याजाणत्या शिष्यांना असल्याने त्यांनी सुनेत्रावहिनींचा शपथविधी करवून घेतला. अपहरणाची भीती ही कल्पना नसते; ती राजकारणात कायम सावलीसारखी असते. सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या कुटुंबालाही ही सावली दिसली असावी.

'गुरुची विद्या गुरुलाच' या न्यायाने अजित पवार गटातील नेत्यांनी वेगवान हालचाली केल्या. भाजपनेही त्यांना त्यासाठी पुरेपूर सहकार्य केले, कारण शरद पवार यांना दूर ठेवावे असे भाजपलाही वाटते. सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या मुलांनाही राष्ट्रवादीच्या अपहरणाची भीतीयुक्त शंका असावी आणि म्हणूनच ते तत्काळ शपथविधी करण्यासाठी राजी झाले असावेत. सुनेत्रा पवार याच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील. त्या बारामतीतून विधानसभा लढतील आणि त्यांच्या जागी त्यांचे पुत्र पार्थ हे राज्यसभेवर जातील असे नजीकच्या भविष्यातले चित्र

दिसत आहे. पक्ष आणि सरकारमध्ये शीर्षस्थ नेतृत्व पवारांचेच असावे, अशी अजित पवार गटात सार्वत्रिक भावना आहे, ती न समजण्याइतपत पटेल, तटकरे हे अपरिपक्व नक्कीच नाहीत. म्हणूनच 'आपण अजिबात राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार नाही', हे पटेल यांनी लगेच स्पष्ट करून गोंधळ संपविला.

तिकडच्या पाटील, इकडच्या पवार

सुनेत्रा पवार या माहेरच्या पाटील अन् सासरच्या पवार आहेत; यातच खूप काही आले. त्यांची राजकीय जाण उत्तम आहे. त्यांना सगळेच कळत नसले तरी बरेच काही कळते हे त्यांच्या आजवरच्या मुलाखतींमधून स्पष्टपणे जाणवते. पवारांच्या घरात तशा त्या बाहेरून आलेल्या (आणि त्यासाठी त्यांना हिणवलेही गेले) पण ज्या पवारांनी महाराष्ट्रातील हजारो लोकांना राजकीय आणि सामाजिक शहाणपण दिले त्यांच्या कुटुंबात ३७ वर्षे घालविल्यानंतर असे शहाणपण सुनेत्रा पवार यांच्यात येणे साहजिकच आहे. त्यांच्यातील हे शहाणपण दाखविण्याची संधी त्यांना आजवर मिळाली नव्हती, आता नियतीने ती त्यांना दिली आहे. राजकारणात त्या प्रचंड यशस्वी होतीलच अशी खात्री आज, आत्ता, ताबडतोब देता येत नाही; पण त्या सपशेल अपयशी ठरतील असेही नक्कीच वाटत नाही. शहाणपण हे फक्त भाषणातून येत नाही; ते कुटुंबात, अनुभवाने आणि शांत निरीक्षणातून तयार होते. पतीनिधनानंतर त्यांनी दाखवलेला संयम आणि न डगमगता उभे राहण्याची क्षमता हेच त्यांच्या राजकीय प्रवासाचे पहिले भाषण आहे. राजकारणात काही जण तलवारी घेऊन उतरतात, तर काही जण संयमाची ढाल घेऊन. सुनेत्रा पवार या ढालीच्या राजकारणातून पुढे जाताना दिसतात- आणि कधीकधी ढालच युद्ध जिंकते.

आपले खरे हितचिंतक कोण आहेत, हे जाणून घेत त्या पुढे जातील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. हितचिंतक म्हणजे तुमच्या हिताची नेहमीच चिंता करणारे... तुमचे हित होत असताना चिंताग्रस्त होणारे नव्हेत. अजितदादांचा वारसा त्या कसा चालवतात तेही महत्त्वाचे.

विलीनीकरण होईल तेव्हा होईल; पण अजितदादा हे काकांच्या पक्षातील लोकांनाही सांभाळून घ्यायचे; मनाचा तो मोठेपणा सुनेत्रा पवार दाखवतील का? एकत्रित राष्ट्रवादीला पश्चिम महाराष्ट्रवादी आणि मराठ्यांचा पक्ष म्हटले जात असे. अजितदादा अल्पावधीतच हे दोन्ही शिक्के पुसत होते, ते सुनेत्रा पवार यांना पुढे न्यावे लागणार आहे. त्यांचे नेतृत्व अपयशी ठरले तर त्यांच्या पक्षातील काही जणांना जुन्या घराची आठवण होईल तर काही जण भाजपकडे झुकतील. काहींना आपल्याकडे ओढण्यासाठी एकनाथ शिंदे तयारच असतील. सुनेत्रा पवार यांचा राजकीय प्रवास सोपा नाही. आता कुठे त्यांची परीक्षा सुरू झाली आहे.

yadu.joshi@lokmat.com

अन्वयार्थ

अपत्याचा 'अडसर' आणि सत्तेची विकृत लालसा..

सरपंचपदाच्या स्वप्नात 'अडसर' ठरू नये म्हणून पित्यानेच मुलीला कॅनॉलमध्ये फेकून देणे याहून राजकीय विकृतीचे टोक आणखी कोणते असू शकते?

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर

तिसरे अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येणार नाही, हा कायद्याचा अडसर चुकवण्यासाठी पोटच्या सात वर्षांच्या मुलीची हत्या करण्यात आली. मुखेड परिसरात उघडकीस आलेल्या या घटनेकडे केवळ एक गुन्हेगारी स्वरूपाची घटना अथवा मानसिक विकृती म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. राजकीय वैमनस्यातून होणारे खून, हाणामारी हे नित्याचेच; परंतु सरपंचपदाच्या स्वप्नासाठी एका पित्याने आपल्या मुलीला कॅनॉलमध्ये फेकून देणे याहून राजकीय विकृतीचे टोक कोणते असू शकते? सध्याच्या आत्यंतिक टोकाच्या अशा राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे आणि सत्ताकेंद्री राजकारणाचे हे भयावह वास्तव तर आहेच, शिवाय या निमित्ताने अपत्यांच्या निर्बंधाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे.

महाराष्ट्रात २८ मार्च २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना सरकारी सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था आणि काही सरकारी योजनांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जुळी मुले किंवा दत्तक अपत्यांना या नियमातून वगळण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात हा नियम ग्रामपातळीवरील राजकारणात अनेकदा अन्यायकारक आणि विसंगत ठरत असल्याचे वास्तव आहे. सरकारी सेवेसाठी संविधानातील अनुच्छेद ३०९च्या आधारे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी संबंधित कायद्यांत दुरुस्ती करून ही अट लादण्यात आली. कायद्याचा हेतू लोकसंख्या नियंत्रणाचा असू शकतो; मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी मूल्ये चिरडली जातील, अशी कल्पना कोणत्याही कायदे मंडळाने केलेली नसते. येथे प्रश्न कायद्याचा नाही, तर त्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी केलेल्या अमानुष कृत्याचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा कट एकट्याचा नाही, तर पती-पत्नी, गावातील राजकीय मंडळी अशा साऱ्यांनी मिळून एका चिमुरडीला राजकीय 'अडसर' ठरवले. अपत्य म्हणून नव्हे, कायद्याच्या चौकटीतील एक 'संख्या' म्हणून 'ती'च्याकडे पाहिले गेले!

संविधानाची रचना नागरिकांचे मूलभूत हक्क

जपण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसतो का, याची कसून तपासणी आवश्यक ठरते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लादलेली 'दोन अपत्यांची अट' याच कसोटीवर तपासली जाणे अपरिहार्य आहे. निवडणूक लढविण्याचा हक्क थेट मूलभूत हक्क म्हणून नमूद नाही; तो कायदेशीर हक्क मानला जातो. तरी तो लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे. ग्रामपातळीवरील सहभागावर निर्बंध घालणे म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे आहे.

संविधानातील कलम १४ 'कायद्यापुढे समानता' अधोरेखित करते. मग हा नियम केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच का लागू? आमदार, खासदार किंवा मंत्रिपदासाठी अशी अट का नाही? लोकसंख्या नियंत्रण खरोखरच सार्वजनिक हिताचे उद्दिष्ट असेल, तर ते सर्व लोकप्रतिनिधींना सरसकट लागू व्हायला हवे. निवडक स्तरांवरच अट लादणे म्हणजे असमान वर्गीकरण असून, ते समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे.

संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला आहे. किती अपत्ये असावीत, हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्य, प्रजनन हक्क आणि कौटुंबिक गोपनीयतेशी निगडित आहे. राज्याला लोकसंख्या नियंत्रणाचा अधिकार असला, तरी तो दंडात्मक मार्गाने राबवणे कितपत घटनासंमत आणि नैतिक आहे, हा मूलभूत प्रश्न होय. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांचे सक्षमीकरण अपुरे असलेल्या समाजात हा हस्तक्षेप अधिक कठोर ठरतो.

राज्याला सामाजिक सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे; या तत्त्वावर न्यायालयांनी ही अट वैध ठरवली असली तरी ती वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. संविधानाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षा करणे नाही, तर त्यांना सक्षम करणे आहे. लोकसंख्या नियंत्रण हे दंडाने नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि प्रोत्साहनात्मक धोरणांतूनच साध्य होऊ शकते, हे या विदारक घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

nandu.patil@lokmat.com

जगभर

पाकच्या पंतप्रधानांना कर्ज मागताना वाटते लाज!

पाकिस्तानच्या तिजोरीतला ठणठणपाळ आणि त्यासाठी दारोदारी भीक मागण्याची त्यांची सवय आता कायमचीच झाली आहे. इतकं की त्यावर खुद्द त्या देशाच्या पंतप्रधानांनीच जाहीर कबुली देताना कर्ज मागायची आता फार लाज वाटते, असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ राजधानी इस्लामाबादमध्ये व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करत होते. तेव्हा त्यांनी स्पष्टच सांगितलं, 'देशाची परिस्थिती आता इतकी डबघाईला आलेली आहे की आम्हाला सतत वेगवेगळ्या देशांकडे पैसे मागायला जावं लागतं. तुम्हाला सांगतो, जेव्हा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि मी जगभर पैसे मागायला जातो, तेव्हा आम्हाला लाज वाटते! पैसे मागताना या देशांसमोर आमची मान झुकलेली असते, अतिशय अपमानजनक वाटत असतं आणि बऱ्याचदा त्यांच्या अटी मानणं ही आमची मजबुरी असते. त्यांच्या अटींना आम्हाला 'नाही'सुद्धा म्हणता येत नाही. सातत्यानं कर्ज घेणं हे आमच्या आत्मसन्मानावर मोठं ओझं आहे. सतत दुसऱ्या देशांसमोर हात पसरण्यापेक्षा पाकिस्तानला आता दुसरे मार्ग शोधण्याची नितांत गरज आहे..

मार्च २०२५पर्यंत पाकिस्तानवरचं एकूण सरकारी कर्ज ७६,००० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त झालं होतं. कर्ज फेडण्यासाठी आणि डिफॉल्ट टाळण्यासाठी पाकिस्तानला वारंवार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, चीन आणि इतर देशांकडे हात पसरवावा लागतोय. चीनही या संधीचं सोनं करून घेताना आपलं उखळ पांढरं करून घेतोय.

चीननं पाकिस्तानला दिलासा देण्यासाठी त्यांची कर्ज फेडण्याची मुदत वाढवलीय. २०२४-२५मध्ये ही मदत सुमारे ४ अब्ज डॉलरची असल्याचं मानलं जातंय. याशिवाय चीननं पाकिस्तानमध्ये वीज प्रकल्प, रस्ते, बंदरं आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये ६० अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे.

सौदी अरेबियानं डिसेंबर २०२४मध्ये

पाकिस्तानच्या सेंट्रल बँकेत ३ अब्ज डॉलर जमा केले. त्यानंतर २०२५मध्ये पाकिस्तानला सुमारे १.२ अब्ज डॉलरचं तेल उधार देण्यात आलं, जेणेकरून तात्काळ पेमेंटचा ताण येऊ नये. सौदी अरेबियानं खाणकाम, शेती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ५ ते २५ अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणुकीचे संकेत दिले आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीनं २०२५च्या सुरुवातीला पाकिस्तानचं २ अब्ज डॉलरचं कर्ज फेडण्याची मुदत पुढं ढकलली होती. तसंच वीज, बंदर संचालन आणि सांडपाणी स्वच्छतेच्या प्रकल्पांमध्ये १० ते २५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. कतारनं पाकिस्तानमध्ये ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी करार केलाय. ही गुंतवणूक विमानवाहतूक, शेती आणि पर्यटन क्षेत्रात होणार आहे. कतार हा पाकिस्तानला गॅस पुरवणारा एक मोठा देश आहे. या सगळ्या देशांपुढे झोळी पसरल्यामुळे आणि त्यांच्या मदतीमुळेच सध्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशीबशी चालतेय.

भरीस भर म्हणून पाकिस्तानमध्ये गरिबी वाढून लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. महागाई, पूर आणि आर्थिक अस्थिरता ही त्यामागची कारणं आहेत. बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्क्यांपर्यंत गेलाय. ८० लाखांहून अधिक लोक बेरोजगार आहेत. २०१८ मध्ये जिथे २१.९ टक्के लोक गरिबीरेषेखाली होते, तो आकडा आता ४५ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. अतिगरिबी ४.९ टक्क्यांवरून वाढून १६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. अर्थातच अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला कटोरा घेऊन फिरण्याशिवाय पर्यायही उरलेला नाही !

जनमन

भाषणबाजी नको, हाताला काम हवे

बदलत्या काळात मतदारांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. आजच्या मतदारांना केवळ पोकळ आश्वासने किंवा आवेशपूर्ण भाषणांपेक्षा विकसित 'कृती' आणि 'निकाल' हवे आहेत. सध्याच्या काळात मतदारांसाठी प्रत्यक्ष विकासाचे मुद्दे भाषणबाजीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहेत. केवळ घोषणा नको, तर रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो, अखंडित वीज सेवा, दळणवळणाची साधने, आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे असे पायाभूत सुविधेचे प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले दिसणे महत्त्वाचे आहे. तरुणांना भाषणांमधून प्रेरणा मिळण्याऐवजी हाताला काम आणि रोजगाराच्या ठोस संधी हव्या आहेत. अर्थात रोजगार निर्मिती कमी पडत आहे. करोडो भारतीय रोजगार संधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा तसेच आधुनिक शिक्षण व्यवस्था ही आजची प्राथमिक गरज बनली आहे.

डिजिटल पारदर्शकता अतिआवश्यक आहे. प्रत्येक खात्याची माहिती ऑनलाइन दिसली पाहिजे. अर्थात, माहिती हक्क कायदा तुमच्या दारी.. सरकारी कामांमध्ये होणारी दिरंगाई कमी होऊन सर्व सेवा पारदर्शकपणे आणि वेळेत मिळणे, हीच खरी विकासकामे मानली जात आहेत आणि मानली जाणार आहेत. शाश्वत विकास पाहता पर्यावरणपूरक विकासकामांना मतदार अधिक पसंती देत आहेत. आताचा मतदार अधिक जागरूक झाला आहे. तो केवळ 'काय करणार आहोत' यावर नाही, तर 'काय करून दाखवले' यावर आपले मत ठरवत आहे. म्हणूनच राजकीय पटलावर आता 'भाषणबाजी'ची जागा विकासाने घेतली आहे.

- राजेश बाणावलीकर, हडफडे बार्देश, गोवा

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

आंदोलनांचे अंतरंग

२००९, बीड जिल्ह्यातल्या काठोडा (गेवराई) गावातली गोष्ट...

दरोड्यात एक खून आणि दोन मुलींवर बलात्काराची घटना घडलेली! मुलींचे आजोबा म्हणाले, 'पोलिसांवर विश्वास नाही, आम्ही तक्रारच करणार नाही!'

डॉ. नीलम गोऱ्हे
उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद

अनेकदा महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद कशी व्हावी, यावरून जनमानसात संतापाचे वातावरण निर्माण होते. बीड जिल्ह्यातील काठोडा (गेवराई) गाव.. वर्ष २००९ मध्ये तिथे एका दरोड्यात शेतकऱ्याचा खून झाला आणि त्याच्या दोन मुलींवर बलात्कार झाला. दरोड्यास विरोध केल्याने दरोडेखोरांनी हे दुष्कृत्य केले होते.

सकाळी ८ वाजता मी तातडीने बीडला जाण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासात ब्रेकिंग न्यूज सुरूच होत्या. दुपारी दोन-तीनच्या सुमारास मी पोहोचले. गावात संतापाचे वातावरण होते. लोकांचा खरा राग पोलिसांच्या भूमिकेवर होता. मला वाटले होते की, पोलिसांनी आतापर्यंत गुन्हा दाखल केला असेल; पण परिस्थिती वेगळी होती. ग्रामस्थ आंदोलनाला बसले होते; पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांचा विश्वास नसल्याने 'आम्ही तक्रारच करणार नाही' अशी त्यांची भूमिका होती.

मी उपस्थित असलेल्या वडीलधाऱ्या मंडळींना नमस्कार केला. तेव्हा मुलींचे आजोबा पुढे आले. त्यांच्या डोळ्यात संताप आणि दुःख दोन्ही होते. ते म्हणाले, "आम्ही ठरवलंय, जोपर्यंत योग्य नोंद होत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करायचे नाहीत. सरकारला आम्ही दाद देणार नाही."

त्यावेळी मी सत्तेत नव्हते, माणुसकीच्या नात्याने संवाद सुरू झाला. ते म्हणाले, "आम्ही तुमचीच वाट पाहत होतो. कोठेवाडीच्या घटनेवेळी तुम्ही जशा पोहोचलात, तशा इथे का आला नाहीत? आमचा गेवराई पोलिस स्टेशनवर विश्वास नाही. मुलींवर

बलात्कार झाला आहे; पण पोलिसांनी ती तक्रार लिहून घेतली नाही."

ही बाब ऐकून मला धक्का बसला. पीडित मुलींची प्रकृती पाहता त्यांना तातडीने हॉस्पिटलला नेणे गरजेचे होते. मी आजोबांना म्हटले, "आपण आधी मुलींची प्रकृती तपासून घेऊन आणि योग्य ठिकाणी तक्रार करूया." गावकऱ्यांना पोलिस स्टेशनला न नेता थेट जिल्हा पोलिस अधीक्षक (SP) कार्यालयात नेण्याचे ठरवले.

तत्काळ संभाजीनगरच्या (तत्कालीन औरंगाबाद) महानिरीक्षकांना आणि बीडच्या पोलिस अधीक्षकांना फोन केला. त्यांना स्पष्ट सांगितले की, मी पीडित कुटुंबाला घेऊन येत आहे, त्यांची तक्रार तातडीने आणि सन्मानाने नोंदवली गेली पाहिजे. पोलिस अधीक्षकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मी पीडित मुलींना आणि आजोबांना घेऊन बीडला निघाले. रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही मुलींची तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. नंतर मृत वडिलांवर अंत्यसंस्कार झाले.

त्यानंतर खटला चालला, आरोपपत्र दाखल झाले आणि बीडमधील ॲड. रमेश जंजिरे या निष्णात वकिलांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. या दीड-दोन वर्षांच्या काळात काठोड्याला माझ्या ८/१० तरी भेटी झाल्या. दोन वर्षांच्या कालावधीत आरोपींना १५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्याय मिळाल्यानंतर मी त्या मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. आज त्या दोन्ही मुली सुस्थितीत आहेत. कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीत खूप मोठा फरक पडला नसला, तरी त्या दिवशी आंदोलनाच्या चक्रव्यूहातून न्यायापर्यंत जाण्याचा रस्ता त्या कुटुंबाला सापडला, याचे समाधान मला कायम वाटते.

neeilamgorhe@gmail.com

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

✔ फॅक्टCheck

आंदोलकांनी भाजप कार्यालय पेटवले?

युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनच्या (यूजीसी) नवीन नियमांमुळे सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक कार्यालय जळताना दिसत आहे. संतप्त यूजीसी आंदोलकांनी भाजप कार्यालयाला आग लावली असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, पडताळणीत हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. व्हायरल व्हिडिओ खरा असला तरी तो जुना आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लेहमध्ये आंदोलन सुरू होते. याच आंदोलनादरम्यान संतप्त जमावाने भाजपच्या कार्यालयाची तोडफोड करून आग लावली होती.

सोशलViral

'मोहम्मद दीपक', 'बाबा' नावाने भडका

उत्तराखंडच्या कोटद्वारमध्ये 'बाबा' नावाच्या कपड्याच्या दुकानात बजरंग दलाचे कार्यकर्ते नावात बदल करण्याच्या मागणीसाठी घुसले असता, ४२ वर्षीय दीपक कुमार यांनी त्यांना कडाडून विरोध केला होता. या वेळी संतप्त झालेल्या दीपक यांनी रागाच्या भरात आपले नाव 'मोहम्मद दीपक' असल्याचे सांगितले होते, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. या घटनेवर बोलताना दीपक म्हणाले की, मी हे रागाच्या भरात म्हणालो होतो, पण ही बाब इतकी दूर जाईल याचा अंदाज नव्हता.

सोशलTrending

प्रियकराच्या मदतीने केला 'हनिमून मर्डर'

इंदूरच्या बेफवा सोनम प्रकरणाची आठवण करून देणारा एक थरारक प्रकार राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमधून समोर आला आहे. ३० जानेवारीच्या रात्री आशिष नावाचा तरुण व त्याची पत्नी अंजू बेशुद्धावस्थेत रस्त्याच्या कडेला सापडले होते. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी आशिषला मृत घोषित केले. सुरुवातीला 'हिट अँड रन' वाटणाऱ्या या प्रकरणाचा तपास केला असता, पत्नी अंजूनेच आपल्या पतीचा काटा काढल्याचे सत्य समोर आले. याला अपघाताचे रूप देण्यासाठी अंजूने स्वतःची दागिने लुटल्याचे नाटक केले. अंजू आपल्या लग्नामुळे खुश नव्हती.

आयआयटीयन जोडप्याची ६ हजार रुपयांची पाणीपुरी

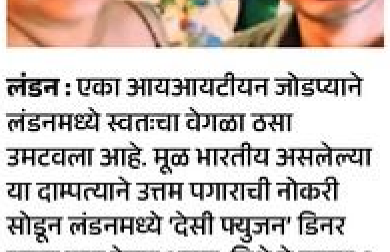

लंडन : एका आयआयटीयन जोडप्याने लंडनमध्ये स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. मूळ भारतीय असलेल्या या दाम्पत्याने उत्तम पगाराची नोकरी सोडून लंडनमध्ये 'देसी फ्युजन' डिनर क्लब सुरू केला असून, तिथे ते चक्क ६ हजार रुपये प्लेटने 'पाणीपुरी' विकत आहेत. नागपूर व उत्तर प्रदेशातील मूळ रहिवासी असलेल्या या जोडप्याने काही काळ भारतात कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केले. २०२४ मध्ये लंडनला स्थायिक झाल्यानंतर, तिथे त्यांनी 'द बुझी क्लब' नावाचा सपर क्लब सुरू केला. महिन्याला केवळ १० ते १२ लोकांसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या या डिनरमध्ये ७ कोर्सचे भारतीय फ्युजन जेवण वाढले जाते, ज्याची किंमत प्रति व्यक्ती ५० पाउंड म्हणजेच ६,००० रुपये आहे. या जेवणाची सुरुवात 'पाणीपुरी'ने होते.

लोकसभेतील गदारोळाचे राज्यसभेत पडसाद, विरोधकांचा सभात्याग

माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकातील उतारे वाचण्यास मल्लिकार्जुन खरगे यांनाही रोखले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू दिले नाही, असा आक्षेप घेत राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गुरुवारी सभात्याग केला. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राहुल गांधी यांचा मुद्दा सभागृहात लावून धरला. तसेच खरगे यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील चीन-भारतबाबतचे उतारे वाचण्यास सुरुवात केली असता त्यांना सभापतींनी रोखले. त्या निर्णयाचाही विरोधकांनी जोरदार निषेध केला.

शून्य प्रहरात खरगे यांनी राहुल गांधी यांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, लोकसभेतील कामकाजावर राज्यसभेत चर्चा होऊ शकत नाही. जर राहुल गांधी यांच्या विषयात काँग्रेस पक्षाला स्वारस्य असेल, तर त्यांच्या नेत्यांनी लोकसभेतील काँग्रेसच्या खासदारांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर मांडण्यात आलेल्या आभारप्रदर्शन प्रस्तावाच्या चर्चेत सहभागी होण्याचा सल्ला द्यावा.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देत असताना, राज्यसभेतून सभात्याग केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली.

संसदेची दोन्ही सभागृहे अतिशय महत्त्वाची : खरगे

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन प्रस्तावावर तीन दिवस झालेल्या चर्चेनंतर आता काँग्रेस पक्ष राहुल गांधी यांचा मुद्दा उपस्थित करतात हे आश्चर्यकारक आहे. राज्यसभेतील पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यास सर्वजण उत्सुक आहेत.

काँग्रेसला हे भाषण ऐकायचे नसल्यास ते त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. त्यांच्यावर कोणीही जबरदस्ती करणार नाही. त्यावर खरगे म्हणाले की, संसद दोन सभागृहांनी बनलेली आहे. ती केवळ एकाच सभागृहावर अवलंबून नाही. दोन्ही सभागृहे लोकशाहीचे स्तंभ आहेत, पण सरकार स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी एका स्तंभाचे खच्चीकरण करत आहे.

पंतप्रधानांच्या भाषणप्रसंगी विरोधकांकडून सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा

१ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबाबत मांडण्यात आलेल्या आभारप्रदर्शन प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी राज्यसभेत भाषण करत असताना विरोधी खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणा दिला व सभात्याग केला.

२ **पंतप्रधान राज्यसभेत आपले भाषण करण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी त्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मात्र तशी परवानगी दिली नाही आणि पंतप्रधानांनी आपले भाषण सुरू केले.**

३ लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भाषण पूर्ण करण्यास परवानगी न दिल्याबद्दल राज्यसभेत विरोधी खासदार घोषणाबाजी करत होते. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला व संसद भवनाच्या मकरद्वारातून घोषणा देत ते बाहेर पडले.

आमदारांना थेट धमकी, सरकारमध्ये जाल तर...

कुकी संघटनांचा इशारा; आज मणिपूर बंदची हाक

इंफाळ : कुकी समुदायाच्या आमदारांनी मणिपूरमधील नव्या सरकारमध्ये सहभागी होऊ नये, असा इशारा या समुदायाच्या संघटनांनी दिला आहे. तसेच चुराचांदपूरमध्ये आज, शुक्रवारी संपूर्ण बंद, तसेच विविध ठिकाणी या संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. दरम्यान, युमनाम खेमचंद सिंह यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी मणिपूर विधानसभेचे नवे अधिवेशन सुरू झाले.

भाजप आमदार यूमनाम खेमचंद सिंह यांनी बुधवारी मणिपूरचे १३ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजप नेते एन. बीरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि राज्यातील मैतेई व कुकी समुदायांतील जातीय हिंसाचारानंतर सुमारे वर्षभराने ही घडामोड घडली. या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. कुकी समुदायातील भाजप आमदार नेमचा किपगेन आणि नागा पीपल्स फ्रंटचे आमदार एल. दिखो यांनी मणिपूरचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, चुराचांदपूर जिल्ह्यातील 'जॉइंट फोरम ऑफ सेव्हन' (जेएफ७) यांनी आज, शुक्रवारी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत कुकी झोबहुल भागांमध्ये संपूर्ण बंद पाळण्याचे आवाहन केले आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे याला प्राधान्य : राज्यपाल

१ मणिपूरचे राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांनी गुरुवारी सांगितले की, मणिपूरमध्ये कायदा, सुव्यवस्था राखणे या गोष्टीला नव्या सरकारचे प्राधान्य असणार आहे. राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी बेकायदेशीर शस्त्रे जप्त करण्याची कारवाई आवश्यक आहे.

२ **मे २०२३ मध्ये जातीय हिंसाचार भडकल्यापासून आतापर्यंत राज्यात ७,३१३ शस्त्रे, ८३,५१२ जिवंत काडतुसे आणि ५,११५ स्फोटके जप्त करण्यात आली असल्याचेही भल्ला यांनी विधानसभेत केलेल्या अभिभाषणात सांगितले.**

संघटनेवर जबाबदारी नाही : कुकी झो कौन्सिलने सांगितले की, कुकी समुदायाच्या आमदाराने सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत निर्णय घेतल्यास त्या निर्णयामुळे येणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी संघटनेवर राहणार नाही.

भारतीय टोळीकडून अमेरिकेत बनावट औषध विक्री; ४ अटकेत

न्यूयॉर्क : भारतातील गुन्हेगारांशी संबंधित २००हून अधिक वेबसाइट डोमेनवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. या वेबसाइटवरून विक्री होणाऱ्या औषधांच्या ओव्हरडोसप्रकरणी ही कडक कारवाई करण्यात आली. अमेरिकेतील ड्रग एन्फोर्समेंट ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या कार्यालयाने ऑपरेशन मेल्टडाऊन ही कारवाई करून चारजणांना अटक केली.

अमेरिकेत सक्रिय भारतातील काही गुन्हेगारांशी संबंधित २०० हून अधिक वेबसाइट डोमेन अमेरिकेने बंद केली. हे लोक अमेरिकेतील सहा प्राणघातक आणि चार कमी घातक ओव्हरडोस प्रकरणांसाठी जबाबदार असल्याचा आरोप आहे. या बेकायदेशीर ऑनलाइन फार्मसींशी संबंधित लोकांची २०२२पासून डीईएच्या रॉकी माउंटन फील्ड विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. हे गुन्हेगार बेकायदेशीर औषधांच्या तस्करीत सहभागी असतात. २७ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण अमेरिकेत डीईएने कठोर कारवाई बनावट औषधांची विक्री, ओव्हरडोसप्रकरणी चारजणांना अटक केली आहे.

२०० हून अधिक फार्मसी वेबसाइट बंद

या संबंधित २०० हून अधिक ऑनलाइन फार्मसी वेबसाइट अमेरिकेने बंद केल्या. वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देणे, बनावट गोळ्यांची विक्री करणे अशी गैरकृत्ये या लोकांनी केली होती. सदर प्रकरणाच्या तपासादरम्यान डीईएने ऑनलाइन फार्मसींद्वारे औषधे खरेदी करणाऱ्या हजारो ग्राहकांची ओळख पटवली. त्यानंतर या तपासासाठी माहिती मागवण्याकरिता डीईएने संबंधित लोकांना २०,००० हून अधिक संदेश पाठविले होते.

मदतीचा 'सेतू' : श्रीलंकेला भारताकडून १० पुलांची मदत

श्रीलंकेत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आलेल्या 'डिटवाह' चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर 'ऑपरेशन सागर बंधू' अंतर्गत भारताकडून श्रीलंकेला मदत म्हणून १० 'बेली ब्रिजेस'ची खेप बुधवारी श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली.

घर भाड्याने दिले तरी घरखरेदीदार 'ग्राहक'च

नवी दिल्ली : घर भाड्याने दिले असले तरी केवळ या कारणास्तव घरखरेदीदाराला 'ग्राहक' मानण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. एखादी व्यक्ती 'ग्राहक' नाही हे सिद्ध करण्यासाठी त्या मालमत्तेची खरेदी निव्वळ नफा कमवण्यासाठी केली असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बिल्डरची असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे घराचा ताबा मिळण्यास विलंब करणाऱ्या व ग्राहकांचे हक्क नाकारणाऱ्या बिल्डरांना न्यायालयाने चपराक लगावली.

विनीत बाहरी यांनी गुरुग्राममधील 'द व्हिलाज' प्रकल्पात २००५ मध्ये सदनिका बुक केली होती. घराचा ताबा २०१५ मध्ये मिळाला. या विलंबाबद्दल त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे दाद मागत भरपाईची मागणी केली. मात्र बाहरी यांनी तो फ्लॅट भाड्याने दिल्याने ते 'ग्राहक' नाही, असा युक्तिवाद बिल्डरने केला.

रूबल नागींमुळे झोपडपट्टीत भिंती शिकवू लागल्या; जागतिक पुरस्काराने सन्मानित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : भारतात शेकडो शिक्षण केंद्रे स्थापन करून आणि झोपडपट्ट्यांच्या भिंतींवर भित्तिचित्रांच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्रांती घडवणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या रूबल नागी यांना यंदाचा प्रतिष्ठित 'जागतिक शिक्षक पुरस्कार' नुकताच प्रदान करण्यात आला. १० लाख डॉलरचा हा पुरस्कार नागी यांनी दुबई येथील एका परिषदेत स्वीकारला.

वर्की फाउंडेशनच्यावतीने 'युनेस्को'च्या सहकार्याने हा पुरस्कार दिला जातो. दुबईत आयोजित भव्य समारंभात विविध देशांचे नेते तसेच धोरणकर्ते यांच्या उपस्थितीत नागी यांना सन्मानित करण्यात आले. २०१५ मध्ये वर्की ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. संस्थेच्यावतीने अनेक शिक्षण संस्था चालवल्या जातात.

नागी आर्ट फाउंडेशन

नागी आर्ट फाउंडेशनच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतात ८००हून अधिक शिक्षण केंद्रे रूबल यांनी स्थापन केली. शाळाबाह्य मुलांना यातून शिक्षण दिले जाते. शिवाय शाळेतील इतर मुलांनाही शिकवले जाते.

भित्तिचित्रांच्या माध्यमातून जागृती

नागी यांनी साक्षरता, विज्ञान, गणित आणि इतिहास यांसारख्या विषयांचे ज्ञान देणारी भित्तिचित्रे तयार करून शिक्षणाचे खूप मोठे कार्य केले आहे. पुरस्कारातून मिळालेल्या रकमेचा वापर त्या मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी एक संस्था उभारण्यासाठी करणार आहेत.

जिद्दी शिक्षकांचा आजवर सन्मान

हा पुरस्कार मिळवणाऱ्यांत केनियाचे, पॅलेस्टिनी प्राथमिक शिक्षक, कॅनडातील शिक्षकांसह सौदी शिक्षक मन्सूर अल-मन्सूर यांचा समावेश आहे. या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ अभ्यासक्रम नव्हे तर, समाजसेवा, अहिंसा आणि गरिबांना मदत करण्याचे शिक्षण मुलांना दिले आहे.

हवाई दलात दाखल होण्यासाठी ५ तेजस लढाऊ विमाने सज्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) जाहीर केले आहे की, ५ तेजस लढाऊ विमाने भारतीय हवाई दलात दाखल होण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने ८३ तेजस विमानांच्या खरेदीसाठी एचएएल सोबत ४८,००० कोटी रुपयांचा करार केला होता.

विमाने सुपूर्द करण्यामध्ये काही विलंब झाला होता, याचे मुख्य कारण जीई एरोस्पेसकडून इंजिन पुरवठ्यामध्ये झालेली दिरंगाई होती. एचएएलच्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली आहे की, ही ५ विमाने करारातील सर्व अटी व तपशिलानुसार तयार आहेत. याशिवाय, आणखी ९ विमाने तयार असून त्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे, जीईकडून इंजिन मिळाल्यानंतर ती देखील डिलिव्हरीसाठी सज्ज केली जातील.

भारत-अमेरिका करारावर १५ मार्चपर्यंत सह्या : गोयल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : भारत-अमेरिकेतील बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर १५ मार्चपर्यंत स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी दिली.

गोयल म्हणाले की, कराराचा पहिला टप्पा जवळपास अंतिम झाला असून, पुढील चार ते पाच दिवसांत दोन्ही देश संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करतील. या निवेदनानंतर टॅरिफ सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. त्यामुळे अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय वस्तू स्वस्त होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल. या बदल्यात, भारतही अमेरिकेतून येणाऱ्या काही ठरावीक वस्तूंवरील कर कमी करणार आहे.

गुंतवणुकीची कोणतीही अट नाही

गोयल म्हणाले की, हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित असून, यात सध्या कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीची अट घालण्यात आलेली नाही. पाच वर्षांत भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची खरेदी करणार असल्याबाबतच्या मुद्द्यावर गोयल म्हणाले की, वेगाने वाढणाऱ्या भारताला ऊर्जा, डेटा सेंटर्स आणि आयसीटी उत्पादनांची मोठी गरज आहे. त्यासाठी ही खरेदी केली जाणार आहे. केवळ विमाने आणि इंजिनांसाठीच १०० अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित असून, पोलाद क्षमता दुप्पट करण्यासाठीही अमेरिकी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे.

मस्ट READ

सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांत थेट अटक नाही : कोर्ट

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये थेट अटक न करता प्रथम नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. नोंग्मेकापम कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अटक ही अपवादात्मक बाब असून, ती केवळ अत्यंत आवश्यक परिस्थितीत आणि लेखी कारणांसहच करता येईल.

सतेन्दर कुमार अँटिल विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत अटक करण्यापूर्वी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ३५(३) अंतर्गत नोटीस देणे बंधनकारक आहे का, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम ३५चा अर्थ लावताना न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण सर्वोच्च असल्याचे अधोरेखित केले. खंडपीठाने स्पष्ट केले, अटक करण्याचा अधिकार असणे व अटक करणे आवश्यक असणे वेगळ्या बाबी आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या सूचना कोणत्या आहेत?

१ अटक ही शेवटची उपाययोजना असावी. अटक करण्यासाठी ठोस व लेखी कारणे आवश्यक. केवळ चौकशीसाठी अटक करता येणार नाही

२ **तपास अटकेशिवाय शक्य आहे का, याचा विचार आवश्यक. न्यायालयांनी अटकेच्या कारणांची काटेकोर तपासणी करावी**

३ नोटीसनंतर अटक फक्त नवीन तथ्य समोर आले तरच व गंभीर परिस्थितीतच अटकेसारखी अपवादात्मक कारवाई करायची असल्यास, त्यासाठी पोलिसांना अत्यंत सबळ कारणे असावी, अशा सूचना केल्या आहेत.

बीएनएनएसमध्ये अटकेची तरतूद

कलम ३५(१)(ब) : सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत अटक केवळ ठरावीक परिस्थितीतच

कलम ३५(३) : अटक करणे आवश्यक नसेल तर नोटीस देणे बंधनकारक

कलम ३५(५) : नोटीसचे पालन केल्यास अटक करता येणार नाही

कलम ३५(६) : नोटीस न पाळल्यासही अटक आपोआप नाही

यापैकी किमान एक कारण असेल तरच अटक करता येईल

- पुढील गुन्हा रोखण्यासाठी
- तपासासाठी अत्यावश्यक असेल तेव्हा
- पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असेल
- साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा धोका असेल
- आरोपी न्यायालयात हजर राहणार नाही, अशी ठोस कारणे अस्तित्वात असतील.

प्रत्येकवेळी अटक बंधनकारक नाही

पोलिसांना अटक करण्याचा अधिकार आहे, पण प्रत्येक वेळी अटक करणे बंधनकारक नाही. अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी स्वतःला विचारले पाहिजे - अटक खरेच गरजेची आहे का? तपास अटकेशिवायही होऊ शकतो.

छत्तीसगडमध्ये १२ नक्षली शरण

बीजापूर : छत्तीसगडमध्ये बीजापूर जिल्ह्यातील ८ महिलांसह १२ जहाल नक्षल्यांनी गुरुवारी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. या सर्वांवर ४६ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. या नक्षल्यांनी शस्त्रसाठा पोलिसांकडे सुपूर्द केला.

शरण आलेले सर्व सदस्य हे नक्षलवाद्यांच्या 'साउथ सब झोनल ब्युरो' संबंधित आहेत. छत्तीसगड पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू केलेल्या 'पुना मार्गेम' या अभियानाला प्रतिसाद देत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर या नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले. यावेळी नक्षल्यांनी एक एके-४७ रायफल, एसएलआर रायफल, २५० जेलेटिनच्या कांड्या, ४०० डेटोनेटर, स्फोटकांनी भरलेला एक ड्रम, कॉर्डेक्स वायरचा गठ्ठा पोलिसांकडे सुपूर्द केला आहे.